चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 03 अक्टूबर–09 अक्टूबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

ग़रीबों का मज़ाक़ मत उड़ाइए

पेज-3

लाशें सड़ती रहीं, लेकिन इंसाफ न मिला

पेज-4

मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा

पेज-6

जैविक खेती और बाज़ार प्रणाली

पेज-7

महाराष्ट्र में

डी वाई पाटिल ग्रुप की हक़ीक़त

शिक्षा का माफिया राज

डॉ. डी वाई पाटिल

शिक्षा माफिया. इस देश को नव उदारवाद का एक उपहार. धंधा ऐसा कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए. और जब भैया हों कोतवाल तो फिर डर कैसा, चाहे जो मर्जी हो, वह कर लो. महाराष्ट्र के शिक्षा जगत में भी सालों से कुछ ऐसा ही हो रहा है. डी वाई पाटिल ग्रुप, एक ऐसा ही नाम है. पेश है, चौथी दुनिया की ख़ास रिपोर्ट.

आलोक मिश्रा

भारतीय संस्कृति में गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है और शिक्षण संस्थानों का महत्व किसी मंदिर से ज़्यादा, लेकिन बाज़ारवाद के दौर में जब शिक्षा के इसी मंदिर को दुकान बनाकर गुरु ख़ुद दुकानदार बन जाए और फिर नैतिकता की बात करे, तो इसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के डी वाई पाटिल ग्रुप और उसके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों का है, जो हज़ारों बच्चों और उनके मां–बाप को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हैं, जबकि सपनों के इन सौदागरों के दामन पर ख़ुद कई दाग़ हैं और यह सब जानना देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद ज़रूरी है. चौथी दुनिया के पास ऐसे कई दस्तावेज़ हैं, जिनसे इन शिक्षण संस्थानों और इन्हें चलाने वालों की असलियत का ख़ुलासा होता है.

महाराष्ट्र की राजनीति और शिक्षा जगत में डी वाई पाटिल का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. राज्य से बाहर भी उनकी शख़्सियत राजनीतिक क्षेत्र में जानी–पहचानी है. उन्हें महाराष्ट्र में शिक्षा महर्षि भी कहा जाता है. वर्तमान में डी वाई पाटिल देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के संवैधानिक मुखिया यानी राज्यपाल के सिंहासन पर विराजमान हैं. उनका पुत्र भी राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य है. इतने ऊंचे पद की शोभा बढ़ाने वाला शख़्स यदि कोई ओछी हरकत करे तो शीघ्र विश्वास नहीं होता है, लेकिन हक़ीक़त यही है कि महाराष्ट्र के इस नामचीन शख़्स ने शिक्षा संस्था के नाम पर ऐसी ओछी हरकत की है कि उन्हें शिक्षा महर्षि कहना शिक्षा जगत का अपमान लगता है. इस मामले से उनके शिक्षा महर्षि होने के बजाय शिक्षा माफिया का रूप उजागर हुआ है, जिसने शिक्षा को व्यवसाय बना डाला है. ऐसे व्यक्ति का किसी संवैधानिक पद पर विराजमान होना उस पद की गरिमा को कलंकित करना है, परंतु इस देश में नेताओं के शब्दकोष में नैतिकता जैसे शब्द के लिए जगह नहीं होती.

दरअसल इन शिक्षा महर्षि और राजनीतिज्ञ महोदय के क्रियाकलापों का भंडाफोड़ कुछ दिनों पहले पुणे में शिक्षा संस्था के नाम पर सुविधाएं हासिल करने के लिए राज्य के शासन–प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के कारण हुआ और इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1991 से. 30 जनवरी, 1991 को धर्मदाय आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) के कार्यालय में डी वाई पाटिल एजुकेशन एकेडमी नाम से एक सार्वजनिक विश्वस्त संस्था का पंजीयन कराया गया. पंजीयन के समय पेश दस्तावेज़ों में बताया गया कि यह संस्था महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में शैक्षणिक संस्थाएं संचालित करती है और समुचित शिक्षा की व्यवस्था करती है. इसके बाद 30 जून, 1992 को महसूल विभाग एवं वन विभाग की सरकारी ज़मीन महाविद्यालयों के लिए बाज़ार भाव से 50 प्रतिशत कम क़ीमत पर देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया. सरकार के इसी निर्णय का फ़ायदा लेने के लिए इस घोटाले को अंजाम देने की योजना उक्त संस्था ने बनाई. संस्था के दस्तावेज़ों की जांच से पता चलता है कि 25 जून, 2002 को डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत किया गया. इसके क़रीब एक साल बाद 11 जून, 2003 को डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 41 लाख 90 हज़ार 191 चौरस फुट ज़मीन गांव मौजे चाहोली बुद्रुक, पुणे में ख़रीदी. इसके बाद 30 अक्टूबर, 2004 को नगर विकास

(शेष पृष्ठ 2 पर)

डी वाई पाटिल के पुत्र विधायक सतेज डी पाटिल उर्फ़ बंटी ने एक फरवरी, 2005 को पत्र लिखकर मांग की कि उनकी संस्था पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है, इस बात को मुख्यमंत्री मान्य करें और ज़मीन ख़रीदी की रकम में छूट दें. इस पर नगर विकास विभाग (नाजकधा) ने अपनी रिपोर्ट में सवाल भी उठाया. फिर भी राजनीतिक दबाव के चलते 23 मई, 2005 को अपर ज़िलाधिकारी शंकर राव सावंत ने शासन से बिना कोई अनुमति लिए उक्त संस्था को सार्वजनिक विश्वस्त संस्था होने की मान्यता देते हुए 13 हेक्टेयर 57 आर ज़मीन को लेकर हुए व्यवहार को नियमित कर दिया.

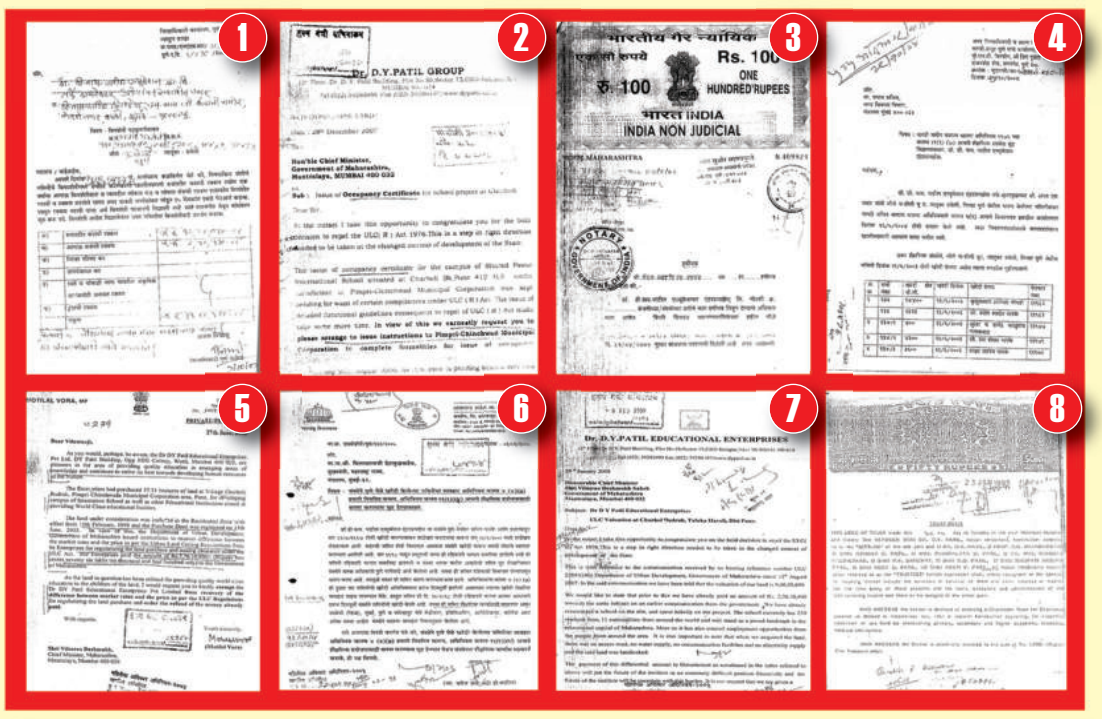

मोती लाल वोरा ने 27 जून, 2006 को लिखे अपने पत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से आग्रह किया कि डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2 करोड़ 76 लाख 10 हज़ार 400 रुपये भरे थे, यह रकम उसे शैक्षणिक संस्था होने के कारण सहूलियत देकर वापस कराएं. इस पत्र से यह भी ख़ुलासा हो जाता है कि कांग्रेस द्वारा अपने नेताओं के भ्रष्ट कारनामों पर पर्दा डालकर कैसे उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. मोती लाल वोरा के पत्र का असर न होता देखकर पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज ने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया.

डी वाई पाटिल कौन हैं

महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम है डी वाई पाटिल. अभी यह त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, राजनीति से इनका पुराना नाता है, लेकिन यह सब एक ओर. जब आप इनका बायोडाटा देखते हैं तो उसमें इनके पेशे के रूप में लिखा है, किसानी और शिक्षाविद्. किसानी का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के शिक्षा जगत में इनका नाम बहुत बड़ा है. नागपुर, पुणे एवं कोल्हापुर से लेकर मुंबई तक फैले कई शिक्षण संस्थान एक ही नाम से चलते हैं. मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, बिजनेस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और भी बहुत कुछ. इन सभी संस्थानों के नाम के पहले सिर्फ़ एक ही नाम जुड़ा हुआ है और वह नाम है डी वाई पाटिल का. आज शिक्षा व्यापार है तो इस व्यापार के सबसे बड़े व्यापारी हैं पाटिल साहब. ज़ाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में थोड़ा–बहुत इधर–उधर का खेल भी करना पड़ता है. सो, इस साम्राज्य को बनाने में भी खेल ख़ूब हुआ है.

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बने एक मंत्री समूह ने सिफ़ारिश की है कि भ्रष्ट बाबुओं की पेंशन में कटौती की जाए.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

विदेश मंत्रालय की परेशानी

विदेश मंत्रालय को कुछ बाबुओं के विदेश प्रेम से काफी परेशानी हो रही है. वे इसलिए कुछ दिनों तक भारत से बाहर काम करना चाहते हैं, क्योंकि विदेश जाने पर उनकी आमदनी में काफी इज़फ़ा हो जाता है. भारत से बाहर जाने पर बाबुओं को 70,000 से लेकर 1.15 लाख रुपये तक विशेष भत्ता दिया जाता है. यही वजह है कि वे भारत से बाहर जाने का कोई भी मौक़ा हाथ से जाने नहीं देना चाहते. इसके लिए नेताओं और बाबुओं के दबाव से विदेश मंत्रालय परेशान है. इस साल मंत्रालय ने हज के समय सऊदी अरब में काम करने के लिए दबाव बनाने वाले 945 बाबुओं की सूची संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के पास भेजी है, जिससे वे इन पर अपने स्तर से कार्रवाई कर सकें. सूत्रों के अनुसार, सचिव संजय सिंह का कहना है कि मंत्रालय पर दबाव बनाना सेवा नियमों के विरुद्ध है. अगर कोई बाबू ऐसा करता है तो वह ग़लत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि जो नेता इन बाबुओं के लिए दबाव बना रहे हैं, उनके लिए किससे कहा जाए.

बाबुओं की चिंता

हिमाचल प्रदेश आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उसने इस बात के लिए रोष प्रकट किया है कि सरकार कई पदों पर ग़ैर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त कर रही है, जिन पर आईएएस अधिकारियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए. एसोसिएशन की चिंता यह है कि अगर इसी तरह पुलिस सेवा या वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती रही तो इससे परेशानी खड़ी हो जाएगी. सात पदों, जिन पर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए था, उन पर ग़ैर आईएएस अधिकारी नियुक्त कर दिए गए. अफवाह है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, जबकि मुख्य सचिव किसी आईएएस अधिकारी को ही बनाया जाता है. साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा श्रीधर पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बना रही है. सामान्य सी बात है कि आईएएस लॉबी को इससे परेशानी तो होगी ही.

अन्ना का असर

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का असर पड़ता दिखाई दे रहा है. जन लोकपाल आने से पहले ही बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त बाबुओं की संपत्ति ज़ब्त करने का काम शुरू कर दिया. केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रही है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बने एक मंत्री समूह ने सिफारिश की है कि भ्रष्ट बाबुओं की पेंशन में कटौती की जाए. अगर कोई बाबू किसी छोटे भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाए तो उसकी पेंशन में 10 फ़ीसदी की कटौती की जाए और यदि उस पर किसी बड़े भ्रष्टाचार का दोष है तो न केवल उसकी पेंशन में 20 फ़ीसदी की कटौती की जाए, बल्कि उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए. केंद्र सरकार जीओएम की इस सिफारिश को लागू करने पर विचार कर रही है. दिल्ली सरकार भी समय पर काम न करने वाले बाबुओं पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

किरण का इंतज़ार समाप्त होगा

वर्ष 1975 बैच की आईएएस अधिकारी किरण ढींगरा को जल्द ही सचिव बनाया जा सकता है. इससे पहले वह आवास एवं शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर रही थीं. कुछ समय से वह नई जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं.

गोविंद मित्रा बने संयुक्त निदेशक

वर्ष 1995 बैच के आईसीएएस अधिकारी गोविंद गोपाल मित्रा को उर्वरक उद्योग समन्वय आयोग (एफआईसीसी) का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. उन्होंने 1991 बैच के आईसीएएस अधिकारी टी एस बसील की जगह ली.

मनीषा बनेंगी निदेशक

वर्ष 1992 बैच की भारतीय डाक सेवा की अधिकारी मनीषा सिन्हा को कपड़ा मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. यह पद पिछले एक साल से खाली था.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जाएंगी दत्त

वर्ष 1978 बैच की आईडीएएस अधिकारी अरुणावा दत्त को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में टैरिफ कमीशन का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है. अभी वह बीएसएफ के वाणिज्य सलाहकार के पद पर काम कर रही हैं.

गोपाल कृष्णन बने सदस्य सचिव

वर्ष 1979 बैच के आईएएस अधिकारी आर गोपाल कृष्णन को नेशनल इनोवेशन काउंसिल का सदस्य सचिव बनाया गया है. इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे.

महाराष्ट्र में शिक्षा का माफिया राज

पृष्ठ एक का शेष

विभाग (नाजकधा) ने डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज द्वारा ख़रीदी गई ज़मीन को धारा 19 (1)(6) के अनुसार सुसंगत बताते हुए संस्था को छूट देने की सिफ़ारिश की. ग़ौरतलब है कि डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है न कि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1949 और इसी तरह सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है.

पिंपरी–चिंचवड महानगर पालिका ने 21 अप्रैल, 2004 को पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज को उक्त ज़मीन पर निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी. साथ ही महानगर पालिका ने 19 जून, 2004 को जोन दाख़िला देते समय यह स्पष्ट किया था कि पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ख़रीदी गई ज़मीन के प्रत्येक सर्वे नंबर में कम से कम 18 से 30 मीटर रास्ते की व्यवस्था का उल्लेख है. इसके बाद अपर ज़िलाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, पुणे नागरी समूह ने 25 अक्टूबर को नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर बताया कि मूल कृषक परिवार के नागरी ज़मीन नीति क़ानून अस्तित्व में आने के बाद धारा 6 (1) के अनुसार दो विवरणपत्र दिए गए हैं, जिनमें केस नंबर 1120–पी एवं 1121–पी का उल्लेख किया गया है, मगर इनमें ज़मीन के मूल मालिक म्हस्के, चौधरी एवं गायकवाड़ द्वारा यह नहीं बताया गया है

कि उक्त जगह खेती की है. मूल मालिक म्हस्के, चौधरी एवं गायकवाड़ से पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने ज़मीन ख़रीदी और धारा 6 (1) के अनुसार विवरण पेश किया है. इस पर भी पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज एक शैक्षणिक व प्राइवेट संस्था है, महानगर पालिका ने लेआउट को देखकर मंजूरी दी है. इसमें नाजकधा 19 (1)(6) के प्रावधानों के अनुसार संस्था ने छूट देने का अनुरोध शासन से किया. इस पर नगर विकास विभाग ने लिखित में दिया कि हक़ीक़त में डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है. ऐसे में उसके धर्मदाय आयुक्त के पास पंजीकृत होने का सवाल ही नहीं उठता है. यह भी बताया गया है कि डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का उक्त तारीख़ यानी 22 जुलाई, 1997 तक कोई अस्तित्व नहीं था, वह 25 जून, 2002 को अस्तित्व में आई. इसके बावजूद 5 जनवरी, 2005 को पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि उक्त ज़मीन 22 जुलाई, 1997 को ख़रीदी गई है, जिसका भुगतान चेक द्वारा किया गया है और 11 मार्च, 2000 को उसके नाम पर ज़मीन की गई है. इसलिए कोई दंड न लगाते हुए मदद की जाए. इससे साफ़ पता चलता है कि पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज झूठ पर झूठ बोलकर शासन से लाभ उठाने का लगातार प्रयास करती रही है.

बताया जाता है कि इसके बाद भी इसकी गतिविधियों पर विराम नहीं लगा. डी वाई पाटिल के पुत्र विधायक सतेज डी पाटिल उर्फ़ बंटी ने एक फरवरी, 2005 को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी संस्था पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन ख़रीदी की रकम में छूट दें. इस पर नगर विकास विभाग (नाजकधा) ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया कि डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के एक शैक्षणिक संस्था होने के बावजूद, नाजकधा अधिनियम के प्रावधान के तहत छूट के लिए संस्था द्वारा शुरुआत में उल्लेख किए गए 1997 के व्यवहार को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत सही ठहराया जा सकता है? फिर भी, राजनीतिक दबाव के चलते 23 मई, 2005 को अपर ज़िलाधिकारी शंकर राव सावंत ने शासन से बिना कोई अनुमति लिए उक्त संस्था को सार्वजनिक विश्वस्त संस्था होने की मान्यता देते हुए 13 हेक्टेयर 57 आर ज़मीन को लेकर हुए व्यवहार को नियमित कर दिया. वहीं 23 सितंबर, 2005 को पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज द्वारा 23 हेक्टेयर 74 आर ज़मीन को लेकर किए गए व्यवहार को नाजकधा के प्रावधानों के तहत अनुचित ठहराया गया.

इस संबंध में सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र एल बरहाते ने बताया कि डी वाई पाटिल एवं उनके विधायक पुत्र सतेज डी पाटिल की जोड़ी ने डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जो किया, उसे जायज़ ठहराने के लिए उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए. अपनी राजनीतिक ताक़त का भी भरपूर उपयोग किया. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा से मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखवाया. मोती लाल वोरा ने 27 जून, 2006 को लिखे अपने पत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से आग्रह किया कि डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 2 करोड़ 76 लाख 10 हज़ार 400 रुपये भरे थे, यह रकम उसे शैक्षणिक संस्था होने के कारण सहूलियत देकर वापस कराएं. इस पत्र से यह भी ख़ुलासा हो जाता है कि कांग्रेस द्वारा अपने नेताओं के भ्रष्ट कारनामों पर पर्दा डालकर कैसे उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. मोती लाल वोरा के पत्र का असर न होता देखकर पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज ने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया. संस्था के प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को पुन: 13 अक्टूबर, 2006 को पत्र लिखकर कहा कि उसके द्वारा चाहोली बुद्रुक गांव में ख़रीदी गई ज़मीन के पास से कोई रास्ता नहीं है. साथ ही उसने पुराने मामले का हवाला देते हुए छूट देने और 2 करोड़ 75 लाख रुपये वापस करने की मांग की. जबकि पिंपरी–चिंचवड महानगर पालिका ने अपने जोन के दस्तावेज़ों में स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक सर्वे नंबर में 18 से 30 मीटर रास्ते के लिए ज़मीन आरक्षित है.

नगर रचना मूल्यांकन महाराष्ट्र राज्य के सह संचालक ने 23 अप्रैल, 2007 को अपनी रिपोर्ट में ज़मीन की क़ीमत 9,06,55,600 रुपये बताई है. वहीं नगर विकास विभाग (नाजकधा) ने अपनी रिपोर्ट में ज़मीन की क़ीमत 14,45,08,094 रुपये बताई है. इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि ज़मीन का मुद्रांक शुल्क किस क़ीमत पर तय किया जाए, नगर रचना विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन पर या नगर विकास विभाग (नाजकधा) द्वारा आंकी गई क़ीमत पर. लेकिन ज़मीन की वास्तव में बाज़ार क़ीमत क्या थी, इसका आकलन नहीं किया गया. पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज लगातार सरकार से म्हाडा, सिडको एवं एमआईडीसी की तरह ख़ुद को सहूलियत और छूट देने के साथ पैसा वापस करने का आग्रह करती रही और वह भी शासन–प्रशासन को झूठी जानकारी देकर. इस पूरे गोलमाल में जिन अधिकारियों ने सहयोग किया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

सतेज डी पाटिल

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 30
दिल्ली, 03 अक्टूबर–09 अक्टूबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यह भी अजीब बात है कि मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलुवालिया की जोड़ी हर चीज के लिए विश्व बैंक का मुंह देखती है, उसके हर आदेश का पालन करती है, लेकिन उसके द्वारा बताए गए फॉर्मूले को नहीं मानती.

महंगाई की मार झेल रहे

ग़रीबों का मज़ाक़ मत उड़ाइए

अगर यह सिर्फ़ आंकड़ों का खेल है तो समस्या उतनी चिंताजनक नहीं है, लेकिन इस हलफ़नामे से योजना आयोग कोई संकेत देना चाहता है तो यह ख़तरनाक है. लगता है कि उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के नाम पर सरकार ग़रीब विरोधी फ़ैसले लेने वाली है. सरकार देश के ग़रीबों को ग़रीबी रेखा से बाहर करके उन्हें मिलने वाले फ़ायदे से अलग करना चाहती है. सामाजिक विकास के क्षेत्र में लागू कई सरकारी योजनाओं को बंद किया जा सकता है. सब्सिडी में कटौती का ऐलान हो सकता है.

मनीष कुमार

32 रुपये में कैसे ज़िंदा रहा जा सकता है, यह कला योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया को पूरे देश को सिखानी चाहिए. मोंटेक सिंह अहलुवालिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोस्त हैं. योजना आयोग की भूमिका देश के विकास में बहुत ही अहम है. इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं, जहां की सरकार को मालूम नहीं है कि देश में कितने ग़रीब हैं. क्या हमने देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में दे दी है, जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है. जिन्हें यह तक पता नहीं कि बाज़ार में चावल–दाल के भाव क्या हैं. योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दिया, जिसमें यह बताया गया कि शहरों में रहने वाले अगर 32 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और जिन ग्रामीणों की 26 रुपये रोज़ाना की आय है, वे ग़रीब नहीं हैं. एक आंकड़ा और है, जिसे देश की जनता को जानना ज़रूरी है. मोंटेक सिंह अहलुवालिया जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उन पर सरकार रोज़ाना औसतन 11,354 रुपये ख़र्च करती है. जनता और शासक में यही फ़र्क़ होता है. अब सवाल उठता है कि योजना आयोग ने ऐसा हलफ़नामा क्यों दिया.

2005 में संयुक्त राष्ट्र की मिलिनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आई, जिसमें दुनिया भर में विकास का विश्लेषण किया गया था. इस रिपोर्ट ने यह बताया कि अगले चार सालों में यानी 2009 में 320 मिलियन लोग भारत और चीन में ग़रीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे. इस रिपोर्ट के मुताबिक़, 2015 में भारत में ग़रीबों की संख्या महज़ 22 फीसदी रह जाएगी. मतलब यह कि भारत दुनिया का ऐसा अकेला देश होगा, जो 1990 की 51 फ़ीसदी ग़रीबी दर को घटाकर 2015 में 22 फ़ीसदी करने में सफल रहेगा. इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि भारत इस लक्ष्य की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट का क्या मतलब है. संयुक्त राष्ट्र की सारी एजेंसियां आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देती हैं. इससे यूरोप और अमेरिका के देशों को फ़ायदा होता है. दुनिया के कई देश इन नीतियों की वजह से संकट में आ चुके हैं. मनमोहन सिंह ने इन्हीं नीतियों को भारत में लागू किया. यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत में चल रही आर्थिक नीति सही है. इससे भारत का विकास हो रहा है, ग़रीबों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है. यही वजह है कि इस रिपोर्ट में यह मान लिया गया कि 2015 तक देश में सिर्फ़ 22 फ़ीसदी ग़रीब रह जाएंगे. हक़ीक़त बिल्कुल विपरीत है.

समझने वाली बात यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जब भी किसी आर्थिक नीति का मूल्यांकन होता है तो पहला सवाल यही उठता है कि इस नीति से ग़रीबों को कितना फ़ायदा पहुंचा. जब यह रिपोर्ट आई, तब के वक़्त में और आज के वक़्त में काफ़ी फ़र्क़ आ गया है. महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है. ग़रीब तो ग़रीब, इस दौर में महंगाई ने अमीरों को भी परेशान कर दिया है. दुनिया की नज़र में भारत में निजीकरण और आर्थिक सुधारों की वजह से फ़ायदा हुआ है. योजना आयोग और सरकार इस भ्रम को क़ायम रखना चाहते हैं. विकास के इस भ्रम को बचाए रखने के लिए आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को सच साबित करने के लिए योजना आयोग ने ग़रीबी रेखा का नया मापदंड तैयार किया है. जबकि इसी हलफ़नामे में यह भी कहा गया कि सच्चाई यह है कि मनमोहन सिंह के उदारीकरण की वजह से ग़रीब पहले से ज़्यादा ग़रीब हो गए हैं. अब मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलुवालिया यानी सरकार और योजना आयोग के सामने एक समस्या है कि आंकड़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे विकास के भ्रम को आंकड़ों से तर्कसंगत किया जाए. इस रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में मोंटेक सिंह अहलुवालिया का बयान देखा जाए तो यह साफ़ हो जाता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बयान क्यों दिए. योजना आयोग ने ग़रीब की परिभाषा बदल दी. शहरों में 32 रुपये और गांवों में 26 रुपये प्रतिदिन पर जीने वालों को ग़रीबी रेखा से बाहर कर दिया. सरकारी आंकड़ों में ग़रीब अब ग़रीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे. सरकार इस भ्रम को जीवित रखने में कामयाब हो जाएगी कि आर्थिक नीति सही रास्ते पर चल रही है.

समस्या यह है कि भारत में ग़रीबी मापने का कोई एक तरीका नहीं है. सरकार की हर शाखा अपने हिसाब से ग़रीबी मापती है, अपने हिसाब से आंकड़े बनाती है, बिगाड़ती है और सहूलियत के मुताबिक़ इसे जारी करती है. वैसे ग़रीबी रेखा की कहानी भारत में चालीस साल पहले शुरू हुई. सरकारी ग़रीबी रेखा सिर्फ़ एक मापदंड पर आधारित है कि ज़िंदा रहने के लिए जितना खाने (कैलोरी) की ज़रूरत है, उसकी क़ीमत क्या है. बताया तो यह जाता है कि योजना आयोग ने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति देकर यह मान लिया था कि देश में 37 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. देश में ग़रीबों की संख्या कितनी है, इस पर एक और रिपोर्ट है, जिसकी मान्यता तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट से किसी भी मायने में कम नहीं है. यह रिपोर्ट अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के नाम से मशहूर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक़, देश के 77 फ़ीसदी लोग ग़रीब हैं. वहीं एन सी सक्सेना रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में 50 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे रहते हैं. ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलेपमेंट इनिशिएटिव के रिसर्च के मुताबिक़, भारत में 645 मिलियन लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. इनमें से 421 मिलियन लोग बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं.

यह भी अजीब बात है कि मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलुवालिया की जोड़ी हर चीज के लिए विश्व बैंक का मुंह देखती है, उसके हर आदेश का पालन करती है, लेकिन उसके द्वारा बताए गए फॉर्मूले को नहीं मानती. विश्व बैंक ने पूरी दुनिया के लिए एक ग़रीबी रेखा बनाई है. इसे इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा कहते हैं. इसके मुताबिक़, ग़रीब उसे माना जाता है, जिसकी आय 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम है. अगर इसे आधार मानें तो भारत में प्रतिदिन 61 रुपये से कम आय वाला व्यक्ति ग़रीब है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक़, भारत के 41.6 फ़ीसदी लोग इस रेखा के नीचे हैं. अक्टूबर 2007 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई. इसमें एक बात चौंकाने वाली थी, जिसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक़, देश में क़रीब 80 फ़ीसदी लोग ऐसे हैं, जिनकी आय 2 डॉलर से कम है. इसका मतलब यह है कि हमारे देश की हालत अफ्रीका के कई देशों से भी खराब है. वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट से एक बात यह साबित होती है कि पिछले 20 सालों से चल रही आर्थिक नीतियों का फ़ायदा ग़रीबों को नहीं हुआ है. निजीकरण और उदारीकरण का फ़ायदा चंद शहरों और उद्योगपतियों को हुआ है. मनमोहन सिंह की सरकार और योजना आयोग ने विकास के भ्रम को बनाए रखने के लिए देश के ग़रीबों का मज़ाक़ उड़ाया है.

समझने वाली बात यह है कि ग़रीबी रेखा के जितने भी मापदंड हैं, वे सिर्फ़ लोगों के खाने–पीने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं. इसके अलावा आम इंसान के जीवन की अन्य ज़रूरतों का हिसाब उनमें शामिल नहीं है. जैसे कि मेडिकल, शिक्षा, मनोरंजन, पर्व–त्योहार पर होने वाले ख़र्च को सम्मिलित नहीं किया जाता है. कहने का मतलब यह है कि ग़रीबों को इन सबसे वंचित रखकर ही उनकी गिनती होती है. अगर इन सब ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ग़रीबी रेखा के मापदंड तैयार किए जाएं तो भारत में ग़रीबों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी. लेकिन सरकारी तंत्र आंकड़ों में इतना उलझ गया है कि उसे ग़रीबों की खुशियों से क्या मतलब? किसी ग़रीब के घर ईद और दीवाली की खुशियां न हों, उससे देश चलाने वालों को क्या फ़र्क़ पड़ता है? यही वजह है कि भारत में जब भी ग़रीबों की बात होती है तो सारा मामला ग़रीबी रेखा और आंकड़ों के जाल में फंस जाता है. ग़रीबी मापने का मापदंड क्या हो, एक डॉलर हो या दो डॉलर हो, सौ रुपये हो या फिर दो सौ रुपये, यह महत्वपूर्ण नहीं है. पांच हज़ार रुपये मासिक दिल्ली, मुंबई या बंगलुरू जैसे शहरों के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इतने में तो सिर्फ़ खाना ही खाया जा सकता है. जिसके बच्चे पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे, जो अपने बूढ़े मां–बाप का इलाज नहीं करा सकता, जो अपनी पत्नी को ईद और दीवाली पर कोई उपहार नहीं दे सकता, जिसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, वह ग़रीब ही माना जाएगा. ग़रीबी का रिश्ता ज़िंदगी की गुणवत्ता से है. मतलब यह कि लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं. ग़रीबी का रिश्ता खुशहाली से है. जो पैसों के अभाव के चलते खुशियां नहीं मना सकता, वही ग़रीब है. अब यह बात योजना आयोग के विद्वान अर्थशास्त्री को भला कौन समझा सकता है.

manish@chauthiduniya.com

ध्यान दीजिए: पॉलिसीधारकों तथा लाभार्थियों

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

केन्द्रीय कार्यालय, ''योगक्षेम'', जीवन बीमा मार्ग,
पो. ऑ. बॉक्स नं. 19953, मुंबई–400 021
फ़ोन: 22028227, फैक्स: 22825829
ईमेल: co_crm@licindia.com

प्रिय पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों,

पॉलिसी की रकम को और अधिक सुरक्षा तथा प्राईवेसी के साथ अधिक शीघ्रता से जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 01.10.2011 से सभी भुगतानों (विद्यमानता हितलाभ, परिपक्वता, ऋण, अभ्यर्पण, पेन्शन तथा समूह योजनाओं का भुगतान आदि) को सीधे पॉलिसीधारक/लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह भारत सरकार के पारदर्शिता अभियान के अनुरूप भी है।

हमारे सभी अमूल्यवान पॉलिसीधारकों/मास्टर पॉलिसीधारकों/वार्षिकी–ग्राहियों/दावेदारों से अनुरोध है कि निर्धारित प्राधिकार प्रपत्र में जल्द से जल्द बैंक अकाउन्ट विवरण उपलब्ध कराएं, जिसे हमारी वेबसाइट www.licindia.in से डाउनलोड अथवा हमारे किसी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

किसी अन्य सहयोग के लिए, कृपया किसी शाखा/सेटेलाइट कार्यालय में शाखा प्रभारी, मंडल कार्यालय में प्रबंधक (सीआरएम), क्षेत्रीय कार्यालय में प्रादेशिक प्रबंधक (सीआरएम) या केन्द्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक (सीआरएम) से सम्पर्क करें। पेन्शन तथा समूह योजनाओं के मामले में कृपया इकाई प्रभारी (पें व स यो), क्षेत्रीय कार्यालय में प्रादेशिक प्रबंधक (पें व स यो) या केन्द्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक (पें व स यो) से सम्पर्क करें।

प्रबंध निदेशक

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA www.licindia.in

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है

पीयूसीएल जांच दल ने इलाक़े के सभी गांवों का दौरा किया और पीड़ितों, उनके परिवारीजनों, ग्रामीणों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की.

गोपालगढ़ हत्याकांड

लाशें सड़ती रहीं, लेकिन इंसाफ़ न मिला

सरकार से चूक हुई है

शशि शेखर

पुलिस का ख़ौफ़ अगर देखना हो तो गोपालगढ़ गांव में देखा जा सकता है. यहां सन्नाटा पसरा है. गांव के लोग बताते हैं कि पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की जान गई. बताया गया कि तीन लाशों को पुलिस ने जला दिया और बाकी लाशें कई दिनों तक पड़ी रहीं. शायद यह पहली ऐसी घटना है, जहां मुसलमानों ने लाशों को दफ़नाने से इंकार कर दिया. वे गुनाहगार पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. गोपालगढ़ राजस्थान के भरतपुर ज़िले का गांव है. राजस्थान का यह इलाका उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से सटा हुआ है. राजनीतिक दृष्टि से यह मामला काफी संवेदनशील है. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. मुसलमान डरे हुए हैं. ख़तरा इस बात का है कि अगर इस मामले का असर आगरा और उसके आसपास के इलाकों पर हुआ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है. सवाल यह है कि इस मामले में सरकार और प्रशासन से कहां चूक हुई.

सही मायने में सांप्रदायिक दंगे से ज़्यादा यह पुलिस की बर्बरता की कहानी है. गोपालगढ़ में जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद था. एक गुट इसे क़ब्रिस्तान की ज़मीन बता रहा था तो दूसरा गुट इसे तलाब बता रहा था. मामले ने तूल पकड़ा. पुलिस आई, उसने मस्जिद को घेरा और गोलियां चलाने लगी. बताया यह जाता है कि पुलिस ने गोली चलाने का आदेश अधिकारियों से ज़बरदस्ती लिया. पुलिस ने तीन लोगों को जला दिया. अल्पसंख्यकों के दिल में डर पैदा हो गया. प्रशासन के मुताबिक, कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर शुरू हुए इस विवाद में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद फायरिंग हुई, कई जगह आगजनी की भी घटनाएं हुईं. जिलाधिकारी ने पहले सिर्फ़ यह माना कि पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि 13 लोग घायल हुए. लेकिन इस मामले का एक और पहलू भी है, जैसे जमीन को लेकर शुरू हुई झड़प के बाद वहां पुलिस पहुंची. इसके बाद फायरिंग हुई और फिर ख़बर आई कि 8 मुसलमानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. ख़बर दबाने की भी कोशिश की गई.

घटना के बाद कई इलाक़ों में कर्फ्यू के साथ धारा 144 लगा दी गई. पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुईं. स्थानीय पुलिस का मानना है कि इस घटना के लिए मुसलमान ही कसूरवार हैं, ऐसा उसके द्वारा दर्ज एफआईआर भी कहती है. एक एफआईआर एसएचओ गोपालगढ़ ने दर्ज कराई है, जिसमें मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल रशीद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. सरकार से लेकर पुलिस तक मृतकों की संख्या और फायरिंग की सही वजह बता पाने में असफल रही. भले ही गोपालगढ़ में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण रही. अफवाहों का भी बाज़ार गर्म रहा. घटना के बाद गोपालगढ़ के कई परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकाने के लिए पलायन कर गए. मामले की जांच के लिए पीयूसीएल के एक दल ने बीते 16–17 सितंबर को घटनास्थल का दौरा भी किया. पीयूसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक़, इस दंगे में आठ लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हुए हैं.

ग़ौरतलब है कि मारे गए सभी लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं. 23 घायलों में भी 19 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बंदूक से निकली गोली का निशाना ज़्यादातर या सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही क्यों बने. यदि स्थिति तनावपूर्ण थी तो सीधे गोली क्यों चलाई गई, रबर की गोली का इस्तेमाल या लाठीचार्ज क्यों नहीं किया गया? ज़ाहिर है, इस पूरे मामले में पुलिस-प्रशासन ने न दूरदर्शिता दिखाई और न तर्कसंगत निर्णय लिए. फायरिंग का निर्णय तब लिया जाता है, जब हालात बेक़ाबू हो जाते हैं. सवाल यह उठता है कि जब पुलिस फायरिंग से पहले एक भी मौत नहीं हुई थी, तब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाईं?

घटना के बाद कई इलाक़ों में कर्फ्यू के साथ धारा 144 लगा दी गई. पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुईं. स्थानीय पुलिस का मानना है कि इस घटना के लिए मुसलमान ही कसूरवार हैं, ऐसा उसके द्वारा दर्ज एफआईआर भी कहती है. एक एफआईआर एसएचओ गोपालगढ़ ने दर्ज कराई है, जिसमें मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल रशीद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

पीयूसीएल जांच दल ने इलाके के सभी गांवों का दौरा किया और पीड़ितों, उनके परिवारीजनों, ग्रामीणों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की. पीयूसीएल की जांच रिपोर्ट बताती है कि अगर पुलिस ने फायरिंग के निर्णय को सही बताया है तो आख़िर मरने वाले सारे लोग एक ही समुदाय के क्यों हैं? पुलिस फायरिंग में 219 राउंड गोलियां चलीं. जिलाधिकारी ने किस परिस्थिति और दबाव में फायरिंग के आदेश दिए, इस बात की जांच होनी चाहिए. पीयूसीएल की रिपोर्ट कहती है कि दीवारों पर गोलियों के निशान थे. रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जो जगह पुलिस के नियंत्रण में थी, वहां दूसरे लोग आकर कैसे हमला कर सकते हैं या मस्जिद में घुस सकते हैं. ज़ाहिर है, इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही.

अगर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई होती तो इन बेगुनाहों की जान नहीं जाती. राज्य सरकार की गलती यह है कि उसने इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में देरी की. जिन पुलिस वालों ने अधिकारियों से ज़बरदस्ती गोली चलाने का आदेश लिया, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. कई दिनों तक लाशें पड़ी रहीं, धरना चलता रहा, फिर भी राज्य सरकार की तरफ से देरी क्यों हुई. हैरानी की बात यह है कि इस घटना पर सोनिया गांधी ने नाराज़गी जताई, फिर भी गुनाहगार पुलिस वालों पर कार्रवाई में ढील बरती गई.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मामले की सच्चाई क्या है

वसीम राशिद

यह भरतपुर का गोपालगढ़ है, जिसकी मस्जिद की दीवार पर गोलियों के निशान हैं. पूरी मस्जिद इस समय छावनी बनी हुई है. पुलिसकर्मी जूता पहने घूम रहे हैं. मस्जिद के मेहराबों और इमाम के नमाज़ पढ़ाने की जगह पर गोलियों के निशान हैं. गोपालगढ़ के मदरसे में जली हुई हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं. जिस मस्जिद के पास गोलियां चलाई गईं, उसकी बाहरी दीवारों और अंदर की दीवार पर भी गोलियों के निशान हैं. यूं तो सभी अख़बारों ने विशेषत: उर्दू अख़बारों ने इस कांड पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि असल विवाद क्यों हुआ, किस कारण हुआ? उसका आंखों देखा हाल बताने के लिए सही लोग नहीं मिल पाए. इससे भी अधिक अफ़सोस की बात यह है कि अंग्रेज़ी और हिंदी मीडिया ने इस ख़बर को पहले दिन तो कोई महत्व नहीं दिया. दूसरे दिन ख़बर आई तो किसी ने पहले पन्ने पर 6 लाइनें दीं, किसी ने दूसरे पन्ने पर और किसी ने तो इसे प्रकाशित करना ही उचित नहीं समझा. मानों 13 लोगों का मारा जाना कोई विशेष बात नहीं थी और जिन अख़बारों ने ख़बर दी, उन्होंने विवाद के बाद तीन दिनों तक कोई ख़बर दोबारा प्रकाशित ही नहीं की.

यह वही मीडिया है, जो साधारण से साधारण बातों पर कैमरा लेकर पहुंच जाता है. यहां तक कि वे अख़बार, जिन्होंने ख़ुद जाकर मौक़े का दौरा किया, उन्हें भी सही रिपोर्ट नहीं मिल सकी. इसकी वजह शायद सही लोगों तक पहुंच न होना रही होगी. विवाद के 10 दिनों बाद तक सही रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई. पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़) जो एक एनजीओ है और जिसे 1976 में जय प्रकाश नारायण ने केवल इस उद्देश्य से स्थापित किया था कि एक ऐसा संगठन हो, जो राजनीतिक दृष्टि से आज़ाद हो और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक-दूसरे के क़रीब आ सकें और एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र होकर सिविल लिबर्टीज़ और मानवाधिकार के लिए काम कर सकें. इस संगठन की रिपोर्ट प्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाता. इस संगठन ने पहली बार भरतपुर कांड की सही रिपोर्ट पेश की और उसके बाद बाक़ी अख़बारों ने इसकी रिपोर्ट को सामने रखकर अपनी-अपनी रिपोर्टिंग की.

गोपालगढ़ क़स्बे में क़ब्रिस्तान की एक ज़मीन है. इस ज़मीन पर विवाद चल रहा था. कुछ लोगों को कहना है कि यह ज़मीन उनकी है और इसी को लेकर वे बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि ज़मीन ख़ाली की जाए, लेकिन जब इसके असल क़ाग़ज़ पटवारी और तहसीलदार से निकलवाए गए तो यह साबित हो गया कि विवादित ज़मीन क़ब्रिस्तान है. उसी दिन रात को गोपालगढ़ के इमाम को कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर मारा. उन्होंने रिपोर्ट लिखवानी चाही, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी. पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों को बुलाकर ही रिपोर्ट लिखी जा सकेगी. फिर दोनों पक्षों के लोगों को थाने में बुलवाया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक ज़ाहिदा बेगम और पड़ोसी क़स्बे के भाजपा विधायक भी आए, लेकिन इससे पहले कि इस मसले का हल निकाला जाता, इलाके में हंगामा मच गया. अफ़वाहें फैलने लगीं. इस बीच एक गुट थाने पर चढ़कर आ गया कि हम पर गोलियां चल रही हैं. पुलिस ने एसपी से ज़बरन गोलियां चलाने की अनुमति ली. पुलिस मस्जिद में घुसी और वहां मौजूद तीन लोगों को गोली मारकर बाहर खींचा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पास में ही एक ईदगाह है, जिसके पास कुआं है, उसमें तीनों लाशें फेंक दीं. कुएं में से वे तीनों लाशें अगले दिन बरामद हुईं. ज़ाहिदा बेगम ने पुलिस स्टेशन के एक छोटे से कमरे में पनाह ली और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को बचाया. जमशेद साहब का कहना है कि 6 बजे तक गोलियां चलती रहीं. विधायक ज़ाहिदा बेगम का कहना है कि उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से पुलिस को निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते देखा है. ज़ाहिदा का कहना है कि यह पुलिस और आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम था. ज़ाहिदा के मुताबिक़, ज़िलाधिकारी और एसपी निष्पक्ष थे, लेकिन एडिशनल एसपी ओ पी मेघवाल एवं इंस्पेक्टर बृजेश मीणा आदि सांप्रदायिक मानसिकता के थे. जमशेद साहब के अनुसार, 5 लाशों को दफ़ना दिया गया, चार का मेडिकल हो गया, कुल 6 लाशें दफ़नाने के लिए बचीं, लेकिन जिन लाशों को दफ़नाया नहीं गया, उन पर राजनीति का घिनौना खेल शुरू हो गया. विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने लाशों को उस समय तक न दफ़नाने का फ़ैसला किया, जब तक वह मरने वालों के परिवारीजनों को मुआवज़ा न दिलवा दें. यह लालच देकर कि मैं 25 लाख दिलवाऊंगा, मैं 40 लाख दिलवाऊंगा, लाशों पर राजनीति होने लगी. जमशेद साहब से जब हमने यह सवाल किया कि अंग्रेज़ी और हिंदी मीडिया आया या नहीं तो उनका जवाब था कि शुरू में कई दिनों तक उर्दू अख़बारों को छोड़कर किसी दूसरे अख़बार का रिपोर्टर नज़र भी नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद थोड़े-बहुत मीडिया के लोग आए. इन सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस विवाद की सही ख़बर देने की ज़हमत न तो प्रिंट मीडिया ने उठाई और न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने. इंडियन एक्सप्रेस ने 10 दिनों बाद पीयूसीएल की रिपोर्ट पर आधारित अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन हिंदी अख़बारों ने तो यह ज़हमत भी नहीं उठाई.

क़लम में बहुत ताक़त है. पत्रकार की, संपादक की कलम अगर बहक जाए तो समाज टूट सकता है, अमन-चैन को ख़तरा पैदा हो सकता है. इसीलिए हम सब पत्रकारों को यह ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए. भारत में कई बार इस तरह की घटनाएं हुईं, लेकिन मुस्लिम इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जबकि लाशें इतने दिनों तक पड़ी रही हों. समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है और मुसलमानों की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रही. उसे यह भी ख्याल नहीं कि यह आग उत्तर प्रदेश तक फैल सकती है. जिन पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, हत्या का मुकदमा लगाकर दफ़ा 302 के तहत जेल में बंद कर देना चाहिए और अदालती फ़ैसले का रंग देखना चाहिए, तभी इंसाफ़ के दोनों पलड़े बराबर दिखाई देंगे.

editorurdu@chauthiduniya.com

आज ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर विश्व भर के पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिक चिंता में डूबे हुए हैं. उन्हें भी मालूम है कि ऐसा हरे जंगलों के लगातार घटने के कारण हो रहा है.

इक और जहां मुमकिन है

रजनीश

कैमूर क्षेत्र के जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चंदौली के दलितों-आदिवासियों ने पिछले 8 वर्षों में जंगल की खाली और बंजर पड़ी क़रीब 30,000 एकड़ ज़मीन पर दोबारा अपना दख़ल क़ायम करते हुए 25 से ज़्यादा नए गांव बसाकर एक नया इतिहास रचने का काम कर दिया है. दरमा, हर्रा बिलरूआ, झिरगाडंडी, तलैयाबीर, कोदवनिया, मगरदाह, जोरूखाड़, बोम, परासपानी, हरना कछार, केवटन, पटवध, दमनभरी, बसधाटोटा, पतदड़ी गुरमुरा, चरगढ़ा भुलई एवं औरहउआ आदि ग्रामीण क्षेत्रों में बसाए गए इन गांवों में आदिवासियों एवं अन्य वनाश्रितों द्वारा स्वयं सामूहिक सहयोग से बनाई गई सड़कें और खोदे गए कुएं सरकार द्वारा करोड़ों रुपये ख़र्च करके चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों को चुनौती दे रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि क्षेत्रफल के मामले में कैमूर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन यहां हरे-भरे जंगल कुल वन भूमि के 50 प्रतिशत के बराबर भी नहीं हैं. यहां के पुराने लोग बताते हैं कि एक समय वह था, जब एक पेड़ को काटना होता था तो उसे नीचे गिराने के लिए आसपास के चार-पांच पेड़ों को भी गिराना पड़ता था. समय के साथ-साथ यहां फैले वन माफ़ियाओं के जाल और वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से होने वाली अवैध कटान के चलते आज यहां हरियाली बीते समय की बात हो चली है. आज़ादी से पहले यानी अंग्रेजी हुकूमत रहने तक यहां का मूल निवासी दलित आदिवासी इन ज़मीनों पर अपने आधे-अधूरे हकूक के साथ खेती करके और जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज के सहारे गुजर-बसर करता चला आ रहा था. आज़ादी का फल भले ही देश के रजवाड़ों, सरमाएदारों और सत्ता पर क़ाबिज होने वाले राजनेताओं के लिए मीठापन लिए रहा हो, लेकिन दलित आदिवासियों एवं वनों पर आश्रित समुदायों के लिए वह कसैला ही साबित हुआ. आज़ादी के बाद ख़ास तौर पर देश का संविधान बनने के बाद जंगल से आदिवासियों एवं अन्य वनाश्रित समुदायों की बेतहाशा बेदखली की शुरुआत जो आज़ाद हिंदुस्तान की सरकारों ने की, वह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है. अपने पुरखों की ज़मीनों पर रहने वाले लोग-समुदाय सरकार और वन विभाग की भाषा में अतिक्रमणकारी हो गए हैं. काग़ज़ों पर वन क्षेत्र बढ़ाने की अंधी दौड़ में सरकारों ने यहां के लोगों की कृषि योग्य, निवास और सामुदायिक इस्तेमाल की लाखों हेक्टेयर ज़मीन आरक्षित जंगल एवं सुरक्षित जंगल आदि में परिवर्तित करके वन विभाग को प्रबंधन के लिए सौंप दी है. एक तरफ़ इस प्रक्रिया ने जहां वन विभाग को सबसे बड़े जमींदार के रूप में स्थापित कर दिया, वहीं दूसरी ओर इन ज़मीनों के असली हक़दार यहां के दलित आदिवासी और अन्य वनाश्रित समुदाय अतिक्रमणकारी घोषित होते चले गए.

वन विभाग को ज़मीनें हस्तांतरित करने की यह प्रक्रिया यूं तो देश भर में चलाई गई, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में हुए इस हस्तांतरण का जायज़ा लिया जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं. राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच द्वारा किए जा रहे एक अध्ययन में यह आंकड़ा 25 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर जाता दिखाई दे रहा है. सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे हस्तांतरण जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली और तराई क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक हुए हैं. एक ही अधिसूचना में एक-एक लाख एकड़ के कई इंद्राज अभिलेखों में दर्ज हैं. आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वन विभाग को ज़मीन हस्तांतरण के संबंध में प्रदेश के राज्यपालों द्वारा जारी की गईं इन अधिसूचनाओं के दस्तावेज़ अन्याय की गाथा बयान करते हुए सरकारी पुस्तकालयों में अभी भी मौजूद हैं. ग़ौरतलब है कि सोनभद्र सहित पूरे कैमूर को प्रदेश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है. आएदिन इस क्षेत्र में नक्सलवाद से निपटने के लिए करोड़ों रुपये के सरकारी पैकेज की घोषणाएं होती रहती हैं. क़रीब तीन वर्ष पूर्व इसके लिए क्षेत्र में दस हेलीपैड बनाने की योजना को मंजूरी मिली है. हास्यास्पद तथ्य यह है कि हेलीपैड बनाने की मंजूरी के साथ-साथ पुलिस के एक मंडल स्तरीय आला अधिकारी का बयान भी आता है कि पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में नक्सलवाद से संबंधित कोई बड़ी घटना नहीं घटी. इस उच्चाधिकारी का बयान एकदम दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पिछले सात वर्षों में इस क्षेत्र में नक्सलवाद से संबंधित कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, तो फिर किस नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को यहां करोड़ों रुपये के पैकेज या हेलीपैड बनाने जैसी योजनाओं को मंजूरी देने की ज़रूरत महसूस होती है, क्यों आएदिन यहां के गांवों में बसे सीधे-सादे दलित आदिवासियों को नक्सली बताकर उनकी गिरफ्तारियां करने की कवायद छिड़ी हुई है?

वन विभाग को ज़मीनों के हस्तांतरण, दबंग समुदायों एवं बड़ी कंपनियों के वर्चस्व और वन विभाग एवं पुलिस द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के कारण इस क्षेत्र में फैले असंतोष के चलते यहां नक्सलवाद को पनपने के लिए ज़मीन तो मिली, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान क्षेत्र में जैसे-जैसे जनवादी आंदोलनों की जड़ें मज़बूत हुईं और यहां के दलित आदिवासियों ने लोकतांत्रिक रास्ता अपनाते हुए छिनी हुई ज़मीनों पर वापस अपने दख़ल क़ायम करने शुरू किए हैं, वैसे-वैसे उनका हथियारबंद आंदोलनों से भी मोहभंग होता चला गया. इसलिए आला अधिकारियों को यह बयान देने का मौक़ा मिलता है कि यहां पिछले चार वर्षों में नक्सलवाद से जुड़ी कोई बड़ी घटना नहीं हुई. यहां के दलित आदिवासियों, खासकर महिलाओं ने स्थानीय वन विभाग एवं पुलिस से निपटने के लिए किस कदर जनवादी तौर-तरीक़े अपना रखे हैं, इसका उदाहरण गांव हरना कछार में घटी एक घटना है. हुआ यह कि ज़मीनों पर स्थानीय दलित आदिवासियों द्वारा क़ायम किए गए दखल को खारिज करने की नीयत से कई स्थानीय अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर यहां पहुंचे. पुलिस ने अपने पुराने हथकंडे अपनाते हुए यहां बसाए गए झोपड़ीनुमा घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया. आदिवासी महिलाओं ने जब विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी करते हुए पुलिसकर्मियों ने उनकी साड़ियां खींचना शुरू कर दिया. क्षुब्ध होकर इन आदिवासी वीरांगनाओं ने पूर्ण रूप से जनवादी तरीक़ा अपनाते हुए अपनी साड़ियां स्वयं खोल-खोलकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया. इस जनवाद के आगे पुलिस भौचक्की रह गई और वहां टिक नहीं सकी. नतीजतन उसे वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा. आदिवासियों एवं अन्य वनाश्रितों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की दुहाई देता नया वनाधिकार क़ानून 2006 मौजूद है, बावजूद इसके वन विभाग और पुलिस द्वारा अंजाम दी जाने वाली ऐसी कार्रवाइयां कई सवाल छोड़ जाती हैं.

वन विभाग को ज़मीनों के हस्तांतरण, दबंग समुदायों एवं बड़ी कंपनियों के वर्चस्व और वन विभाग एवं पुलिस द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के कारण इस क्षेत्र में फैले असंतोष के चलते यहां नक्सलवाद को पनपने के लिए ज़मीन तो मिली, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान क्षेत्र में जैसे-जैसे जनवादी आंदोलनों की जड़ें मज़बूत हुईं और यहां के दलित आदिवासियों ने लोकतांत्रिक रास्ता अपनाते हुए छिनी हुई ज़मीनों पर वापस अपने दखल क़ायम करने शुरू किए हैं, वैसे-वैसे उनका हथियारबंद आंदोलनों से भी मोहभंग होता चला गया.

वन विभाग को ज़मीनें हस्तांतरित करने की यह प्रक्रिया यूं तो देश भर में चलाई गई, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में हुए इस हस्तांतरण का जायज़ा लिया जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं. राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच द्वारा किए जा रहे एक अध्ययन में यह आंकड़ा 25 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर जाता दिखाई दे रहा है. सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे हस्तांतरण जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली और तराई क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक हुए हैं.

जिस जनवादी आंदोलन के चलते आज यह पूरा क्षेत्र हथियारबंद आंदोलनों की चपेट में जाने से बचा हुआ है, उसी को कुचलने के लिए यहां का वन विभाग, पुलिस-प्रशासन, उनका संरक्षण प्राप्त दबंग समुदाय और एनजीओ चलाने वाले कई तथाकथित समाजसेवी हर वक़्त कमर कसकर तैयार बैठे रहते हैं. आज ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर विश्व भर के पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिक चिंता में डूबे हुए हैं. उन्हें भी मालूम है कि ऐसा हरे जंगलों के लगातार घटने के कारण हो रहा है. अभी जापान की एक संस्था ने जाइका के नाम से जंगल में पेड़ लगाने के लिए भारत सरकार से एक क़रार के तहत क़रीब डेढ़ अरब रुपये का एक प्रोजेक्ट लिया है. यह पैसा वन विभाग के माध्यम से जंगल की खाली पड़ी ज़मीनों पर उसके हिसाब से पेड़ लगाने के लिए ख़र्च किया जा रहा है. योजना के तहत यूकेलिप्टस, सफेदा एवं साल जैसे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, जिनसे न ज़मीन का भला होने वाला है, न जंगल का और न पर्यावरण का. वन विभाग पौधारोपण के मामले में हमेशा नाकाम सिद्ध हुआ है और उसकी गवाही विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले दस्तावेज़-वर्किंग प्लान चीख-चीखकर एक-एक आंकड़े के साथ देते हैं. सरकारें उसी वन विभाग के साथ मिलकर नए पेड़ लगाने के जाइका जैसे कार्यक्रम परोसती रहती हैं.

दूसरी तरफ़ क्षेत्र की महिलाओं ने जंगल की ज़मीन पर अपनी मर्जी के फल और ऑक्सीजन देने वाले ऐसे पेड़ों का पौधारोपण शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ़ जंगल और यहां रहने वाले समुदायों को, बल्कि पूरी पृथ्वी पर जीवन बचाने में सहायक साबित हो सकते हैं. शर्त यही है कि दुनिया के तथाकथित पर्यावरणविद् और वन वैज्ञानिक अपने किताबी ज्ञान का सिंहासन छोड़कर वन समुदायों पर यक़ीन करते हुए वनों को वापस उनके हवाले कर दें. पर्यावरणीय असंतुलन के कारण पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाने की दुहाई देते हुए घड़ियाली आंसू बहाना आम हो चला है. दूसरी तरफ़ जब आदिवासी वन विभाग के क़ब्ज़े की खाली एवं अधिकांशतः बंजर हो चली अपनी ज़मीनों पर वापस दख़ल क़ायम करता है और अपने ख़ून-पसीने से सींचकर उसे उपजाऊ, हरा-भरा करके न सिर्फ़ अपने जीने के साधन जुटा लेता है, बल्कि पूरी मानवता को बचाने की कोशिश भी करता है तो वह अपराधी कैसे हो जाता है? इस सवाल पर हर कोई ख़ामोश है. जबकि इस पर न सिर्फ़ सरकारों, बल्कि शहरी समाज के अन्य तबकों को भी आज पूरी गंभीरता के साथ विचार करना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

धीरज अपने बारे में बताते हुए लिखता है कि वह सीबीएसई बोर्ड का छात्र रह चुका है. उसके पिता रामदेव शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात थे. 1997 में बदमाशों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई.

वाराणसी सेंट्रल जेल से एक क़ैदी की चिट्ठी

मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा

उत्तर प्रदेश की वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी धीरज कुमार शर्मा ने चौथी दुनिया को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं. पत्र में लिखा गया है कि जेल में मिल रही मानसिक प्रताड़ना और धमकी से मैं टूट गया हूं. ऐसी हालत में मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है. मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा या किसी की हत्या कर दूंगा. इस पत्र से एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि एक कैदी द्वारा सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल किए जाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ. यह सर्वविदित है कि सूचना अधिकार क़ानून के इस्तेमाल की वजह से आम आदमी, जो जेल में नहीं है, को भी प्रताड़ित करने की ख़बरें आएदिन आती रहती हैं. हमने इस मामले में जेल अधीक्षक कैप्टन एस के पांडेय से बात की. उनका कहना था कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है और उक्त कैदी अपने स्थानांतरण के लिए यह सब कर रहा है. अब धीरज कुमार शर्मा के साथ जेल में क्या हो रहा है, किसकी ग़लती है, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, यह सब जांच का विषय है. जेल से भेजे गए इस पत्र को हम इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले की जांच हो और सच सामने आ सके. चौथी दुनिया यहां धीरज कुमार शर्मा और जेल अधीक्षक, दोनों की बातों को प्रकाशित और सार्वजनिक कर रहा है. अब यह ज़िम्मेदारी जेल प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित एजेंसियों की है कि वे इस पूरे मामले की जांच कराएं और सच को सामने लाएं.

वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद धीरज शर्मा नामक एक युवक चौथी दुनिया को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाता है. आख़िर क्यों? दरअसल, ऐसी घटना एक व्यक्ति के मन में विश्वास और अविश्वास की एक साथ चल रही कहानी का ही परिणाम है. अविश्वास उस व्यवस्था पर, जहां से उसे न्याय की उम्मीद नहीं है और विश्वास उस संस्था से, जहां से उसे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है. पूरा मामला कुछ यूं है. धीरज कुमार शर्मा वल्द स्वर्गीय रामदेव शर्मा जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है. धीरज अपने पत्र में लिखता है कि 26 जुलाई, 2006 को अपराध संख्या 607/2006 एवं धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट और आख्या संख्या निल/2006 एवं धारा 41, 411 के तहत थाना कसया, जनपद कुशीनगर द्वारा उसका चालान किया गया था. वह 26 जुलाई, 2006 से जनपद कारागार देवरिया में बंद था. इस मुक़दमे में (एक किलो पांच सौ ग्राम चरस की तस्करी) अपर जनपद न्यायाधीश कुशीनगर (एएसजे/एफटीसी द्वितीय) यानी त्वरित न्यायालय द्वारा 27 अक्टूबर, 2009 को दस वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड और अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त दो वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. धीरज का मानना है कि जनपद न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 21 का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि धारा 21 में यह कहा गया है कि अगर कम मात्रा में चरस है तो तीन से सात साल की सज़ा दी जाए. धीरज अपने पत्र में लिखता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर एवं न्यायमूर्ति ए के ठक्कर की खंडपीठ ने 6 जुलाई, 2007 को अपने एक निर्णय में कहा है कि अभियुक्त की हैसियत देखकर ही जुर्माना किया जाए, जिसमें अतिरिक्त सज़ा मात्र छह माह की हो. इसके आगे वह लिखता है कि जिस समय उसे न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई, उस समय अपराध संख्या निल/2006, यू/एस 41, 411 आईपीसी में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसमें वह अभी भी विचाराधीन है. बावजूद इसके 17 मई, 2010 को धीरज का स्थानांतरण जनपद कारागार देवरिया से केंद्रीय कारागार शिवपुर वाराणसी कर दिया गया. धीरज बताता है कि महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं लखनऊ, उत्तर प्रदेश के आदेश का पालन जनपद कारागार देवरिया के अधीक्षक द्वारा नहीं किया गया. महानिरीक्षक के आदेश में यह कहा गया है कि जिस अभियुक्त का दूसरा वारंट हो, उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. न्यायपालिका के आदेशानुसार, किसी अभियुक्त का स्थानांतरण करने से पूर्व जेल अधीक्षक यह पता कर लेंगे कि उस जेल में संबंधित अभियुक्त का कोई दुश्मन तो निरुद्ध नहीं है. यदि है तो अभियुक्त का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.

धीरज अपने बारे में बताते हुए लिखता है कि वह सीबीएसई बोर्ड का छात्र रह चुका है. उसके पिता रामदेव शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात थे. 1997 में बदमाशों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई. पिता की हत्या के बाद उसने लखनऊ से बीएससी किया और 2000 में घर जाकर रहने लगा, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे हत्या के फर्जी मामले में फंसा दिया और वह आठ माह बाद जेल से रिहा हुआ. इसके बाद वह अपराधी बन गया. उसने कुल आठ घटनाओं को अंजाम दिया. धीरज के मुताबिक़, पुलिस ने उस पर 15 मुक़दमे फर्जी लगा दिए. अपराध संख्या निल/06, धारा 41, 411 आईपीसी के तहत न्यायालय से अभिरक्षा वारंट जारी किया गया था, जिसे जनपद कारागार अधीक्षक देवरिया द्वारा फाड़ कर फेंक दिया गया और उसके बाद उसका स्थानांतरण किया गया. धीरज यह भी बताता है कि कैसे उसने जेल के भीतर सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल किया और बदले में उसे प्रताड़ित किया गया. उसने 01 जून, 2011 को वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी, जो 2 जुलाई, 2011 को प्राप्त हुई, लेकिन सूचना भ्रामक थी. इससे नाराज़ वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वाराणसी द्वारा 07 जुलाई, 2011 को उसे चक्र संख्या 3, जो जेल का अस्पताल है, में भेज दिया गया. पत्र में धीरज कहता है कि 14 जुलाई, 2011 को पागलों का डॉक्टर बुलाकर मुझे पागल क़रार देने की धमकी और मानसिक प्रताड़ना दी गई. धीरज लिखता है कि जेल अधीक्षक को डर है कि वह जेल में हो रहे अवैध कार्यों का पर्दाफाश न कर दे, इसलिए उसे पागल घोषित कराने की साजिश रची जा रही है. धीरज ने लिखा है कि उसने इस पूरे मामले की जानकारी ज़िलाधिकारी वाराणसी, जनपद न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, मानवाधिकार आयोग लखनऊ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय को भी दी है, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई. धीरज लिखता है कि उसे फतेहगढ़ जेल में स्थानांतरित करने और हत्या कर देने की धमकी दी गई है. धीरज के मुताबिक़, उसकी हत्या या आत्महत्या या उसके द्वारा किसी अन्य की हत्या की ज़िम्मेदारी वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार शिवपुर, वाराणसी की होगी. धीरज इस पत्र के माध्यम से न्याय की मांग कर रहा है. वह चाहता है कि उसका मानसिक उत्पीड़न रोका जाए और उसका स्थानांतरण जनपद कारागार देवरिया अथवा मंडल कारागार गोरखपुर किया जाए.

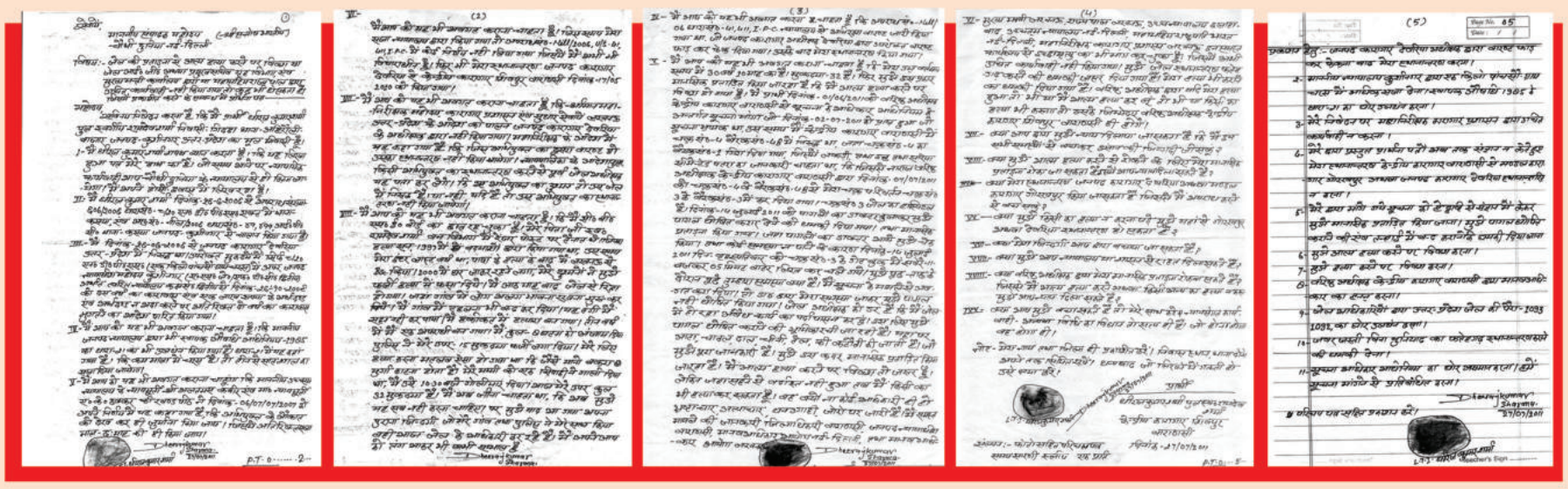

(कानून की नज़र में एक अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों की रक्षा की बात क़ानून ख़ुद कहता है. धीरज कुमार शर्मा अपराधी है, यह बात वह ख़ुद स्वीकार कर रहा है. फिर भी अगर उसने चौथी दुनिया को पत्र लिखकर अपनी आपबीती सुनाई है और जेल के अंदर की बात बाहर लाने का प्रयास किया है तो उस पर पहली नज़र में ही अविश्वास करना तर्कसंगत नहीं होगा. ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आए.)

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... राग चिदंबरम

देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है. खाद्य पदार्थों की क़ीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और इन हालात में भी देश में हर साल क़रीब 60 हज़ार करोड़ रुपये के खाद्यान्न की बर्बादी हो रही है.

शेखावाटी

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जैविक खेती और बाज़ार प्रणाली

अभिषेक रंजन सिंह

कुछ वक़्त पहले तक लोग ऑर्गेनिक फूड की ख़ूबियों से वाक़िफ़ नहीं थे. यह विदेशियों की पसंद ज़्यादा हुआ करता था, पर अब हालात बदल चुके हैं. अब भारतीय बाज़ार न सिर्फ़ ऑर्गेनिक उत्पादों से भरे पड़े हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जैविक खेती भी की जा रही है. भारत में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने का श्रेय देश के मशहूर उद्योगपति कमल मोरारका द्वारा संचालित मोरारका फाउंडेशन को जाता है. मोरारका फाउंडेशन ने वर्षों की मेहनत और सतत प्रयास के ज़रिए न सिर्फ़ जैविक खेती को एक आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया, बल्कि शेखावाटी के लाखों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है. ग़ौरतलब है कि जैविक खेती पैदावार, बचत और सेहत के नज़रिए से भी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है. लिहाज़ा किसान जैविक खेती की ओर तेज़ी से रुख़ कर रहे हैं. इससे न सिर्फ़ पैदावार बढ़ती है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में भी इज़ाफ़ा होता है. इतना ही नहीं, जैविक खेती करने वाले किसानों की फ़सलों को अन्य फ़सलों की तुलना में क़ीमत भी ज़्यादा मिलती है, जिससे वे आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे हैं. फ़िलहाल मोरारका फाउंडेशन कुल पंद्रह राज्यों में जैविक खेती करा रहा है. मोरारका आर्गेनिक के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, जो इंटरनेशनल कंपीटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर (आईसीसीओए) के भी अध्यक्ष हैं, के मुताबिक़ आईसीसीओए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग करने का काम करता है. मुकेश गुप्ता कहते हैं कि वर्ष 2008 तक भारत में 8.65 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर ऑर्गेनिक खेती हो रही थी, जो देश के कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का महज़ 0.61 प्रतिशत है, लेकिन यह जागरूकता का ही नतीजा है कि यह आंकड़ा 2012 तक 20 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाने की उम्मीद है. मुकेश गुप्ता बताते हैं कि भारत में ऑर्गेनिक उत्पादों का कारोबार हर वर्ष दोगुना होता जा रहा है. इस रफ़्तार से यह उम्मीद बंधी है कि वर्ष 2012 तक भारत से जैविक खाद्यान्नों का निर्यात 4500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है. खाद्य पदार्थों की क़ीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और इन हालात में भी देश में हर साल क़रीब 60 हज़ार करोड़ रुपये के खाद्यान्न की बर्बादी हो रही है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैविक खेती के ज़रिए इस बर्बादी को नियंत्रित किया जा सकता है. इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक फूड लंबे समय तक ख़राब नहीं होते. उनके संरक्षण के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ती. जैविक खेती के माध्यम से सूखे जैसी स्थितियों से भी निपटा जा सकता है, क्योंकि जैविक खेती में फ़सलों की सिंचाई के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहती है. मोरारका फाउंडेशन का मानना है कि आज जबकि खाने की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट होने से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में ऑर्गेनिक फूड की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जैविक उत्पादों में शुद्धता की गारंटी है. जैविक खेती के विकास और जैविक मिट्टी के महत्व को समझते हुए मोरारका फाउंडेशन ने राजस्थान के शेखावाटी समेत देश के कई हिस्सों में काम करना शुरू किया. फाउंडेशन ने इस बारे में बैठकें कीं, सेमिनार किए और घर–घर जाकर किसानों को जैविक खेती के फ़ायदे के बारे में बताया और समझाया. क्षेत्र की बंजर मिट्टी, पानी एवं बाज़ार आदि पर शोध करके फाउंडेशन ने उसका सीधा फ़ायदा क्षेत्र के किसानों को पहुंचाया. प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती की पद्धति का बारीक़ प्रशिक्षण दिया गया. नतीजतन, आज शेखावाटी का पूरा इलाक़ा अर्द्ध रेगिस्तान में हरित क्षेत्र की तरह हो गया है. आज यहां दूर–दूर तक फ़सलें लहलहाती नज़र आती हैं. खाद्यान्नों में दलहन और तिलहन ही नहीं, बल्कि हरी सब्ज़ियां भी बहुतायत में पैदा हो रही हैं. फाउंडेशन की कोशिशों के परिणाम इतने उत्साहवर्द्धक हैं कि साल के बारहों महीने शेखावाटी क्षेत्र में पैदा हुई हरी सब्ज़ियां मसलन टमाटर, बैगन, हरी मिर्च, प्याज़, लहसुन, गाज़र, करेला एवं मटर आदि दिल्ली और मुंबई के बाज़ारों में सीधे पहुंच रही हैं. यह काम मोरारका फाउंडेशन के निर्देशन में ही संभव हो पाया है. किसान मनवीर बताते हैं कि जैविक खेती से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि लागत 80 फ़ीसदी कम हो गई है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और किसानों की आमदनी 30 से 40 प्रतिशत बढ़ गई है.

मुकेश गुप्ता बताते हैं कि किसानों को कृषि से व्यवसाय जैसी आमदनी हो, इसके लिए फाउंडेशन उन्हें कई उपयोगी सलाह भी देता है, मसलन फ़सल का चुनाव, खेती करने के उन्नत तरीक़े, कृषि संबंधी आधुनिक सूचनाएं और फ़सल कटने के बाद वे कैसे बेहतर मूल्य पा सकते हैं. साथ ही फ़सल का बीमा और खाद एवं बीज की उपलब्धता आदि के बारे में भी शिविरों के माध्यम से बराबर प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके लिए मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ क़स्बे में बस स्टैंड, तहसील, पंचायत समिति और कोर्ट के पास एग्री बिज़नेस सेंटर भी स्थापित किए हैं. इन केंद्रों पर किसानों से अनाज और सब्ज़ियों की ख़रीद बेहतर मूल्य देकर की जाती है. इस तरह के कई ख़रीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. ख़रीदे गए कृषि उत्पाद को जयपुर स्थित मोरारका आर्गेनिक की प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में मज़दूर अनाज की सफ़ाई, छंटाई और पैकेजिंग का काम करते हैं. पैकेजिंग में किसी तरह की कोई खामी न रहे, इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट में मशीनों के अलावा बड़े पैमाने पर महिला श्रमिक भी रखी गई हैं.

डाउन टू अर्थ

मोरारका ऑर्गेनिक अपने रिटेल स्टोर डाउन टू अर्थ के नाम से ऑर्गेनिक उत्पादों की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में भी सामने आया है. डाउन टू अर्थ खाद्य पदार्थों की बड़ी रेंज उपलब्ध कराता है, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसालें, मिक्स मसाले, गाय का देसी घी, डेयरी उत्पाद और सीधे खाने योग्य दाल ढाबा तड़का, पंजाबी राजमा मसाला, कढ़ी, दाल मखानी, बाजरा खीचड़ा, स्नैक्स, सूजी के मीठे कुकीज, रोस्टेड नमकीन एवं नानखटाई आदि शामिल है. इन रिटेल स्टोरों के ज़रिए किसानों को बाज़ार मुहैया कराया जाता है. डाउन टू अर्थ के रिटेल स्टोर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर एवं नोएडा समेत कई शहरों में मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि मोरारका आर्गेनिक के प्रोडक्ट अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और शुद्धता के लिए देश और विदेशों में जाने जाते हैं. फिलवक्त डाउन टू अर्थ के स्टोरों में दो सौ से ज़्यादा ऑर्गेनिक उत्पाद उपलब्ध हैं. हालांकि इस वक़्त देश में ऑर्गेनिक उत्पादों के लगभग 30 मिलियन उपभोक्ता हैं, लेकिन उन्हें इन उत्पादों को ख़रीदने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए मोरारका ऑर्गेनिक ने डाउन टू अर्थ रिटेल स्टोर की शुरुआत की, जिससे उपभोक्ताओं से लेकर किसानों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है. इससे किसान बिचौलियों के चंगुल में आए बिना अपनी फ़सल का उचित मूल्य पाते हैं.

जैविक खेती मौजूदा समय की ज़रूरत

वर्तमान समय में किसानों द्वारा रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से कृषि में प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ रही है. यही नहीं, रसायनों और कीटनाशकों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है. मोरारका फाउंडेशन ने जैविक कृषि का प्रचार–प्रसार न केवल शेखावाटी, बल्कि संपूर्ण भारत में किया है. वर्तमान समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मोरारका फाउंडेशन ने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से भी क़रार किया है. फ़िलहाल फाउंडेशन क़रीब एक लाख एकड़ भूमि में जैविक खेती का विकास कर चुका है. इसके लिए फाउंडेशन वर्मी कल्चर का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहा है. वर्ष 1995 में राजस्थान सरकार ने राज्य के दस हज़ार किसानों के साथ जैविक खेती की शुरुआत करने का प्रस्ताव मोरारका फाउंडेशन के सामने रखा था. आज दो लाख से ज़्यादा किसान इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर जैविक खेती कर रहे हैं. ये किसान जैविक खादों का प्रयोग कर बेहतरीन गुणवत्ता के फल, सब्ज़ी, दलहन, तिलहन और मसालों का उत्पादन कर रहे हैं.

मोरारका फाउंडेशन से किसानों को मिलने वाले फ़ायदे

1. ख़रीफ़ की फ़सल में जैविक बीजों की उपलब्धता
2. फ़सल तैयार होने के बाद किसानों से प्रीमियम रेट (लाभांश मूल्य) पर ख़रीद
3. खेतों का आईएमओ सर्टिफिकेशन (इसका ख़र्च 10–15 हज़ार रुपये तक आता है, सभी ख़र्च फाउंडेशन की ओर से)
4. हर किसान को ग्रुप सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराना
5. ख़रीफ़ में तिल और रबी में काबुली चने के अलावा अन्य उत्पादों को अन्यत्र बेचने के लिए किसानों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट
6. खेत से फ़सलों की उठान से लेकर और ख़रीद तक सभी संबंधित ख़र्चों का फाउंडेशन द्वारा वहन
7. हर सीजन में फ़सलों की बुवाई के 15–20 दिन पहले किसानों को प्रशिक्षण

मोरारका फाउंडेशन किसानों को गोबर एवं केंचुआ से जैविक खाद और वर्मी वाश के रूप में कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग देता है. गोमूत्र, नीम, हल्दी एवं लहसुन से हर्बल स्प्रे बनाया जाता है. जैविक खेती आज इन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. फाउंडेशन इन किसानों द्वारा उपजाए गए जैविक अनाज के लिए बाज़ार भी उपलब्ध करा रहा है. नतीजतन किसानों को अपने उत्पादों के लिए बाज़ार तो मिल ही रहा है, साथ ही अपनी उपज का बेहतर दाम भी मिल रहा है. गांव बलरिया, ज़िला झुंझुनू के किसान मेवा राम का कहना है कि आज से कुछ साल पहले वह रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, लेकिन मोरारका फाउंडेशन से जुड़ने के बाद रासायनिक खादों से उन्होंने तौबा कर ली. मेवा राम के मुताबिक़, जैविक खेती करने से उन्हें काफी फ़ायदा हो रहा है. गांव मकंदगढ़, ज़िला झुंझुनू के किसान बलवंत के पास 15 बीघा ज़मीन है, जिसमें वह जैविक खेती करते हैं. उनके घर के आसपास फैली हरियाली उनकी कामयाबी की जीती–जागती मिसाल है. नाथासर तहसील, ज़िला सीकर निवासी प्रमोद जांगिड़ एक पढ़े–लिखे किसान हैं. उन्होंने हिसार (हरियाणा) से कृषि शास्त्र में डिप्लोमा किया है. प्रमोद के पास 25 बीघा ज़मीन है, जिसमें वह जैविक खेती करते हैं. प्रमोद ने मौजूदा सीजन में चार बीघा ज़मीन पर उड़द की खेती की है. उनका कहना है कि उड़द की खेती किसानों के लिए काफी फ़ायदेमंद हैं. प्रमोद के अनुसार, मोरारका फाउंडेशन ने शेखावाटी इलाक़े में दूसरी हरित क्रांति लाने का काम किया है. जैविक खेती से देसी प्रजाति के अनाज की खेती को बढ़ावा मिला है. पहले किसान हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैविक खेती का प्रचलन बढ़ने से देसी किस्मों के अनाजों के दिन दोबारा वापस आ गए हैं. जैविक अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फ़ायदेमंद है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मोरारका फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है.

वैश्विक स्तर पर भारत का ऑर्गेनिक कारोबार

भारत में हाल के दिनों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में वृद्धि होने से ऑर्गेनिक उत्पाद के कारोबार में भी तेजी दिखाई देने लगी है. आज ऑर्गेनिक क्षेत्र प्रगति की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है. आंकड़ों के मुताबिक़, दुनिया भर में कुल 30.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है. यही वजह है कि विश्व बाज़ार में जैविक उत्पाद का कारोबार लगभग 38.6 बिलियन यूएस डॉलर है. वहीं जैविक उत्पादों में भारत की भागीदारी महज़ 0.2 फ़ीसदी है यानी भारत लगभग 300 करोड़ रुपये का ऑर्गेनिक उत्पाद सालाना निर्यात करता है. मोरारका फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि ऑर्गेनिक उत्पादों का देसी बाज़ार तेजी से बढ़ता जा रहा है. लिहाज़ा उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2012 तक भारत 2.5 फ़ीसदी निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकेगा.

मोरारका ऑर्गेनिक

भारतीय परंपरा और समाज में परोपकार की अहम भूमिका रही है. एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में जन्मे जाने–माने उद्योगपति कमल मोरारका ने वर्ष 1991 में एम आर मोरारका जीडीसी रूरल रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी. इसे उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय एम आर मोरारका की याद में स्थापित किया, जिन्होंने एमएस गैनन डूंकेरले एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना की थी. फाउंडेशन की शुरुआत राजस्थान की नवलगढ़ तहसील में हुई थी. वर्ष 1993–94 से फाउंडेशन ने शेखावाटी के दस हज़ार लोगों को अपनी सेवाएं देना शुरू किया. मौजूदा समय में मोरारका फाउंडेशन 15 राज्यों में अपनी गतिविधियां चला रहा है और क़रीब दस लाख लोगों को अपनी सेवाएं मुहैय्या करा रहा है. मोरारका ऑर्गेनिक ने भारत से बाहर नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोस्टारिका, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ अन्य कई देशों से भी कई क़रार किए हैं.

arsingh@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट बैंक स्पष्ट रूप से मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन केवल इस तरह के मतदाताओं के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता.

सार्क देशों का यह भी तर्क है कि उत्पीड़क आधारित 1951 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या 1967 का प्रोटोकॉल इस क्षेत्र में मौजूदा शरणार्थी समस्या से व्यापक तौर पर निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

कोई मालिक नहीं

प्रकृति का नियम है कि कुछ न कुछ काम आदमी को करना ही पड़ता है. काम न करने में भी एक विशेष क्रिया की प्रेरणा सन्निहित है. अगर एक आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसके हिस्से का काम किसी दूसरे को करना ही पड़ेगा. अगर सारा राष्ट्र काम करना बंद कर दे या निष्क्रिय हो जाए तो अकाल और दुर्भिक्ष से मानव मात्र नष्ट हो जाएगा, मर-खप जाएगा. इसलिए काम करने का उत्तरदायित्व तो प्रकृति ने आपको, हमको, सबको दिया ही है. सिर्फ़ स्वतंत्रता है कि कौन कितना काम करे, यही विचारने की. काम का, उसकी लोकप्रियता के अनुपात पर अवकाश या फुर्सत से संबंध जोड़ दिया जाए तो समस्या हल हो जाती है. जिसे अवकाश या फुर्सत कहा जाता है, उसमें भी आदमी कुछ न कुछ काम करता ही है. मेहनत, मज़दूरी या अपनी ड्यूटी का काम करना ऐसा काम है, जिससे राष्ट्र को जो फ़ायदा पहुंचता है, सब उसका समान रूप से उपभोग करते हैं.

अवकाश या फुर्सत में भी लोग अपने-अपने शौक का काम करते ही हैं. जैसे कई लोग बागवानी, साग-सब्ज़ी पैदा करने का शौक रखते हैं, कई लोग मुर्गियां पालते हैं, कई लोग फुटबाल या गोल्फ खेलते हैं, कई स्त्रियां सिलाई या बुनाई का काम शौक के लिए करती हैं. तात्पर्य यह है कि जो अवकाश या फुर्सत में स्वेच्छा से अपने मन का शौक पूरा करने के लिए काम किए जाते हैं, वे भी तो देश का धन बढ़ाने में सहायक होते हैं. अवकाश का समय मानव आराम में गुज़ारता है. आराम शरीर की थकान को मिटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, हालांकि आराम से कोई धन पैदा नहीं होता. पर अगर मानव आराम न करे तो दूसरे ही दिन उसकी ड्यूटी का काम करने की कार्यक्षमता नष्ट हो जाएगी और स्वेच्छा से अवकाश में भी काम नहीं कर सकेगा. मानव दिन भर में तीन तरह का कार्य करता है-(1) कर्तव्य को निभाने के लिए निश्चित ड्यूटी का काम, (2) अवकाश के समय स्वेच्छा से अपने मनपसंद के काम और (3) शरीर की थकान मिटाने के लिए आराम.

प्रकृति ने जो काम मानव पर लाद दिए हैं, उनमें इन तीनों का समावेश हो जाता है. काम करने में, दास की तरह या बैल की तरह जुटे रहने में हमें आपत्ति क्यों है? इसलिए न कि कोई दूसरा व्यक्ति मालिक बनकर अपने से काम ले रहा है. इससे आत्मा विद्रोह करने लगती है. क्या अधिकार है, एक आदमी दूसरे मनुष्य को दासता के बंधन में जकड़े? पर समान वित्त वितरण हो जाने से सब कार्य स्वांतः सुखाय हो जाएंगे. प्रकृति की प्रकृति को कोई बुरा नहीं कहता. नैसर्गिक नियमों को मानते रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सहर्ष तैयार है. सिर्फ़ दूसरों की गुलामी बर्दाश्त नहीं होती. काम करने की भी एक लत हो जाती है, फिर वह आदमी कभी 5 मिनट के लिए भी निठल्ला बैठ ही नहीं सकता. काम में अपने आप आनंदानुभूति होने लगती है और अपने आनंद के लिए ही मानव काम में संलग्न रहता है. पर यह संभव तब ही है, जब ऊपर कोई हुकूमत करने वाला न हो और स्वेच्छा से आपको, हमको, सबको काम करने दिया जाए. समान वित्त वितरण हो जाने से न कोई हुकूमत कर सकेगा, न किसी की दासता ही रहेगी. सब उसी प्रकृति या नियति के विधान में अपना-अपना काम करते रहेंगे.

विकराल जनसंख्या

समान वित्त वितरण व्यवस्था में अब कठिन समस्या है जनसंख्या की. एक दंपति के दस बच्चे हैं, वह परिवार उपार्जन तो बहुत कम करता है और हिस्सा बराबर-बराबर का लेता है, जबकि दूसरे दंपति के एक ही बच्चा है या है ही नहीं. मानव की मानसिक भावनाएं वात्सल्यपूर्ण होती हैं. हर माता-पिता अपने बच्चों को सुखी और समृद्ध देखना चाहता है. समान वित्त वितरण योजना के विरोधियों का यह कहना है कि बिना काम किए या बहुत थोड़ा किए भी जब 10 बच्चे सुख से पुष्पित-पल्लवित होंगे, जबकि हमारा तो सिर्फ़ एक ही बच्चा उस राष्ट्रीय धन से पाला-पोसा जाएगा. अगर यही भावना सब नागरिकों में व्याप्त हो गई तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सारी पृथ्वी में उनके खाने के लिए अन्न उपजाने की शक्ति ही न रहेगी.

वे नहीं जानते कि प्रकृति हमेशा से अपना संतुलन बराबर रखती है. कोई मानव जाति अपने आपको मिटाने पर तुली हो तो वह उसे मिटने नहीं देती. भयंकर रूप से जनसंख्या बढ़ाकर संसार को ओतप्रोत करने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता. प्रकृति के नियम विचित्र हैं. इन्हें पूर्ण रूप से समझने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हुआ. भारत की जनसंख्या 40 करोड़ की है, जबकि आज से बीस वर्ष पूर्व भारत और पाकिस्तान की मिलकर 33 करोड़ की जनसंख्या मानी जाती थी. किसी भी नगर या शहर में रहने के लिए मकान प्राप्त नहीं हो सकते. खाने के लिए अन्न की समस्या विकट है. प्रकृति का नियम इस तरह से तकलीफ़ पहुंचा कर, दुःखी करके भारतीय जनसंख्या को नष्ट करना ही है तो [illegible] इस नियम से. इसको ठीक करने का ज़रूर कुछ न कुछ उपाय होना ही चाहिए.

यह ठीक है कि साधारण नियम हमेशा लागू हो नहीं सकता. जनसंख्या में वृद्धि होना जहां बहुत बड़ा अभिशाप है तो दूसरी ओर बहुत बड़ा वरदान भी है. जितने ज़्यादा आदमी काम करने वाले होंगे, राष्ट्रीय धन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. असल मायने में मानव की कार्यशक्ति ही तो धन है. जिस राष्ट्र के पास यह धन ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में है, वह राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा धनी है. प्रकृति के संतुलन की बात तो यों है कि अगर [illegible] हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के सफल प्राणी जीवित रहें तो उनकी संख्या 400 वर्षों में 2 करोड़ के लगभग हो जाती है. यह संभव नहीं है. एक कॉड मछली एक साथ लाखों अंडे देती है या एक मधुमक्खी एक साथ हज़ारों मधुमक्खियों को जन्म देती है, पर उनका नाश भी उसी हिसाब से होता ही रहता है. जिस प्राणी की जितनी खपत है, उसी अनुपात से उसकी पैदावार होती है. यही प्राकृतिक नियम है. इसे ही प्रकृति का संतुलन कहते हैं. गंदी बस्तियों या मोहल्लों में, [illegible] जातियों में [illegible] का कोई साधन नहीं है, वहां बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं और उसी अनुपात से उन्हीं मोहल्लों या जातियों में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु भी होती है. जिस देश में अत्यधिक गरीबी है, आर्थिक स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा निर्बल है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और मरते हैं. जाति [illegible] मिट न जाए, इसलिए प्रकृति ज़्यादा संख्या में जन्म कर देती है, जिससे कि पर्याप्त मरण के बाद भी उपयुक्त संख्या में लोग बच जाते हैं.

प्रकृति के इस नैसर्गिक नियम पर ही अवलंबित रहकर प्रस्तुत विकट प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती. इसलिए संतति नियमन अनिवार्य होना ही चाहिए, दंपति को 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. क़ानून द्वारा उसके बाद उन्हें बाध्य कर दिया जाए कि पुरुष या स्त्री का आपरेशन करा ही देना चाहिए. या अन्य आधुनिक तरीक़ों से [illegible] नियमित और नियंत्रित बनाए और बाहरी उपकरणों का सहारा ले. इस तरह का क़ानून बनाकर निश्चय ही इस बढ़ती हुई जनसंख्या का इलाज किया जाना आवश्यक है. आप कहेंगे कि बड़ी विपरीत बात है. एक ओर तो कहा जाता है कि जिस राष्ट्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा मानव धन है, वह देश ज़्यादा से ज़्यादा धनी है. दूसरी तरफ़ बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए आप क़ानून बनाने की बात करते हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नद्रष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

जनता के मन में विश्वास पैदा करने की ज़रूरत

टू जी स्पेक्ट्रम बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है. शायद सबसे बड़ा घोटाला नहीं है. सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है अभी गर्भ में हो, आने वाला हो. लेकिन यह घोटाला ऐसा ज़रूर है, जिसने लोगों के मन में उत्सुकता पैदा कर दी है. उत्सुकता यह है कि क्या इस घोटाले की जांच में कुछ निकलेगा, जिसने कई मंत्रियों की बलि ली और उन्हें जेल में पहुंचाया. इस सारी कवायद का आख़िर नतीजा कोई निकलेगा या नहीं, यह सवाल देश के लोगों के मन में जरूर है. अब सवाल उठता है कि तुरुप का इक्का किसके पास है, इस सारे घोटाले के मंथन में से मक्खन क्या निकलेगा. अजीब-अजीब नाम आ रहे हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उनके पास सूचना के अधिकार के तहत मिला एक काग़ज़ है, जिसे प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा था और जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम की भूमिका को लेकर कुछ सवाल उठाए गए हैं. किसने यह काग़ज़ सुब्रह्मण्यम स्वामी के पास तक पहुंचाया. ज़रूर किसी ने आरटीआई डाली होगी, जब श्री स्वामी कह रहे हैं, पर आरटीआई के तहत यह जानकारी लेने वाले उस व्यक्ति के दिमाग़ की दाद देनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, जिसने प्रणब मुखर्जी का यह पत्र निकलवाया. कौन है वह आदमी? अगर उसका नाम सामने आया तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग आगे बढ़ें, उसे शाबाशी दें. अगर यह नाम सामने नहीं आया, तब हो सकता है कि लोगों के मन में संदेह उठे कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है.

लोगों के मन में यह धारणा बैठ चुकी है कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री मनमोहन सिंह बहुत गहरे दोस्त हैं और जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब सुब्रह्मण्यम स्वामी उस सरकार में मंत्री थे और श्री मनमोहन सिंह उस सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे. दूसरी तरफ़ राजा ने कोर्ट में बयान दिया कि प्रधानमंत्री को सारी चीज़ों की जानकारी थी और प्रधानमंत्री की जानकारी में ही उन्होंने सारे फ़ैसले लिए. राजा अगर सिर्फ़ एक कड़ी होते तो यह माना जा सकता था कि वह अपनी छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, लेकिन राजा मनमोहन सिंह कैबिनेट के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे. वह ऐसे मंत्री थे, जो सिर्फ मंत्री ही नहीं थे, बल्कि इतने हेकड़ीबाज़ मंत्री थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा किए हुए किसी भी काम में प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप नहीं किया. प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब आख़िरी तौर पर प्रधानमंत्री होता है और छोटे तौर पर वहां का एक डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेट्री होता है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की रचना के बारे में जानना हम सबके लिए ज़रूरी है. प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेट्री होते हैं. उन सारे ज्वाइंट सेक्रेट्रीज के बीच में केंद्रीय सरकार के जितने विभाग हैं, वे बंटे हुए होते हैं. उस ज्वाइंट सेक्रेट्री की ज़िम्मेदारी यह होती है कि वह उन विभागों के ऊपर नज़र रखे और वहां अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो फौरन प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दे. क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस

> **बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे राजनेता चुप रहने में भलाई समझते हैं. उन्हें यह नहीं मालूम कि सुब्रह्मण्यम स्वामी दोधारी तलवार हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी कांग्रेस के ऊपर भी वार करेंगे और करुणानिधि के लोगों पर भी वार करेंगे. सुब्रह्मण्यम स्वामी एक ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने अकेले खड़े होकर टू जी स्पेक्ट्रम की लड़ाई लड़ी. तो क्या तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल कर सुब्रह्मण्यम स्वामी के पास आ गया है. तुरुप के इक्के से मतलब यह डर दिखाना कि मेरे पास एक ऐसा पत्ता है, जिसे अगर मैं खोल दूं तो हारी हुई बाज़ी जीत सकता हूं.**

ज्वाइंट सेक्रेट्री के पास संचार मंत्रालय का ज़िम्मा था, उसने संचार मंत्रालय में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री को नहीं बताया? यह जांच कैबिनेट सेक्रेट्री और प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उनको जानकारी नहीं मिली, कहीं इसमें ज्वाइंट सेक्रेट्री का भी इंटरेस्ट था क्या? लेकिन राजा का कहना है कि उन्होंने सब कुछ प्रधानमंत्री को बताकर किया. राजा के इस सवाल का जवाब इस सरकार में किसी को तो देना चाहिए. भले ही आप यह कह दें कि राजा ग़लत कह रहे हैं. मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली उन दिनों ऐसी थी कि मंत्री अपने मंत्रालय के काम का ज़िम्मेदार होता था. अगर प्रधानमंत्री कार्यालय यह कह दे तो मान लिया जाएगा कि संचार मंत्रालय में हुए सारे कामों की ज़िम्मेदारी, जिनमें घोटाले भी शामिल हैं, ए राजा के ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक यह नहीं कहा या प्रधानमंत्री ने अभी तक यह नहीं कहा.

बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राजनेता चुप रहने में भलाई समझते हैं. उन्हें यह नहीं मालूम कि सुब्रह्मण्यम स्वामी दोधारी तलवार हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी कांग्रेस के ऊपर भी वार करेंगे और करुणानिधि के लोगों पर भी वार करेंगे. सुब्रह्मण्यम स्वामी एक ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने अकेले खड़े होकर टू जी स्पेक्ट्रम की लड़ाई लड़ी. तो क्या तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल कर सुब्रह्मण्यम स्वामी के पास आ गया है. तुरुप के इक्के से मतलब यह डर दिखाना कि मेरे पास एक ऐसा पत्ता है, जिसे अगर मैं खोल दूं तो हारी हुई बाज़ी जीत सकता हूं. जिन लोगों ने टू जी स्पेक्ट्रम में पैसे खाए, उनके तार या उनका जोड़ किस-किस से है, क्या इसकी जानकारी सुब्रह्मण्यम स्वामी के पास पहुंच चुकी है. सुब्रह्मण्यम स्वामी का आत्मविश्वास तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, लेकिन शायद वह नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत हैं, सारे सबूत नहीं हैं. मान लीजिए, सुब्रह्मण्यम स्वामी वे सबूत खोल दें तो उनके ऊपर आंदोलन कौन करेगा या उनका नोटिस कौन लेगा. सवाल जितना सीधा है, जवाब भी उतना ही सीधा है. आंदोलन जनता कर सकती है और नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के मन में विश्वास नहीं है कि इस मामले का कुछ भी हल निकलेगा. जनता को लगता है कि कुछ समझौते होंगे, कुछ लेनदेन होंगे, कुछ लंबी-चौड़ी बातें होंगी, फिर कुछ लीपापोती की बातें होंगी और अंत में इस कांड से कुछ नहीं निकलेगा. ठीक उसी तरह, जैसे हिंदुस्तान में अब तक हुए बड़े-बड़े घोटालों में से किसी के बारे में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया. लेकिन यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. जनता अपने शासक में ईमानदारी भी देखना चाहती है, गतिशीलता भी देखना चाहती है और विश्वसनीयता भी देखना चाहती है. इसलिए अगर हम साधारण पत्रकारों की बात पर यह सरकार ध्यान दें तो हम विनम्रता से यही कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में आप इतना विश्वास ज़रूर बैठाइए कि अब तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब कुछ न कुछ ज़रूर होगा. यह विश्वास सरकार बैठाएगी या सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं, लेकिन अपेक्षा दोनों से है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

ज़ख्म कुरेदने की क़वायद

मेघनाद देसाई

पुरानी यादें भी एक आश्चर्यजनक चीज हैं. हम लोग अपनी पुरानी विजय को ताजा रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि बीच का समय समाप्त हो जाए और हम फिर से युवा हो जाएं. इसी तरह की स्थिति लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में देखी जा सकती है. उन्होंने एक बार फिर से रथ यात्रा करने का फ़ैसला लिया है. वह फिर से अपनी पुरानी रथ यात्रा की सफलता को भुनाना चाहते हैं. राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसी सफलता पहले मिली हो, वैसी ही फिर से मिल जाए. मैंने सोचा कि भाजपा या संघ का कोई व्यक्ति आडवाणी को ये बातें बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय भाजपा ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी और निश्चिंत हो गई. भाजपा के इस रवैये ने कांग्रेस की सहायता की और किसी तरह संसद की गरिमा के नाम पर आंदोलनकारियों से समझौता हो गया. अब अगर आडवाणी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रथ यात्रा निकालते हैं तो क्या वह उत्तराखंड और कर्नाटक के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का साहस करेंगे, जहां उनकी ही पार्टी की सरकारें हैं. वामपंथी पार्टियों को छोड़कर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी भारत में नहीं है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना सिर ऊंचा रख सके. विपक्ष में रहना ही सही होने या नैतिक होने की गारंटी नहीं है. विपक्ष में रहकर केवल सरकार की खिंचाई की जा सकती है.

सबसे बड़ी बात है कि यह यात्रा उन पुरानी घटनाओं की यादें ताजा कर देगी, जो आडवाणी की उस यात्रा के दौरान घटी थीं. उसी यात्रा के समय दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था. भारतीय मुस्लिम उसे अभी भी भूल नहीं पाए हैं. आडवाणी की यह रथ यात्रा चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही क्यों न हो, मुसलमानों को उस डरावनी यात्रा की याद दिलाएगी, जिसके बारे में आडवाणी ने कहा था कि दिसंबर 1992 की घटना से वह ख़ुद भी बहुत आहत हुए हैं. जिस तरह की यात्रा आडवाणी ने उस समय की थी, वह आरएसएस, बजरंग दल या वीएचपी जैसे संगठनों के लिए भले ही विजय दिलाने वाली हो सकती है, लेकिन उस राजनीतिक दल के लिए कभी अच्छी नहीं कही जा सकती, जिसे देश का शासन चलाना है. भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट बैंक स्पष्ट रूप से मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन केवल इस तरह के मतदाताओं के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता. इस मुद्दे पर बुश की बात सही जान पड़ती है. उन्होंने कहा था कि कोर वोट की तरफ़ जाना सुविधाजनक होता है. अगर आप एक नहीं, दो-दो चुनाव लगातार हारे हैं. मैं इस मनोदशा को भलीभांति जानता हूं. मेरी लेबर पार्टी लगातार चार बार चुनाव हारी. पहले दो चुनावों में हम अपने कोर वोट पर ही टिके रहे, जिसके कारण हार होती रही, लेकिन इसके बाद हमने वास्तविकता को समझा कि कोर वोट जो नहीं बता सकते, वह दूसरे लोग बताते हैं. वे लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जिसे सुनना चाहिए. इसके बाद हमने अपनी पार्टी के अंदर आधुनिक मतदाताओं की सोच के आधार पर बदलाव किया, जिसके बाद हम जीतने लगे. भाजपा को भी ऐसा सोचना चाहिए.

भारत के अधिकांश मतदाता 1984 के बाद पैदा हुए हैं, जिन्हें बंटवारे के समय की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है. आरएसएस मराठा-पेशवा के हिंदू पद-पदशाही के सपने से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आधुनिक युवा, यहां तक कि नेहरू भी प्राचीन भारत के गौरव को ही महिमामंडित करते नज़र आएंगे. अन्ना हजारे के आंदोलन में लोगों ने भाग लिया, क्योंकि यह उनके सपनों के क़रीब था और अन्ना हजारे का संदेश सामान्य था. उन्होंने साधारण जीवन का उदाहरण पेश किया, जो लोगों को पसंद आया. पुराने राजनेताओं ने दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों की बात कहकर अन्ना के आंदोलन में खामियां तलाश कीं, लेकिन यह अब पुरानी बात हो गई है. भारत के लोग अब इन नेताओं के झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें इनकी वास्तविकता मालूम है. वे अब धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर धोखा खाने वाले नहीं हैं.

यदि भाजपा को वास्तविक तौर ख़ुद को ऐसा राष्ट्रीय दल साबित करना है, जो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी. नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, जिसमें मुक़दमे को निचली अदालत में भेजने की बात कही गई है, के बाद ट्विटर पर लिखा कि ईश्वर महान है. यह काफी दु:खदायी है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा गुजरात के न्यायालय में चलने से उन्हें राहत मिलेगी, तो यह न्यायालय का अपमान है. वैसे भी भारत की न्याय व्यवस्था धीमी है और जब मामला अल्पसंख्यकों का हो, तो यह और भी मंद हो जाती है. इसे 1984 के दिल्ली के दंगों और 1993 की मुंबई की घटना के संदर्भ में देखा जा सकता है. अभी तक किसी को भी इन मुक़दमों में सज़ा नहीं मिली है. 27 सालों के बाद भी सिखों को इंसाफ़ नहीं मिला. हालांकि प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्षमा मांगी है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन इसे न्याय न मिलने की क्षतिपूर्ति नहीं कहा जा सकता. हम आशा करते हैं कि मोदी के मामले में ऐसा न हो. फ़ैसला चाहे जो भी हो, लेकिन समय पर हो जाना चाहिए. यह पीड़ित व्यक्ति के लिए भी सही है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी.

feedback@chauthiduniya.com

कमल मोरारका का ब्लॉग

पुलिस तंत्र में सुधार समय की मांग है

दिल्ली हाईकोर्ट के निकट हुए बम विस्फोट ने एक बार फिर से एक बड़े ख़तरे के तौर पर आतंकवाद की ओर लोगों का ध्यान खींचा है. इसी तरह के बम विस्फोट मुंबई, पुणे एवं जयपुर आदि शहरों में भी हुए थे. लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा बम धमाका नहीं हुआ और न 2005 के विस्फोट के बाद ब्रिटेन में ही ऐसी कोई घटना घटी. आखिर हमारे देश में ही बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इसका कारण है, हमारे यहां मज़बूत पुलिस व्यवस्था का अभाव. किसी समय मुंबई पुलिस का नाम था और उसकी तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से की जाती थी, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है. आज मुंबई पुलिस की बरसों पुरानी मुख़बिर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और बम विस्फोट होने के बाद इस संबंध में किसी प्रकार का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता. इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां पुलिस फोर्स की कमी है और जितनी पुलिस है, उसमें भी बहुतों को वीआईपी सुरक्षा में लगा दिया गया है. यहां तक कि एक सांसद भी पुलिस जीप के साथ चलता है, चाहे उसे जान का कोई ख़तरा हो या नहीं. यह एक स्टेटस सिंबल बन गया है.

अब समय आ गया है, जबकि हमें पुलिस का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा. कहां कितने पुलिस वालों की तैनाती की जानी चाहिए, इस पर समुचित विचार करना होगा. यही नहीं, यह भी देखना होगा कि पुलिस अपना काम सही तरीके से करे, न कि जनता को परेशान करने में अपना क़ीमती समय बर्बाद करे. किरण बेदी ने एक बार कहा था कि पुलिस तुरत न्याय कर सकती है. उदाहरण के लिए अगर कोई चोर किसी से चेन छीन लेता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वह छीनी हुई चेन तुरंत पीड़ित को वापस दिला सकती है. किरण बेदी का कहना सही है, लेकिन आजकल कितने पुलिस वाले ऐसा करेंगे? सच्चाई तो यह है कि अगर चोर पकड़ा भी जाए तो पीड़ित को अपना ही सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे. पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है कि एक पुलिस कोड हो.

आज एक सामान्य नागरिक भी यह देख सकता है कि हमारे यहां की पुलिस कितनी ढीली-ढाली है. बड़े पेट वाले पुलिसकर्मियों से आप भला क्या उम्मीद कर सकते हैं. जो ख़ुद ही फिट नहीं हैं, वे हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? ऐसे पुलिस वाले तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ भी नहीं सकते हैं. हमारे यहां ऐसे हज़ारों युवा हैं, जो पुलिस की नौकरी करने के लिए तैयार हैं और वे इसके लिए फिट भी हैं. अगर पुलिस में नौकरी करने वाले लोगों की कार्यक्षमता का क्षरण हो गया है तो हमें युवाओं को भर्ती करने की आवश्यकता है, ताकि हम भी ब्रिटेन और अमेरिका की तरह आतंकवाद से लड़ने में सफल हो सकें. कुछ ही महीनों के अंतराल पर हमारे यहां कोई न कोई आतंकवादी घटना हो जाती है और हर बार एक ही तरह की बातें सुनने को मिलती हैं.

आज समय आ गया है कि यदि सामान्य नागरिकों से प्राप्त संसाधनों को पुलिस पर ख़र्च किया जा रहा है तो पुलिस को भी ज़िम्मेदार होना चाहिए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ख़ुफ़िया तंत्र से युक्त सशक्त पुलिस इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकती है. इतना तो कम से कम जनता के लिए किया ही जाना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

सौमित्र मोहन

शरणार्थी समस्या : सकारात्मक पहल की ज़रूरत

जनसंख्या विस्थापन के क्षेत्र में दक्षिण एशिया का एक अनूठा इतिहास रहा है. यहां युद्ध के बाद लोग या तो अपने देश की सीमाओं से बाहर निकाल दिए गए अथवा वे जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए. इसके बाद पर्यावरणीय या विकासात्मक प्रक्रिया भी विस्थापन की एक वजह बनी. भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी आज़ादी के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या के गवाह रहे. 1947 के विभाजन के बाद 7.5 मिलियन हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए, वहीं 7.2 मिलियन मुस्लिम शरणार्थियों को भारत से पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी. इतिहास में दर्ज़ यह अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी विस्थापन था. इस व्यापक मानवीय संकट के समय में भी काफी कम अंतरराष्ट्रीय सहायता मिल पाई. बाद में 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के समय 10 मिलियन शरणार्थियों ने भारत का रुख़ किया. 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद 3.5 मिलियन अफ़ग़ानियों ने पाकिस्तान की शरण ली. ऐसा कहा जाता है कि इनमें 1.2 मिलियन शरणार्थी अभी भी गांवों में रह रहे हैं. 1970-1990 के दौरान बांग्लादेश में म्यांमार के राखिन ज़िले से 3,00,000 मुस्लिम शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई, जिसमें 30,000 शरणार्थी अभी भी वापस नहीं गए हैं. इसी तरह 90,000 नेपाली मूल के भूटानियों को निष्कासित कर दिया गया और उनमें से अधिकतर शरणार्थी नेपाल के झापा ज़िले में अभी भी रह रहे हैं. फिर भी संयुक्त राज्य उच्चायुक्त (शरणार्थी) द्वारा हाल में अधिकांश को तीसरी दुनिया के देशों में बसाया गया है.

> **शरणार्थी समस्या के निदान के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय साधनों के हिसाब से सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शरणार्थियों की समस्या के समाधान की दिशा में सरकारों को मार्गदर्शन देने के लिए एक ख़ास क़ानून होना चाहिए. दक्षिण एशियाई देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून स्वीकार करना चाहें अथवा वे ख़ुद एक अलग क़ानून बनाएं, लेकिन उनके लिए अब फ़ैसला लेने का वक़्त आ चुका है.**

तमिलों के बाह्य विस्थापन और सिंहली, तमिल एवं मुस्लिमों के आंतरिक विस्थापन की वजह से ही श्रीलंका को प्राय: शरणार्थी द्वीप कहा जाता है. हालांकि यह शरण देने वाला नहीं, बल्कि शरणार्थी पैदा करने वाले देशों में शुमार होता है. 1983 से श्रीलंका ने लाखों शरणार्थियों को पैदा किया. इसके अलावा 50,000 तमिल शरणार्थी पहले से ही पश्चिम देशों में शरण लिए हुए हैं. तमिलनाडु में शरण लिए अधिकांश श्रीलंकाई शरणार्थियों को स्वेच्छा से वापस भेज दिया गया, लेकिन उत्तर-पूर्व श्रीलंका में चल रहे सुरक्षा संकट की वजह से अभी भी 60,000 से अधिक शरणार्थी वापस जाने से हिचक रहे हैं. 1960 के दशक से ही भारत 1,00,000 से भी अधिक तिब्बती और 50,000 बांग्लादेशी बौद्ध शरणार्थियों की मेज़बानी कर रहा है, जिनमें कुछ ने तो हाल में भारत का रुख़ किया है. भारत ने यूएनएचआरसी को आश्वासन दिया है कि वह मानवीय आधार पर 12,000 अफ़ग़ानियों की भी मदद करेगा. मालदीव पहला सार्क देश है, जो न शरणार्थी पैदा करता है और न उन्हें शरण देता है. इन वर्तमान और अतीत के शरणार्थी संकट तथा शरण देने की पुरानी मानवीय परंपरा के बावजूद किसी भी सार्क देश ने 1951 के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें दुनिया के 136 देशों में मान्यता मिल चुकी है. फिर भी भूटान और नेपाल के अलावा सभी सार्क देशों ने शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहयोग के आधार पर मदद करने का संकल्प दोहराया है. 1951 के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल और सार्क देशों के बीच इस मसले पर असहमति के कारण काफी समान थे. उनका तर्क है कि शरण देने की उनकी परंपरा अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी बेहतर है. कभी-कभी बेहतर संसाधन वाले देशों से भी. इसीलिए वे शरणार्थी मुद्दे से द्विपक्षीय नीति के आधार पर ही निपटेंगे, लेकिन इस समस्या को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायताओं का वे स्वागत करते हैं.

सार्क देशों का यह भी तर्क है कि उत्पीड़क आधारित 1951 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या 1967 का प्रोटोकॉल इस क्षेत्र में मौजूदा शरणार्थी समस्या से व्यापक तौर पर निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है. अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी समस्या से निपटने के साधनों को अपर्याप्त बताते हुए वे अफ्रीकी शरणार्थी व्यवस्था, 1958 के अफ्रीकी एकता संगठन सम्मेलन, लैटिन अमेरिकी शरणार्थी और 1984 की कर्टेजेना शरणार्थी घोषणा जैसी व्यवस्था की मांग करते हैं, जो शरणार्थियों को व्यापक रूप से परिभाषित भी करती है. दक्षिण एशिया में शरणार्थी समस्या काफी हद तक स्थायी हो चुकी है. राज्यों द्वारा मानवीय आधार पर इन मसलों का हल न करने की वजह से यह राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सुरक्षा के लिए चिंता का सबब बन चुकी है. चूंकि तकनीकी तौर पर सभी शरणार्थियों को अवैध विस्थापक माना जाता है, इसलिए क़ानूनी तौर पर उनके पास सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता. इस स्थिति में सार्क देशों द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन या घोषणा प्रासंगिक है. साथ ही इन बुनियादी सवालों पर सहमति, मसलन शरणार्थी की परिभाषा, शरण देने और स्वेच्छा से शरणार्थियों को बसाने जैसी बातें शरण देने वाले राज्यों के वार्ताकारों के बीच तनाव कम करके बातचीत का माहौल बनाने में मददगार साबित होंगी. सार्क शरणार्थी सम्मेलन अथवा घोषणा भी इस क्षेत्र में मानवीय संकट दूर करने की दिशा में एक अहम क़दम साबित हो सकता है. भारत के मामले में उच्च न्यायालयों ने संवैधानिक और मानवाधिकारों के आधार पर शरणार्थियों के मानवीय सरोकार के मसले पर अपनी राय दी है, लेकिन किसी भी सार्क देश में इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं हुई है. वर्तमान राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े संदर्भ में प्रत्येक देश शरणार्थी समस्या का अपने द्वारा तय मानकों के हिसाब से समाधान करना चाहता है. हालांकि ये मानक समय और देशों के मुताबिक़ बदलते रहते हैं. शरणार्थी मसले पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन या घोषणा द्वारा सार्क देश मौजूदा पारंपरिक मानवीय सहायता नीति को सुधार सकेंगे, साथ ही उन्हें ग़ैर विवादास्पद सिद्धांतों को भी विकसित करने में मदद मिलेगी. ऐसे सम्मेलन अथवा घोषणाओं के दस्तावेज़ इस आधार पर तैयार किए जाएंगे कि वे इस क्षेत्र में शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त हों और यह सार्क देशों का अपना एक अंतरराष्ट्रीय क़ानून होगा.

शरणार्थी समस्या के निदान के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय साधनों के हिसाब से सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शरणार्थियों की समस्या के समाधान की दिशा में सरकारों को मार्गदर्शन देने के लिए एक ख़ास क़ानून होना चाहिए. दक्षिण एशियाई देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून स्वीकार करना चाहें अथवा वे ख़ुद एक अलग क़ानून बनाएं, लेकिन उनके लिए अब फ़ैसला लेने का वक़्त आ चुका है. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे बहुपक्षीय-क्षेत्रीय स्तर पर आसानी से निपटा जा सकता है. यह पहली बार है, जब दक्षिण एशियाई देशों ने शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक उपायों की जगह एक निर्णयात्मक फ़ैसला लिया. इसीलिए इस मसले पर उनके पास एक क़ानून होना अनिवार्य है. शरणार्थियों से संबंधित विशेष क़ानून होने के कारण उक्त देश पहले से उन्हें शरण देते आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें इन क़ानूनों को केवल औपचारिक रूप से लागू करने और एक ठोस शक्ल देने की ज़रूरत है. संबंधित क़ानूनों में राष्ट्रीय हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि शीत युद्ध के दौरान बनाए गए इन क़ानूनों में बदलाव के तहत इस उप महाद्वीपीय क्षेत्र में शरणार्थियों की वास्तविकता से इसे अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके, क्योंकि पहले के क़ानून मौजूदा समय में दक्षिण एशियाई शरणार्थियों की ज़मीनी हक़ीक़त को बयां नहीं करते. बुनियादी और सांगठनिक रूप से शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए नए क़ायदे-क़ानून क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कस्टम व्यवस्था पर आधारित होंगे. ऐसी व्यवस्था शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए अधिक तर्कसंगत होगी. साथ ही इन देशों को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाने में भी मदद करेगी. यूएनएचसीआर के नेतृत्व में मॉडल नेशनल लॉ और ड्राफ्ट रीज़नल डिक्लेरेशन का मसौदा तैयार किया जाना एक सकारात्मक क़दम है. उम्मीद की जाती है कि दक्षिण एशियाई देश शरणार्थियों से संबंधित विशेष क़ानून पर सकारात्मक रुख़ अपनाने के बाद अपनी आन (प्रतिष्ठा) को त्याग कर उदारता का परिचय देंगे.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

आतंकवाद से निपटना होगा

इस समय आतंकवाद देश के समक्ष एक बड़ा संकट है. हमारा दुर्भाग्य यह है कि कोई भी आतंकवादी घटना होते ही पड़ोसी देश का नाम लेना शुरू कर दिया जाता है. इस बात की आड़ में कौन अपना काम कर जाता है, कहना कठिन है. मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह का मामला सबके सामने है. किसी भी घटना के लिए ईमानदारी से जांच होनी चाहिए.

-अवनीश कुमार, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

डायन प्रथा पर रोक लगे

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-डायन प्रथा: जीने का हक़ मत छीनो पढ़ा. यह बेहद अफ़सोस की बात है कि आज के दौर में भी हमारे समाज में इस तरह की कुप्रथाएं मौजूद हैं. सरकार को इस तरह के मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त से सज़ा देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग इससे सबक़ हासिल करें. डायन प्रथा के ख़िलाफ़ समाज के जागरूक लोगों को भी आगे आना चाहिए. शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं.

-अनुराग, मुंबई, महाराष्ट्र.

मोदी का नाटक

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिनों के उपवास का नाटक कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है. गुजरात की जनता 2002 का दंगा भूली नहीं है और हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी को कभी माफ़ नहीं करेगा. जो व्यक्ति गुजरात की जनता के साथ राजधर्म नहीं निभा सका, वह भारत की जनता के साथ राजधर्म कैसे निभा सकता है? इसलिए मोदी दिन में सपना देखना बंद करें. प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी.

-ललन कुमार चंद्रवंशी, पटना, बिहार.

संवेदनशील मुद्दे

राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं. राइट टू रिजेक्ट रूपी मुद्दे को निस्संकोच अमल में लाया जा सकता है. यह क़दम लोकतंत्र के लिए हितकर एवं प्रभावकारी है. राइट टू रिकॉल देश की बढ़ती जनसंख्या एवं अशिक्षा को देखते हुए बेहद संवेदनशील है. सर्वप्रथम इसका प्रारूप तैयार हो और देखा जाए कि वह कितना स्वागत योग्य है. इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाना संभव है, किंतु इस आशंका की वजह से इसे किनारे भी नहीं किया जा सकता.

-श्याम कोरी उदय, *ई-मेल से.*

■ मेरे विचार से राइट टू रिजेक्ट का कोई विशेष औचित्य नहीं है. हां, राइट टू रिकॉल जरूरी है, किंतु इसे लागू करने के साथ ही चुनाव प्रणाली में अन्य संशोधन भी होने चाहिए, जिससे देश को सही नेतृत्व मिल सके और जनता शासन व्यवस्था पर अपना प्रभावी नियंत्रण बना सके.

-आशीष दुबे, *ई-मेल से.*

व्यक्तित्व की पाखी

आलेख-व्यक्तित्व की पाखी अच्छा लगा. साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक हमेशा इस संकल्प के साथ प्रवेशांक लाते हैं कि इसे आजीवन चलाया जाएगा, लेकिन ऐसी अधिकांश पत्रिकाएं संपादक के जीवनकाल में ही दम तोड़ देती हैं. राजेंद्र यादव ने तमाम झंझावात झेलते हुए इस इंटरनेट और टीवी के युग में हंस की गुणवत्ता को 25 वर्षों तक ज़िंदा रखा. हंस ने नए रचनाकारों को अवसर भी दिया.

-चंद्रशेखर चौधरी, *देवघर, झारखंड.*

पंचायत चुनाव में पैसों का बोलबाला

झारखंड में पंचायत चुनावों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ. ज़िला परिषद अध्यक्ष पद के लिए 25 लाख रुपये तक ख़र्च करके चुनाव जीता गया. मुखिया पद के उम्मीदवारों ने छह लाख, पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों ने तीन लाख और वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवारों ने दो लाख रुपये खर्च किए. प्रत्याशी पर्ची के साथ पैसे भी मतदाताओं के घर पहुंचा देते हैं. हमें इस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए.

-पंचानन महतो, *धनबाद, झारखंड.*

सरकार की अनदेखी

केंद्र सरकार विदेशी कंपनियों और कुछ घरेलू उद्योगपतियों के दबाव में आकर देश हित की अनदेखी कर रही है. 40 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रुपये की आय पर गुज़ारा करते हैं, वहीं मुट्ठी भर लोग ऐश कर रहे हैं. अधिकांश जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही है. सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए.

-एनजे, *छपरा, बिहार*

राजकमल प्रकाशन समूह
चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.
राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

हैरानी इस बात पर हो रही है कि बिल्ली 2600 किलोमीटर दूर पहुंच कैसे गई. यह पता नहीं चल पाया है कि बिल्ली बीते पांच साल कहां रही.

आरटीआई से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक़ है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह क्या, कहां और कैसे काम कर रही है. हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टैक्स देता है, इसलिए भी उसे यह जानने का हक़ है कि उसका पैसा कहां ख़र्च किया जा रहा है. जनता को यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है. 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया. अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं, तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती. 2005 में देश की संसद ने एक क़ानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि नागरिक किस प्रकार सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी. सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जांच कर सके, किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके या किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके.

सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं ग़ैर सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाएं आदि इसमें शामिल हैं. पूर्णत: निजी संस्थाएं इस क़ानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी क़ानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है. (धारा-2 (क) और (ज). हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं. यह वे अधिकारी हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं.

धारा 5 (1) लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह 30 दिनों के अंदर (कुछ मामलों में 45 दिनों तक) सूचना उपलब्ध कराए. धारा 7 (1)-अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा ग़लत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का ज़ुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है, साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी. लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे, धारा 6 (2). सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क देना होगा (केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क तय किया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. बीपीएल कार्डधारकों से सूचना मांगने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, धारा 7(5). दस्तावेज़ों की प्रति लेने के लिए भी शुल्क देना होगा (केंद्र सरकार ने यह शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखा है), लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जाएगी धारा 7 (6). यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह उस आवेदन को पांच दिनों के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे. ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी, धारा 6 (3).

लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या ग़लत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक शुल्क मांगने के ख़िलाफ़ आप केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं. लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है. जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, उनका विवरण सूचना के अधिकार क़ानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है. जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है, धारा 8 का ग़लत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है, धारा 19 (1). यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे संबंधित हो) के पास करनी होती है, धारा 19 (3).

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

न्यूयॉर्क पहुंच गई बिल्ली

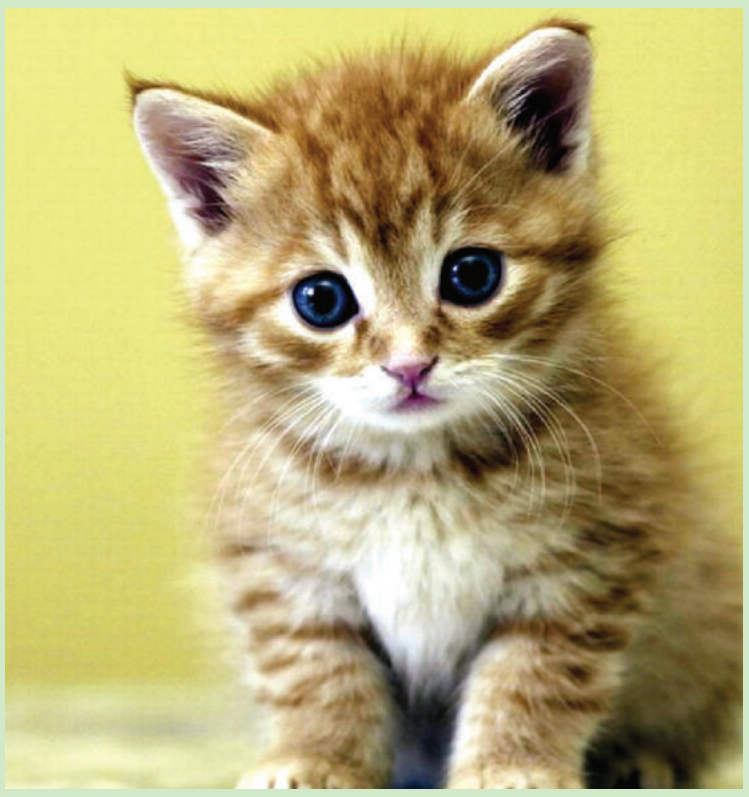

आम तौर पर कुत्तों के लिए कहा जाता है कि उन्हें कितनी भी दूर छोड़ दो, वे गंध पाकर अपने नज़दीकी के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहां जिस बिल्ली का जिक्र हो रहा है, उसकी बात ही कुछ और है. जी हां, न्यूयॉर्क की एक गली में मिली एक बिल्ली ने लोगों को हैरत में डाल दिया. विलो नामक यह पालतू बिल्ली पांच साल पहले कोलोराडो से गुम हुई थी. मालिक ने पालतू बिल्ली पर माइक्रो चिप लगा रखी थी. पांच साल बाद अचानक उनके पास एक फोन आया और पता चला कि विलो 2600 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में है. विलो मैनहट्टन की एक गली में मिली. बिल्ली के मालिक क्रिस कहते हैं, यहां उल्लू और लोमड़ियां काफी हैं. हमें लगा कि विलो मर चुकी होगी, किसी लोमड़ी ने उसे मारकर खा लिया होगा. हम उसे लेकर सारी उम्मीदें खो चुके थे, लेकिन तभी उन्हें न्यूयॉर्क एनिमल रेस्क्यू सेंटर से फोन आया. फोन करने वालों ने बिल्ली पर लगा टैग देखा और कोलोराडो फोन किया. क्रिस अपनी पत्नी के साथ अब न्यूयॉर्क जा रहे हैं. वह विलो को वापस घर लेकर आएंगे.

हैरानी इस बात पर हो रही है कि बिल्ली 2600 किलोमीटर दूर पहुंच कैसे गई. यह पता नहीं चल पाया है कि बिल्ली बीते पांच साल कहां रही. बिल्लियों की नाक इतनी तेज नहीं होती कि वह गंध का पता लगाकर वापस लौट सकें. विलो के न्यूयॉर्क में मिलने से पशुओं के जानकार भी हैरान हैं. पशु प्रेमियों का कहना है कि बिल्ली में जिंदा बचे रहने की ज़बरदस्त कला होती है. अचूक शिकार और पेड़ पर चढ़ने के हुनर की वजह से बिल्लियां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा बच जाती हैं. अपने इलाके को लेकर बिल्लियां कुत्तों की तुलना में कम भावुक होती हैं, लेकिन इसके बावजूद यह पता नहीं चल पाया कि कोई पालतू बिल्ली इतनी दूर कैसे जा सकती है. रेस्क्यू सेंटर के अधिकारी अंदाज़ा लगाते हुए कहते हैं कि हो सकता है, विलो किसी ट्रक या मालगाड़ी में चढ़ गई हो. लेकिन फिर वही सवाल आता है कि वह बीच के स्टेशनों पर क्यों नहीं उतरी. अगर उतरी, तो क्या फिर किसी गाड़ी में चढ़ी. अगर ऐसा हुआ है तो बिल्लियों की समझ के बारे में विज्ञान का दायरा एक नई दिशा में जा सकता है. ख़ैर, शुक्र है कि बिल्ली मिली तो सही...

सूरज का डबल धमाल

यह खोज कुछ नई है. इस बार वैज्ञानिकों ने दो सूरज वाले ग्रह को खोजने का दावा किया है. अंतरिक्ष विज्ञानियों ने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है, जिसके पास दो सूर्य हैं. ग्रह को केपलर 16 बी नाम दिया गया है. आकार में शनि के बराबर का कैपलर 16 बी हमारे सूर्य से छोटे दो तारों की परिक्रमा करता है. नासा की केपलर दूरबीन ने इस ग्रह को खोजा है. पृथ्वी से इसकी दूरी 200 प्रकाश वर्ष है. यह पहला मौक़ा है, जब दो सूर्यों वाला कोई ग्रह मिला है. केपलर अभियान के प्रमुख खोजकर्ता विलियम बॉरुकी ने कहा, यह नए श्रेणी के खगोलीय मंडल की खोज है, जो हमारे काम आ सकती है. हमारी आकाश गंगा के ज़्यादातर तारे बाइनरी सिस्टम में हैं. दो सूर्य होने का अर्थ है कि दिन ख़त्म होने पर केपलर 16 बी में दो बार सूर्यास्त होता होगा. केपलर 16 बी के पास मौजूद बड़ा सूरज हमारे सूर्य का 69 फ़ीसदी है. छोटा सूर्य सिर्फ़ 20 फ़ीसदी है. इसकी वजह यह है कि इस ग्रह का तापमान भी -73 से -101 डिग्री सेल्सियस के बीच है. इतनी ठंड में वहां इंसान के जीवन के लिए संभावनाएं नहीं हैं. ग्रह चट्टानों और गैसों से भरा हुआ है. केपलर 16 बी 229 दिनों में अपने दोनों सूर्यों की परिक्रमा पूरी करता है. अध्ययन से पता चला है कि जिन तारों की चमक फीकी दिखाई पड़ती है, उनमें से कुछ किसी विशाल तारे के क़रीब होते हैं. यही वजह है कि उनका प्रकाश मंद दिखाई पड़ता है. दूरबीन की मदद से वैज्ञानिकों ने एक लाख 50 हज़ार तारों के प्रकाश के फीके पड़ने की घटना का अध्ययन किया. पता चला कि कुछ तारे इस वजह से टिमटिमाते हैं, क्योंकि वह बड़ी तेजी से बड़े तारों के आसपास घूमते हैं. बड़े तारे के आभा मंडल से बाहर आने पर उनकी चमक बढ़ जाती है और बड़े तारे के साये में आकर उनका प्रकाश मंद प्रतीत होता है. इस बारे में पूरी रिपोर्ट जनरल साइंस पत्रिका ने छापी है. केपलर दूरबीन 2009 में छोड़ी गई थी. यह दूरबीन अंतरिक्ष में पृथ्वी के बराबर आकार वाले या धरती जैसे दिखाई पड़ने वाले ग्रहों की खोज कर रही है. केपलर की मदद से धरती के करीब किसी ऐसे ग्रह को खोजने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सतह पर पानी हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

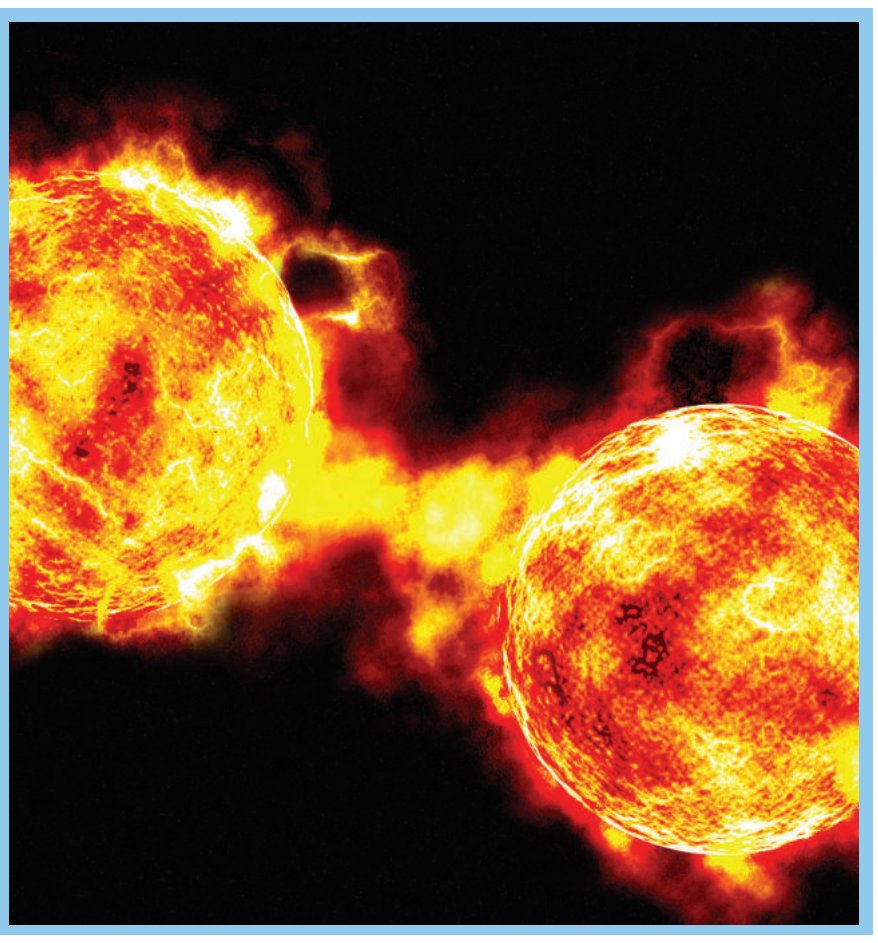

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
सप्ताह के आरंभ में अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. कोई ऐसी समस्या भी सप्ताह के मध्य हल हो सकती है, जिसके लिए आपको पहले एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था. सप्ताहांत तक मायूसी ख़त्म होगी. पेट से संबंधित शिकायत हो सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आपके पास और भी बहुत ज़रूरी काम हैं. यदि आप उन्हें पूरा कर लेंगे तो अगले दो-तीन दिनों के भीतर आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आ जाएगा. आप किसी इंवेस्टमेंट या यारी-दोस्ती के लफड़े में न पड़ें, क्योंकि ख़तरे की कोई सीमा नहीं होती.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
भाग्य की एक पतली लकीर आपके हाथों में भी विराजमान है, लेकिन काफी परिश्रम के बाद भी यह लकीर अभी तक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो पाई. अब वह समय आ गया है, जब आप अपने कर्म के बलबूते भाग्य का निर्माण कर सकने में सफल होंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आपके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण काम अभी तक किए गए हैं, उन सबका सुपरिणाम मिलना बाक़ी है. आपको धैर्य और साहस का परिचय देना है और अपनी कार्यशैली में भी तेजी लानी है. हो सकता है, कोई विरोधी या शत्रु आपके लिए ऐसा रास्ता बना रहा हो, जहां पर फंसने से बदनामी या आर्थिक क्षति हो सकती है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
सप्ताह के मध्य जो काम करना चाहिए, उसी वक्त पर आपका क़दम आगे उठता है. यही कारण है कि आप आज के दौर में एक सफल कारोबारी साबित हो सकते हैं. सप्ताह के अंत में बंधुजनों एवं मित्रों का सहयोग भी आपको समय-समय पर मिलता रहता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
योग-व्यायाम करना और पथ्य परहेज रखना आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा एक बार अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो उसे संभालने में कई हज़ार गुना समय नष्ट हो सकता है. फ़िलहाल जो भी छोटे-मोटे लाभ हैं, वे आपको सप्ताहांत तक मिल सकते हैं.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह के आरंभ में प्रतियोगिता में सफलता से ख़ुशी प्राप्त होगी. सप्ताह के मध्य में कोई ऐसा अवसर आएगा, जब आपसे भी अधिक समर्थ और धैर्यवान व्यक्ति एकाएक अपने कामकाज में विघ्न-बाधाओं का शिकार हो सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आपके व्यवहार और आचरण में अनेक प्रकार के गुण और ख़ूबियां मौजूद हैं, लेकिन इन सबका उपयोग आप अपने लिए न करके दूसरों के लिए करने में अधिक विश्वास रखते हैं. आपका हित यही है कि आप पहले अपने बोझ को हल्का करें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह के मध्य आपके निकट सहयोगी और पार्टनर फ़िलहाल आपके भरोसे अपनी नाव चलाएंगे, लेकिन ऐसा न हो कि कहीं आप अधिक आत्मविश्वास के कारण रास्ते से भटक जाएं और आपके द्वारा किया गया परिश्रम हफ्ते के अंत में व्यर्थ हो जाए.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह व्यक्तिगत जीवन में कुछ विसंगतियां चलती रहेंगी, उनके पीछे पड़कर कामकाज स्थगित रखना ठीक नहीं. सप्ताह के अंत तक आपको या तो किसी से मुलाक़ात करनी होगी या फिर सपरिवार किसी का मेहमान बनना होगा, ताकि उसे आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
यदि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, जो इस दौर में ज़्यादा कामयाब हैं तो सप्ताहांत तक उनसे मुलाक़ात हो सकती है. अपना काम निकालना आपके लिए सरल हो जाएगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
सप्ताह मध्य के बाद कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के आश्वासन से आपकी कार्यशैली अधिक प्रभावी और लाभप्रद सिद्ध होगी. सप्ताहांत का समय कुछ ख़र्चीला साबित होगा. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हों तो आवश्यक धनराशि अपने साथ लेकर चलें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़रिए लीबिया को दस लाख डॉलर की सहायता दी है और बीस लाख डॉलर की और सहायता देने की प्रक्रिया चल रही है.

लीबिया में राष्ट्रीय अंतरिम परिषद

राजीव कुमार

कर्नल मुअम्मर ग़द्दाफ़ी के शासन का अंत हो गया है. हालांकि ग़द्दाफ़ी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी पराजय हो चुकी है साथ ही लीबिया में राष्ट्रीय अंतरिम परिषद का गठन भी हो चुका है. परिषद का प्रमुख मुस्तफा अब्दुल जलील को बनाया गया है, जो ग़द्दाफ़ी सरकार में न्याय मंत्री रह चुके हैं. जलील ने विद्रोहियों पर गोली चलाने के मुद्दे पर ग़द्दाफ़ी का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद विद्रोहियों ने उन्हें अपने साथ कर लिया. जब ट्रांजिशनल नेशनल काउंसिल का गठन किया गया तो उन्हें इसका प्रमुख बनाया गया और अब वह राष्ट्रीय अंतरिम परिषद के प्रमुख हैं, जिसे लीबिया की अंतरिम सरकार कहा जा सकता है. जलील ने शहीद चौक से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक लीबिया का निर्माण उदारवादी इस्लाम के आधार पर किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही है और यह भी कहा कि देश में क़ानून शरिया के ज़रिए ही बनाए जाएंगे.

अभी भी लीबिया के कुछ क्षेत्र ग़द्दाफ़ी के क़ब्ज़े में हैं, लेकिन फिर भी विश्व के देशों ने विद्रोहियों के संगठन ट्रांजिशनल नेशनल काउंसिल को मान्यता देना शुरू कर दिया है. भारत ने भी लीबिया की इस सरकार को मान्यता दे दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि भारत लीबिया के लोगों को उनके राजनीतिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण कार्यों में हरसंभव सहायता करने को तैयार है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़रिए लीबिया को दस लाख डॉलर की सहायता दी है और बीस लाख डॉलर की और सहायता देने की प्रक्रिया चल रही है. भारत लीबिया के साथ बेहतर संबंध बनाने का हरसंभव प्रयास कर रहा है. मालूम हो कि लीबिया में विद्रोह होने से पहले तक दस–पंद्रह हज़ार भारतीय नागरिक काम कर रहे थे. लीबिया की निर्माण परियोजनाओं में कई भारतीय कंपनियां काम कर रही थीं. इसलिए ज़रूरी है कि भारत लीबिया में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करे और नई सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास जारी रखे. विश्व के अन्य देशों ने भी परिषद का समर्थन किया है. संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा टीएनसी को लीबिया का प्रतिनिधि घोषित किया गया. 193 सदस्यीय महासभा में 114 सदस्यों ने टीएनसी के पक्ष में वोट दिया, 17 देशों ने टीएनसी के विरोध में मतदान किया और 15 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया. विरोध में मतदान करने वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, कांगो, लोसोथो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला एवं केन्या के साथ–साथ लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ, वेनेजुएला और वोलिविया शामिल हैं. इनमें से अधिकांश देशों ने इसलिए टीएनसी का विरोध नहीं किया कि वे ग़द्दाफ़ी के समर्थक हैं, बल्कि उनका मानना है कि लीबिया के विद्रोह में टीएनसी को नाटो का सहयोग मिलना सही नहीं है. अगर विद्रोह केवल लीबिया के लोगों ने किया होता तो टीएनसी को समर्थन देने से इन्हें कोई गुरेज नहीं होता.

लीबिया में नाटो के सैनिक तैनात हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि जब तक ग़द्दाफ़ी के समर्थकों को पूरी तरह पराजित नहीं किया जाता, तब तक नाटो की कार्रवाई जारी रहेगी. डर तो इस बात का है कि कहीं लीबिया भी अफ़ग़ानिस्तान या इराक़ न बन जाए. विद्रोहियों की जीत के कुछ दिनों पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी लीबिया गए और वहां राष्ट्रीय अंतरिम परिषद के कार्यों की सराहना की. इन दोनों ने भी लीबिया में पूरी तरह शांति बहाल होने तक नाटो सैनिकों के बने रहने की बात कही. अंतरिम परिषद के प्रमुख अब्दुल जलील ने इन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया. अब लीबिया में शांति बहाल करने और लोकतांत्रिक सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी अंतरिम परिषद की है. परिषद को जल्द से जल्द सरकार गठन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि वह देश की जनता का विश्वास जीत सके. लीबिया के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, मसलन ग़द्दाफ़ी समर्थकों का विश्वास हासिल करना, ताकि गृह युद्ध न हो, पश्चिम देशों के चंगुल से निकल कर स्वतंत्र विदेश नीति बनाना, युद्ध में हुई क्षति की भरपाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आदि. इनसे निपटने में नई सरकार कितनी सफल साबित होती है, यह तो समय बताएगा, लेकिन अगर असफल रहती है तो लीबिया में फिर से विद्रोह होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

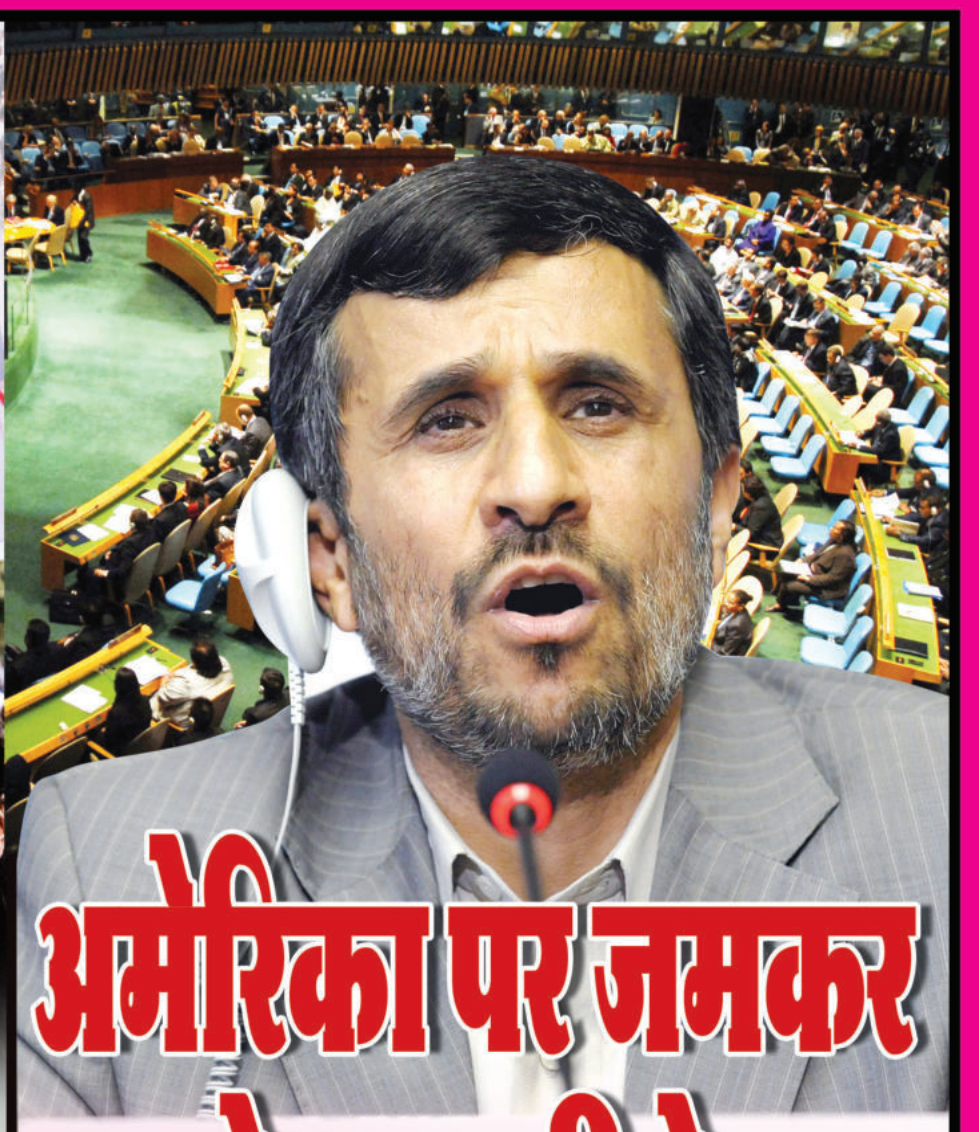

अमेरिका पर जमकर बरसे अहमदीनेजाद

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है. बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिला है. वे विश्व के 193 देशों के सामने अपनी बात कह रहे हैं. अपनी बारी आने पर ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने जो बातें कहीं, वे चौंकाने वाली तो नहीं थीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों के प्रतिनिधियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थीं. अहमदीनेजाद जब अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी के प्रतिनिधि हॉल से बाहर निकल गए. कनाडा और इजराइल के प्रतिनिधियों ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वे ईरानी राष्ट्रपति के भाषण के समय आए ही नहीं. अहमदीनेजाद ने अमेरिकी नीतियों की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि विश्व के सामने जो आर्थिक समस्या खड़ी है, उसकी जड़ अमेरिकी नीतियां हैं. अमेरिका अपनी सेना पर बेहिसाब ख़र्च करता है और डॉलर छापता जाता है, इसलिए विश्व में महंगाई बढ़ रही है. अहमदीनेजाद ने अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया और कहा कि जर्मनी, जापान और मध्य एशिया में वह अपना सैन्य एवं ख़ुफ़िया अड्डा बनाए हुए है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने अमेरिका की आतंकवाद संबंधी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि उस पर हुआ हमला रहस्यमय था. अमेरिका को अपने ऊपर हुए हमले के बाद एक विशेष जांच दल बनाना चाहिए था, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ओसामा को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराकर उसे मौत के घाट उतार दिया. अहमदीनेजाद ने दुनिया को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया और भौतिकवादी मानसिकता को आधुनिक समस्याओं की जड़ बताया. हालांकि ईरानी राष्ट्रपति नैतिक मूल्यों की बात सबके लिए कह रहे थे, लेकिन उनका इशारा अमेरिका की तरफ ज़्यादा था. ईरान–अमेरिका के बीच तनाव बहुत पहले से चल रहा है. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका की नज़रों पर चढ़ा हुआ है. उसने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और अन्य देशों पर भी उससे आर्थिक संबंध तोड़ने के लिए दबाव बनाता रहा. उसने भारत पर भी ईरान से गैस न लेने के लिए दबाव बनाया था. वह ईरान–पाकिस्तान गैस पाइप लाइन को भी रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है. अमेरिका ईरान पर आक्रमण करने की धमकी भी देता रहा है. ईरान भी अमेरिका पर दोषारोपण करने या उसे चुनौती देने का कोई मौका छोड़ता नहीं है. यूएन में भी उसे मौका मिला, जिसे वह नहीं गंवाया और अपनी भड़ास निकाल दी. कुछ दिनों पहले उसने 2000 किलोमीटर रेंज वाली 14 मिसाइलों का परीक्षण किया. ईरान के एक सेनाधिकारी कमांडर आमिर अली हाजीजादा ने कहा कि इन मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है. अहमदीनेजाद को ईरानी जनता का समर्थन प्राप्त है और उनके ऊपर कुछ वैश्विक शक्तियों का भी हाथ है. ईरान का यह रुख़ तब तक बरक़रार है, जब तक अमेरिका उसे मौका दे रहा है. वरना संभव है कि उसका भी वही हश्र हो, जो इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान का हुआ है.

feedback@chauthiduniya.com

लीबिया में नाटो के सैनिक तैनात हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि जब तक ग़द्दाफ़ी के समर्थकों को पूरी तरह पराजित नहीं किया जाता, तब तक नाटो की कार्रवाई जारी रहेगी. डर तो इस बात का है कि कहीं लीबिया भी अफ़ग़ानिस्तान या इराक़ न बन जाए. विद्रोहियों की जीत के कुछ दिनों पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी लीबिया गए और वहां राष्ट्रीय अंतरिम परिषद के कार्यों की सराहना की.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

ऐसे ही एक बार साई बाबा के एक भक्त बाला गनपत शिंपी को मलेरिया हो गया. उन्होंने तरह-तरह की दवाएं लीं और उपचार कराए, पर उनका ज्वर हटता ही नहीं था. बीमारी असाध्य हो गई.

ॐ साई राम ॐ साई राम ॐ साई राम ॐ साई राम ॐ साई राम ॐ साई राम ॐ साई राम

साई की हर लीला में शिक्षा है

मामलतदार और डॉक्टर दोनों ही साई बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए. वहां पहुंचने पर डॉक्टर सबसे आगे चला और साई बाबा के पास पहुंच कर उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया. यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ. लोगों ने उस राम भक्त डॉक्टर से पूछा कि अपने विचार और निश्चय के विरुद्ध आपने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि आसन पर स्वयं भगवान श्रीराम पीत वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए और हाथों में धनुष-बाण लिए बैठे थे. उसने साई बाबा को बार-बार देखा तो उसे एक बार श्रीराम और दूसरी बार साई बाबा दिखाई देते थे. दोनों के दर्शन उसे एक के बाद एक, लगातार होते रहे.

अहमदनगर में दादा साहब नामक एक डॉक्टर था. वह भगवान श्रीराम का परम भक्त था. एक बार वह डॉक्टर अपने किसी मामलतदार मित्र के साथ शिरडी आया. मामलतदार साई बाबा का भक्त था. उसने डॉक्टर को साई बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद चलने को कहा. डॉक्टर बोला कि वह मुसलमान के सामने सिर नहीं झुकाएगा. उसने सुन रखा था कि साई बाबा मुसलमान हैं. मामलतदार ने उससे मस्जिद चलने का आग्रह यह कहते हुए किया कि साई बाबा को प्रणाम करने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा. डॉक्टर मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गया. मामलतदार और डॉक्टर दोनों ही साई बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए. वहां पहुंचने पर डॉक्टर सबसे आगे चला और साई बाबा के पास पहुंच कर उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया. यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ. लोगों ने उस राम भक्त डॉक्टर से पूछा कि अपने विचार और निश्चय के विरुद्ध आपने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि आसन पर स्वयं भगवान श्रीराम पीत वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए और हाथों में धनुष-बाण लिए बैठे थे. उसने साई बाबा को बार-बार देखा तो उसे एक बार श्रीराम और दूसरी बार साई बाबा दिखाई देते थे. दोनों के दर्शन उसे एक के बाद एक, लगातार होते रहे. वह हैरान हो गया. उसके मन से सब भेदभाव मिट गए और वह साई बाबा का भक्त हो गया. उसने कहा, यह मुसलमान नहीं हो सकता, यह तो परब्रह्म का योगावतार है.

ऐसे ही एक बार साई बाबा के एक भक्त बाला गनपत शिंपी को मलेरिया हो गया. उन्होंने तरह-तरह की दवाएं लीं और उपचार कराए, पर उनका ज्वर हटता ही नहीं था. बीमारी असाध्य हो गई. उनकी पत्नी और वह चिंतित रहने लगे. बाला जी गनपत शिंपी और उनकी पत्नी ने साई बाबा की शरण में जाने का निश्चय किया. दोनों शिरडी गए और साई बाबा के दर्शन कर उन्हें अपना कष्ट बताया. बाबा ने रोग से छुटकारा पाने का विचित्र उपाय बताया. उन्होंने तात्या कोते पाटिल को दही और भात लाने को कहा. वह ले आया. साई बाबा ने बाला गनपत शिंपी से कहा, दही और भात को मिला दो, बाहर लक्ष्मी मंदिर के पास जाओ और वहां एक काले कुत्ते को यह दही-भात खिला दो. काला कुत्ता तुम्हें मंदिर के पास मिलेगा. दही-भात लेकर पति-पत्नी लक्ष्मी मंदिर के पास गए. वहां उन्हें एक काला कुत्ता दिखाई दिया, जो उन दोनों को देखकर पूंछ हिलाने लगा. बाला जी गनपत शिंपी ने उस कुत्ते के सामने दही-भात रख दिया. कुत्ते ने खाया और खाते ही मुंह फेरकर जंगल में भाग गया. आश्चर्य है कि इसके बाद बाला जी गनपत शिंपी का मलेरिया ज्वर ख़त्म हो गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

भविष्यवाणी निरस्त

नाना साहब डेंगले नामक एक बड़े ज्योतिषी ने एक दिन बापू साहब बूटी से कहा, आज का दिन आपके लिए अशुभ और अनिष्टकारी है. आज आपके जीवन को खतरा है. यह भविष्यवाणी सुनकर बापू साहब बूटी बहुत बेचैन हो गए. नित्य की भांति जब वह साई बाबा का दर्शन करने मस्जिद में आए, तब बाबा ने उनसे कहा, यह नाना क्या कहता है? उसने आज तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी की है. तुम्हें घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसे बहादुरी से बता दो कि मौत तुम्हें नहीं ले जाएगी. उसी दिन शाम के समय जब बापू साहब बूटी शौच के लिए अपने शौचालय में गए, तब वहां उन्होंने एक काला विषैला सांप देखा. उन्होंने अपने नौकर को एक बड़ी लाठी लाने के लिए कहा. जब वह लाठी लेकर आया, तब उसने सांप को दूर जाते हुए देखा. सांप जल्दी ही ग़ायब हो गया. इस प्रकार साई बाबा ने ज्योतिषी डेंगले की भविष्यवाणी को निरस्त कर दिया. इसी तरह एक बार शामा के हाथ की कनिष्ठा उंगली में एक ज़हरीले सांप ने काट लिया और उसके शरीर में विष फैलने लगा. शिरडी में विठोबा का मंदिर था, जहां सर्प दंश का इलाज किया जाता था. कुछ लोग शामा को वहां ले जाना चाहते थे, पर शामा का एकमात्र सहारा तो साई बाबा ही थे. वह दौड़ता हुआ मस्जिद की ओर गया और मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा. तभी साई बाबा क्रोध से गरज उठे, उतर- उतर, दूर हट, नीचे उतर. यह सुनकर शामा सन्न रह गया. उसने सोचा कि मस्जिद और बाबा के चरण ही मेरे रक्षक हैं. जब बाबा ही भगा रहे हैं, तब मेरा कहां ठिकाना? उसके पैर वहीं जकड़ गए और वह खड़ा रह गया. पर सच्चाई कुछ और थी. वास्तव में साई बाबा ने सांप के जहर को दूर हट, नीचे उतर कहकर फटकारा था, न कि शामा को. साई बाबा कुछ ही क्षणों में शांत होकर ध्यान मग्न हो गए. यह देखकर शामा मस्जिद के भीतर जाकर उनके चरणों के पास बैठ गया. बाबा ने आंखें खोलीं और मधुर स्वर में बोले, शामा, डरो मत. तिल भर भी फ़िक्र मत करो. बाहर मत निकलना. शामा के घर चले जाने पर साई बाबा ने तुरंत तात्या कोते पाटिल और काका साहब दीक्षित को उसके घर यह निर्देश देकर भेजा कि जो इच्छा हो, वह खा सकता है. घर के भीतर इधर-उधर टहल सकता है, पर कभी भी लेटे और सोए नहीं. साई बाबा के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया गया और शामा को भयंकर ज़हरीले सर्पदंश से बचा लिया गया.

कुछ लोग शामा को वहां ले जाना चाहते थे, पर शामा का एकमात्र सहारा तो साई बाबा ही थे. वह दौड़ता हुआ मस्जिद की ओर गया और मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा. तभी साई बाबा क्रोध से गरज उठे, उतर- उतर, दूर हट, नीचे उतर. यह सुनकर शामा सन्न रह गया. उसने सोचा कि मस्जिद और बाबा के चरण ही मेरे रक्षक हैं. जब बाबा ही भगा रहे हैं, तब मेरा कहां ठिकाना?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरुष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

सप्तमी के दिन मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया जाता है. मूर्तियां बनाने में 12 से 14 घंटे तक लग जाते हैं. मूर्तियां बनाने के लिए बांस की खप्पिचयों के ऊपर लुगदी लगाकर चेहरा बनाया जाता है.

अनंत विजय

कमज़ोर संस्मरण, ढीला संपादन

लंबे समय तक कई अंग्रेजी अख़बारों के संपादक रहे एस निहाल सिंह ने अपनी संस्मरणात्मक आत्मकथा इंक इन माई वेन–अ लाइफ इन जर्नलिज्म में देश पर इंदिरा गांधी द्वारा थोपी गई इमरजेंसी पर लिखते हुए जय प्रकाश नारायण को रिलक्टेंट रिवोल्यूशनरी (अनिच्छुक क्रांतिकारी) कहा है. एक लेखक को शब्दों के चयन में सावधान रहना चाहिए और अगर वह दो दशकों से ज़्यादा समय तक संपादक रहा है तो यह अपेक्षा और बढ़ जाती है. कोई भी क्रांतिकारी अनिच्छुक नहीं हो सकता. क्रांति का पथ तो वह ख़ुद चुनता है तो फिर अनिच्छा कहां से? आगे निहाल सिंह लिखते हैं कि अगर इंदिरा गांधी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को हटाने और बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग मान लेतीं तो जेपी संतुष्ट हो जाते. मुझे लगता है कि निहाल सिंह ने जय प्रकाश नारायण के आंदोलन और उनके विजन को बेहद हल्के ढंग से लिया है और दिल्ली में बैठकर अपनी राय बनाई है. जय प्रकाश नारायण को समझने की भूल अक्सर लोग कर जाते हैं. निहाल सिंह भी उसी दोष के शिकार हो गए हैं. न तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को समझा और न जय प्रकाश के योगदान को. किस तरह से गुजरात के विद्यार्थियों ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया था और उनसे मार्गदर्शन की अपील की थी, यह सर्वविदित तथ्य है. निहाल सिंह की राय उसी तरह की है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन के मूड को महसूस किए बग़ैर लोग अन्ना पर टिप्पणी कर रहे हैं. जय प्रकाश नारायण के बारे में निहाल सिंह की चाहे जो राय हो, लेकिन गांधी ने कहा था, जय प्रकाश एक फकीर हैं, जो अपने सपनों में खोए रहते हैं. इसके अलावा 25 जून, 1946 को उन्होंने लिखा कि मैं जय प्रकाश की पूजा करता हूं. इसके बाद तो कुछ कहने को शेष रहता नहीं है.

लेखक मोरार जी देसाई से काफी प्रभावित लगते हैं. जब भी उनका कोई प्रसंग उठता है तो लेखक यह बताना नहीं भूलते हैं कि मोरार जी भाई बेहद शुद्धतावादी थे. जब वह प्रधानमंत्री थे तो उस वक़्त का एक दिलचस्प प्रसंग है, उस वक़्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा कि विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी और लेखिका नयनतारा सहगल को रोम में राजदूत बना दिया जाए, लेकिन मोरार जी भाई ने कहा कि राजदूत बनने से पहले नयनतारा को मंगत राय से शादी करनी होगी. मंगत राय और नयनतारा उस वक़्त लिव इन रिलेशनशिप में थे. नयनतारा ने यह बात मान ली, लेकिन दुर्भाग्य से मोरार जी भाई की सरकार ही गिर गई और वह राजदूत बन न सकीं. 27 अगस्त, 1978 को रविवार में संतोष भारतीय का एक लेख छपा था, जिसमें लिखा गया था, मोरार जी भाई का इतिहास एक अक्खड़ व्यक्तिवादी और परंपरावादी शुद्धता के आवरण को ओढ़े हुए एक जिद्दी आदमी का इतिहास रहा है. संतोष भारतीय ने उस लेख में तर्कों के आधार पर अपनी बात साबित भी की है, जबकि निहाल सिंह टिप्पणी करके निकल जाते हैं. शायद निहाल सिंह को यह मालूम हो कि जब जय प्रकाश नारायण देश के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शुमार हो चुके थे, उस वक़्त मोरार जी भाई अंग्रेजी सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे. वह मोरार जी देसाई से ऑबसेस्ड लगते हैं. क्यों? इस बात के संकेत भी इस किताब में हैं, लेकिन यह एक अवांतर प्रसंग है.

एस निहाल सिंह, पत्रकारिता जगत का एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम, एक ऐसा बड़ा संपादक, जिसने लंबे समय तक देश–विदेश में पत्रकारिता की. कई लोगों का कहना है कि उनके द्वारा लिखे को पढ़कर उन्होंने पत्रकारिता सीखी. अपने छात्र जीवन के दौरान मैंने भी द स्टेट्समैन में निहाल सिंह के कई लेख पढ़े थे. स्कूल में हमें यह बताया जाता था कि अगर अंग्रेजी अच्छी करनी है तो स्टेट्समैन के लेख पढ़ा करो. उस जमाने से एस

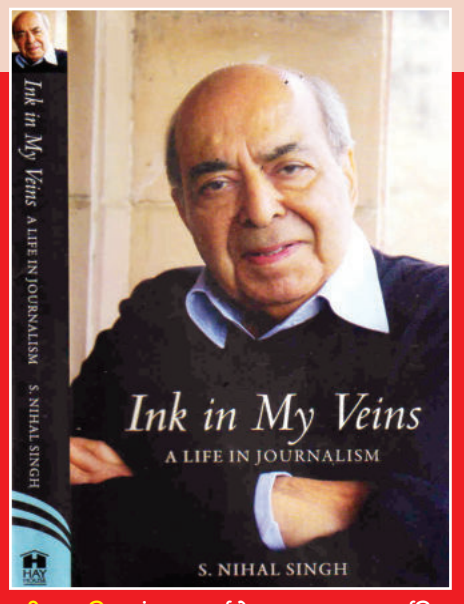

समीक्ष्य कृति : इंक इन माई वेन–अ लाइफ इन जर्नलिज्म
लेखक : एस निहाल सिंह
प्रकाशक : हे हाउस पब्लिशर्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली
मूल्य : 499 रुपये

निहाल सिंह और उनके लेखन को लेकर मन में एक इज़्ज़त थी. इमरजेंसी के दौरान उनके और उनके अख़बार के स्टैंड के बारे में पढ़कर यह इज़्ज़त और बढ़ गई थी. उनका कुछ भी लिखा मैं हुलस कर पढ़ता था. मैंने निहाल सिंह की किताब इंक इन माई वेन–अ लाइफ इन जर्नलिज्म इस उम्मीद से पढ़नी शुरू की कि उन्होंने आज़ादी के बाद देश की राजनीति को परखा होगा और कुछ नए तरीक़े से उस कालखंड को व्याख्यायित भी किया होगा. पाठकों की भी यही अपेक्षा रही होगी कि निहाल सिंह देश की राजनीति के अपने कुछ ऐसे अनुभवों को लिखेंगे, जो अब तक सामने नहीं आए थे, लेकिन पाठकों को इस किताब से घोर निराशा होगी, मुझे भी हुई.

निहाल सिंह ने अपनी इस किताब को संस्मरणात्मक आत्मकथा बना दिया है, जिस वजह से इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन पाया है. इस किताब के बहुत से पन्ने उन्होंने अपने, अपने परिवार और अपने परिवेश के बारे में निहायत ग़ैर ज़रूरी विवरणों से भर दिए हैं. अब पाठकों को इन बातों से क्या लेना–देना कि आपका पहला सेक्स एनकाउंटर किससे हुआ और उसने आपके अंगों की तुलना किन प्रतीकों से की. पाठक की इस बात में क्यों रुचि होगी कि लेखक बचपन में इतने ख़ूबसूरत थे कि स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला उन्हें गुलाब (द रोज) कहकर पुकारता था. इस तरह की कई बातें इस किताब में भरी पड़ी हैं. तक़रीबन तीन सौ पन्नों की इस किताब में लगभग डेढ़ सौ पन्नों में निहाल सिंह के निहायत निजी और पारिवारिक प्रसंग हैं, जिनमें उनकी अमेरिका यात्रा, मास्को प्रवास के संस्मरण, खलीज टाइम्स के दौरान उनका रहन=सहन, दिल्ली की पार्टियों में शराब और शबाब के किस्से आदि शामिल हैं. किताब के प्राक्कथन में निहाल सिंह लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में लिखता है तो उसे यह विश्वास होता है कि उसका लेखन उसके परिचितों और मित्रों से अलग एक वृहत्तर समुदाय के लिए रुचिकर होगा. इसके अलावा आत्मकथा लेखन में एक और बात होती है कि लेखक जीवन और मृत्यु के अपने दर्शन के बारे में भी अपना मत प्रकट करता है. हो सकता है कि निहाल सिंह यह सोच रहे हों कि उनकी इस आत्मकथा में वृहत्तर पाठक वर्ग की रुचि होगी, लेकिन उनकी इस सोच को अगर वस्तुनिष्ठता की कसौटी पर कसेंगे तो कम से कम आधी सोच ग़लत साबित होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि निहाल सिंह की इस आत्मकथा को पूरे तौर पर ख़ारिज कर दिया जाए. जब भी निहाल सिंह अपनी व्यक्तिगत चीजें छोड़कर राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम पर आते हैं तो किताब पटरी पर लौटती नज़र आती है. इमरजेंसी की घटनाओं पर निहाल सिंह ने विस्तार से लगभग एक पूरा अध्याय लिखा है. इस अध्याय में निहाल सिंह ने इंदिरा गांधी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कई जगहों पर बेहद संजीदगी से टिप्पणी की है. इंदिरा गांधी के साथ अपनी मुलाक़ात का जिक्र भी किया है. जिक्र तो अतुल्य घोष, एस के पाटिल से लेकर बाबू जगजीवन राम तक का है, लेकिन निहाल सिंह की इस किताब में दो अध्याय अहम हैं, द इमरजेंसी और इंदिराज पॉलिटिकल रिबर्थ. अहम इस वजह से कि इसमें लेखक के अपने कुछ विचार सामने आते हैं. इसके अलावा जो अन्य अध्याय हैं, उनमें सामान्य बातें हैं. दूसरी जो कमज़ोरी इस किताब की है, वह यह कि इसके लेखों में तारतम्यता का अभाव है. लंबे समय तक संपादक रहे निहाल सिंह की किताब को संपादन की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि कई जगह घटनाएं गड्डु–मड्डु हैं, आगे–पीछे आती–जाती है, जो पाठकों को कन्फ्यूज़ करती हैं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

नंदा देवी महोत्सव

हर तरफ़ मां के जयकारे की गूंज

विनीता यशस्वी

उत्तराखंड के कई हिस्सों में नंदा देवी का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है. नैनीताल में भी इस वर्ष 108वां उत्सव मनाया गया. ऐसी मान्यता है कि कंस ने जब देवकी की आठवीं संतान को मारने के लिए उसे उठाया तो वह ग़ायब हो गई और हिमालय में जाकर बस गई. उसी को बाद में नंदा के नाम से जाना गया. इसीलिए हिमालय की इस 7816 मीटर ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी चोटी पड़ गया. यह उत्सव भादों के महीने में पंचमी से दशमी तक मनाया जाता है, जिसके लिए पहले मां को पारंपरिक लोक गीतों के साथ निमंत्रण दिया जाता है. फिर नज़दीक के किसी एक गांव का चयन किया जाता है और पंचमी के दिन वहां जाकर केले का एक पेड़ छांटा जाता है. पेड़ का चयन भी कुछ विशेष नियमों के तहत किया जाता है. षष्ठी के दिन केले के पेड़ की वैदिक विधि से पूजा की जाती है और उसे नगाड़े और बैंड बाजे के साथ पूरे शहर में घुमाया जाता है.

सप्तमी के दिन मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया जाता है. मूर्तियां बनाने में 12 से 14 घंटे तक लग जाते हैं. मूर्तियां बनाने के लिए बांस की खप्पिचयों के ऊपर लुगदी लगाकर चेहरा बनाया जाता है. फिर रंगा हुआ कपड़ा चिपका कर आंख, नाक और मुंह को उभारा जाता है. केले के पेड़ की डंडियों को साफ करके उसके सफेद कपड़े में इन चेहरों को लपेटा जाता है और फिर उसके सहारे मूर्तियों को खड़ा किया जाता है, जो इसका सबसे अहम कार्य होता है. जब ये सारे कार्य हो जाते हैं तो उसके बाद मूर्तियों को गहनों से सजाया जाता है और उन्हें डोलों में रख दिया जाता है. मूर्तियां बनाने वाले कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य करते चले आ रहे हैं और इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं. ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों के चेहरे का आकार नंदा देवी चोटी से मेल खाता हुआ दिखता है. हालांकि नैनीताल में बनाई जाने वाली मूर्तियों में अब काफी बदलाव आ गया है, पर कुछ स्थानों पर आज भी पारंपरिक तरीक़े से ही मूर्तियां बनाई जाती हैं. अष्टमी के दिन पूजा करके मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है. यह पूजा सुबह चार बजे से शुरू हो जाती है. उसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है. मूर्तियां कुछ दिनों तक मंदिर में ही रहती हैं. इस दौरान कई जगह शस्त्र पूजा भी की जाती है और मंदिर में प्रतिदिन एक बकरे की बलि दी जाती है. पहले से भैंस की बलि दी जाती थी, पर अब उसे बंद कर दिया गया है. अंतिम दिन मूर्तियों की पूजा करके उनका डोला पूरे शहर में घुमाया जाता है और शाम को उनकी पूजा करके उन्हें झील में विसर्जित कर दिया जाता है. इसके साथ ही उत्सव का भी समापन हो जाता है. इस दौरान एक मेला भी लगता है, जिसमें बाहर से आए व्यापारी भी अपनी दुकानें लगाते हैं. कई दुकानदार तो ऐसे होते हैं, जो साल भर जगह–जगह के मेलों में जाकर ही दुकानें लगाते हैं और अपनी आजीविका इसी तरह चलाते हैं. नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, भवाली, चंपावत एवं रानीखेत आदि में भी यह उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है. अल्मोड़ा में यह उत्सव लगभग साढ़े तीन सौ साल से मनाया जा रहा है.

किताब मिली

पुस्तक का नाम
हिन्दी भाषा का वृहत् ऐतिहासिक व्याकरण

लेखक
हजारी प्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
750 रुपये

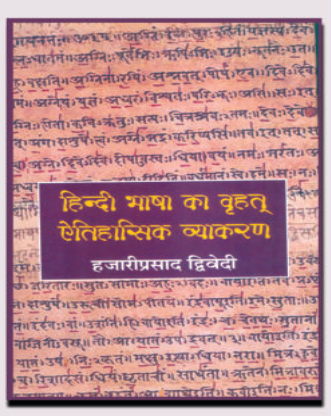

इस किताब में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की सोदाहरण व्याख्या करते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली–110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई–मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

यह यूजर फ्रेंडली है और बटन के इस्तेमाल से चलता है. जेबरस्टेशन लाइट सफेद और काले रंग में उपलब्ध है. इसमें इनबिल्ट बैट्री है, जो यूएसबी के ज़रिए चार्ज की जा सकती है.

बॉश के घरेलू उपकरण अब भारत में

बीएसएच बॉश और सीमेंस होम अप्लाएंसेज, जो विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है, ने अपनी सहायक कंपनी बीएसएच होम अप्लाएंसेज की ओर से भारत में बॉश होम अप्लाएंसेज लांच करने की घोषणा की. इस मौक़े पर बॉश के घरेलू उपकरणों की नई रेंज पेश की गई, जिसमें वाशिंग मशीन, डिशवाशर, रेफ्रिजरेटर एवं ड्रॉयर आदि शामिल हैं. समूह की रिटेल विस्तार रणनीति के रूप में बॉश के घरेलू उपकरण पूरे भारत में दो चरणों में उपलब्ध कराए जाएंगे. भारत में आरंभिक रेंज तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं दिल्ली-एनसीआर में अग्रणी मल्टी ब्रांड रिटेलर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. दूसरे चरण में ये उत्पाद पूरे भारत में उपलब्ध कराए जाएंगे. बीएसएच होम अप्लाएंसेज के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक मार्क हैंशर ने कहा, बॉश होम अप्लाएंसेज की लांचिंग करके हम भारत के घरेलू उपकरण क्षेत्र में एक नई कारोबारी रौनक ला रहे हैं, जो एशिया में हमारे प्रमुख बाज़ारों में से एक है. मार्क हैंशर ने कहा कि बॉश होम अप्लाएंसेज को भारत में लांच करते हुए विश्व के सर्वोत्तम उपभोक्ता उपकरण पेश करना हमारा ध्येय है, जो अपनी गुणवत्ता और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए विख्यात हैं और युवा एवं श्रेष्ठता पसंद भारतीय वर्ग को व्यापक रूप से लुभा सकें. भारत में बिजली और जल की मांग तेजी से बढ़ी है, इसलिए आज ऊर्जा कुशल उपकरणों की आवश्यकता प्रबल हो गई है. हैंशर ने कहा कि बॉश के सभी उत्पादों में कार्यकुशलता, शुद्धता, गुणवत्ता और बेजोड़ सहूलियत का तालमेल है. बॉश होम अप्लाएंसेज को बाज़ार में उतारने से पहले उनके टिकाऊपन और कार्यकुशलता का समुचित कठोर परीक्षण किया जाता है. हमने यह कभी मंजूर नहीं किया कि किसी के द्वारा हमारे किसी भी उत्पाद का परीक्षण किए जाने पर इसमें कोई कमी पाई जाए. इसी कारण हमने ऐसे उत्पाद बनाने के प्रयास किए, जो सूक्ष्म निरीक्षण में भी स्वयं को साबित कर सकें.

भारत में आरंभिक रेंज तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं दिल्ली-एनसीआर में अग्रणी मल्टी ब्रांड रिटेलर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. दूसरे चरण में ये उत्पाद पूरे भारत में उपलब्ध कराए जाएंगे. बीएसएच होम अप्लाएंसेज के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक मार्क हैंशर ने कहा, बॉश होम अप्लाएंसेज की लांचिंग करके हम भारत के घरेलू उपकरण क्षेत्र में एक नई कारोबारी रौनक ला रहे हैं, जो एशिया में हमारे प्रमुख बाज़ारों में से एक है.

बॉश होम अप्लाएंसेज इंडिया

बीएसएच होम अप्लाएंसेज इंडिया बीएसएच बॉश एंड सीमेंस होम अप्लाएंसेज (बीएसएच) ग्रुप की एक सहायक कंपनी है. बीएसएच बॉश और सीमेंस हॉजगेरेट जीएमबीएच यूरोप में घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी कंपनियों में से हैं. 1967 में रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच (स्टटगार्ट) और सीमेंस एजी (म्यूनिख़) के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में एक ग्रुप स्थापित किया गया, जिसकी सालाना बिक्री वर्ष 2010 में 9,073 बिलियन यूरो रही. वर्तमान में बीएसएच यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया के 13 देशों में स्थित अपनी 41 फैक्ट्रियों के माध्यम से अपने उत्पाद निर्मित करती है. बीएसएच घराने में 46 देशों की लगभग 70 कंपनियां हैं, जिनमें लगभग 43,000 लोग काम करते हैं.

ओटकर म्युसेली के नए वैरिएंट

डॉ. ओटकर द्वारा हाल में जर्मनी के नंबर 1 म्युसेली ब्रांड विटालिस के चार क्रंची वैरिएंट पेश किए गए हैं, रेजिंस एंड हनी, चॉकलेट ग्रैनोला, हनी एंड कॉर्नलेक्स और ओट्स, जो सीधे जर्मनी से मंगवाए गए हैं. यूरोप की भोजन शैली के सबसे बड़े संरक्षकों में एक और दुनिया के 50 से अधिक देशों में मौजूद डॉ. ओटकर द्वारा पेश विटालिस म्युसेली के 375 ग्राम पैक की क़ीमत 189 रुपये है और यह पैकिंग से 13 महीने तक उपयोग किया जा सकता है. यह 7 मुख्य महानगरों-दिल्ली एवं एनसीआर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरू की चुनिंदा रिटेल चेन समेत स्थानीय दुकानों में भी उपलब्ध है. इसे दिल्ली में आयोजित एक ब्रेकफास्ट सेशन में बॉलीवुड के नामी कलाकार जिसेली मोंटेरियो ने डॉ. ओटकर इंडिया के प्रबंध निदेशक ओलिवर मिर्जा के साथ मिलकर पेश किया. जिसेली मोंटेरियो ने कहा, मैंने करियर की शुरुआत में पूरे यूरोप, विशेषकर जर्मनी में काम किया. ज़ाहिर है, मुझे एक मजेदार क्रंची म्युसेली के साथ दिन की शुरुआत करना सबसे अच्छा लगता है. चूंकि मेरे काम में भागदौड़ लगी रहती है, इस लिहाज़ से भी म्युसेली मेरे लिए एक आसान और अच्छा विकल्प बन गया है. मुझे इस बात की ख़ुशी है कि अब भारत में भी जर्मनी का डॉ. ओटकर विटालिस म्युसेली उपलब्ध है और मैं एक संपूर्ण ब्रेकफास्ट का आनंद लेने के लिए उत्साहित हूं. इस अवसर पर ओलिवर मिर्जा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत के ब्रेकफास्ट मार्केट में बहुत बदलाव आया है. आज शहरों की भागदौड़ की ज़िंदगी में ग्राहक ब्रेकफास्ट में सुविधा के साथ-साथ संपूर्ण ब्रेकफास्ट के सारे गुण चाहते हैं. यही वजह है कि ब्रेकफास्ट के पुराने मेन्यू धीरे-धीरे सप्ताहांत के मेन्यू बन रहे हैं. दिनोंदिन बढ़ती भागदौड़ में विशेषकर सुबह के समय लोगों के पास समय और ऊर्जा की कमी रहती है. चूंकि ब्रेकफास्ट हमारे आहार का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यह सुविधाजनक, स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट हो, जबकि पारंपरिक ब्रेकफास्ट में इन ख़ूबियों की कमी है. इसी कमी को दूर करना हमारा लक्ष्य है, ताकि ब्रेकफास्ट के प्रति लोगों का उत्साह बना रहे, वह भरपूर पोषण दे और लोगों को पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखे.

पैनासोनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मशहूर बॉलीवुड स्टार दीया मिर्जा.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

बीटेल का टच स्क्रीन मोबाइल

भारती इंटरप्राइजेज समूह की कंपनी बीटेल टेलीटेक ने टोटल टच स्क्रीन फोन बाज़ार में उतारा है. दूरसंचार और आईटी उत्पादों की वितरक इस कंपनी ने जीडी-470 नामक मॉडल लांच किया. डुअल सिम वाले इस फोन में कई नए एवं आकर्षक फीचरों के साथ ही भारतीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग राज्यों की कला, डिज़ाइन और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन का समावेश है. जीडी-470 भारत में 3300 रुपये में मिलेगा. बीटेल जीडी-470 में 2.8 इंच संपूर्ण टच मोबाइल डिवाइस है. इसमें 1000 एमएएच बैट्री डाली गई है, जो 2-4 घंटे का टॉक टाइम और 200 घंटों का स्टैंड बाई टाइम देती है. आकर्षक स्टाइलिश डिजायन, बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ-साथ ब्लुटुथ एवं वीडियो प्ले करने के लिए इसमें .3 जीपी, एवीआई, एमपी 4 फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाली 25 एफपीएस और एमपी थ्री प्ले बैक फैसिलिटी है. बीटेल जीडी-470 में 1.3 मेगा पिक्सल कैमरा एवं एमएम रेडियो है. इसकी मेमोरी 8 जीबी तक एक्सपेंडेबल है. जीडी-470 एक बेहतरीन गैजेट है. इंटरनेट ब्राउजिंग और गेमिंग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के तौर पर इसे मॉडम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जीडी-470 के साथ बीटल वर्ल्ड पैक भी ख़रीददारों को मिलता है. इसमें कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंफोटेनमेंट फीचर्स जैसे फेसबुक, स्नैप्टू, एमआईजी-33, याहू, आईबीबो, वीयूक्लिप, रॉयटर्स, हंगामा और पेंग्विन हैं. इस फोन में भारतीय कैलेंडर का भी फीचर है, जिससे यूजर्स आसानी से भारतीय व्रत-उपवास, पर्व-त्योहार की जानकारी ले सकते हैं. इस फोन की एक खासियत यह है कि इसे रिकॉर्डर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

रिको के नए प्रिंटर मॉडल एसपी 1210-एन, एसपी 1200-एसएफ और एसपी 1200-एस के लॉन्च के मौके पर कंपनी के एमडी और सीईओ.

जेबरोनिक्स का पोर्टेबल स्पीकर

भारत में कंप्यूटर एक्सेसरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपूर्ति करने वाली कंपनी टॉपनॉच इंफोट्रॉनिक्स ने अपने ब्रांड जेबरोनिक्स के तहत बैट्री से ऑपरेट होने वाला पोर्टेबल स्पीकर लांच किया है. साइज में छोटा होने के बावजूद इसके सिस्टम में गहरी बास और बढ़िया साउंड क्वालिटी है. इसका सबसे अनोखा पहलू यह है कि इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, मसलन एमएमसी/एसडी कॉर्ड या डाटा यूएसबी फ्लैश ड्राइव को प्लग इन करके आप अपने फेवरिट डिजिटल एमपी थ्री म्यूज़िक को सुन सकते हैं. इसके अलावा अपने सेलफोन या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसे स्पीकर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए इस स्पीकर के पैकेज के साथ ही ए/वी केबल दिया गया है. इस ख़ास स्पीकर का नाम जेबस्टेशन लाइट रखा गया है. इसमें बिल्ट इन एफएम रेडियो है, जिसमें आप अपनी पसंद के अनुसार स्टेशन सेट कर सकते हैं. एक आकर्षक सॉफ्ट ग्लो 7 इंच का एलसीडी डिस्प्ले यह दिखाता रहता है कि कौन सा रेडियो स्टेशन सुनाई दे रहा है और कौन सा गाना उस पर चल रहा है. यह यूजर फ्रेंडली है और बटन के इस्तेमाल से चलता है. जेबस्टेशन लाइट सफेद और काले रंग में उपलब्ध है. इसमें इनबिल्ट बैट्री है, जो यूएसबी के ज़रिए चार्ज की जा सकती है. इसे 3.5 एमएम स्टीरियो केबल कनेक्ट से मोबाइल फोन, एमपी थ्री प्लेयर्स एवं लैपटॉप के साथ जोड़ा जा सकता है. इसकी पैकिंग के साथ एक छोटा स्टैंड और पाउच भी हैं, जिससे आसानी से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है. अगर आप ईजी टू यूज एवं पोर्टेबल स्पीकर चाहते हैं, जो हैंडबैग या सूटकेस में आसानी से आ जाए तो यह जेबस्टेशन आपके लिए बेस्ट है. इसे बाज़ार में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 990 रुपये में ख़रीदा जा सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत ने पटौदी की अगुवाई में नौ टेस्ट मैच जीते. इससे पहले भारत विदेशों में हुए 33 में से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था.

जीत का ग़म और हार की ख़ुशी

फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

राजेश एस कुमार

जब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्वकप जीता था, तब न सिर्फ़ उसे पर्याप्त फीस मिल रही थी, बल्कि उस पर पूरे देश की राज्य सरकारों एवं उद्योगपतियों समेत कई लोगों ने ईनामों की बौछार कर दी थी. इस सबके बावजूद टीम इंडिया प्रबंधन द्वारा दी गई फीस से संतुष्ट नहीं थी. इसीलिए धोनी समेत कई खिलाड़ियों ने बाक़ायदा विरोध कर अपनी फीस बढ़वा ली. यह वाकया पिछले दिनों फिर से दोहराया गया, लेकिन इस बार इसे इंग्लैंड के हाथों सीरीज और इज़्ज़त दोनों गंवाने वाली धोनी की टीम ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और ग़रीब खेल हॉकी के खिलाड़ियों ने दोहराया. अब इन दोनों वाकयों का फ़र्क़ समझते हैं.

हॉकी के खिलाड़ियों को हर विदेशी दौरे के प्रति मैच के लिए महज़ 50 डॉलर यानी दो हज़ार रुपये और भारत में प्रति मैच 1800 रुपये मिलते हैं. वहीं हमारे होनहार क्रिकेटरों को एक टेस्ट मैच के लिए 7 लाख रुपये, एक वन डे के लिए 4 लाख रुपये और एक टी–20 मैच के लिए 2 लाख रुपये बतौर फीस मिलते हैं. यानी क्रिकेट और हॉकी के खिलाड़ियों की फीस में ज़मीन–आसमान का अंतर है. इसके अलावा अगर मौजूदा प्रदर्शन पर चर्चा की जाए तो हॉकी खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर आए हैं. इसके बावजूद खिलाड़ियों द्वारा फीस लेने से इंकार करने के बाद खेल मंत्रालय ने ईनाम की राशि बढ़ाई, जबकि इंग्लैंड में शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली क्रिकेट टीम को वहां खेले गए 4 टेस्ट, एक टी–20 और पांच वन डे मैच खेलने के लिए सालाना कांट्रैक्ट से मिलने वाली भारी–भरकम धनराशि के अलावा हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपये मैच की फीस के तौर पर दिए गए. यह तुलना इसलिए की गई, क्योंकि अगर क्रिकेट खिलाड़ी अपनी इस भारी–भरकम फीस के बावजूद अपनी फीस बढ़ाने की मांग कर सकते हैं तो पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर आई हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने अपनी फीस न लेने का फ़ैसला करके क्या ग़लत किया? ख़ैर, असली मामला यह है कि जब हॉकी के खिलाड़ियों ने फीस लेने से इंकार कर दिया और बाक़ी लोगों, जिनमें राज्य सरकारों से लेकर अन्य उद्योगपति भी शामिल हैं, ने टीम हॉकी को पुरस्कार देने की भरमार कर दी, तब केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने अचानक एक प्रेस कांफ्रेंस की और एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को बतौर ईनाम 1.5 लाख रुपये देने की घोषणा कर दी. ग़ौरतलब है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम ने प्रत्येक खिलाड़ी को 25–25 हज़ार रुपये का ईनाम लेने से इंकार कर दिया था. उन्होंने इस फ़ैसले पर नाराज़गी भी जताई थी. बाद में हर

NIMBUS
NIMBUS SPORT

तरफ़ से आलोचना होते देख अजय माकन ने यह कांफ्रेंस की. माकन के मुताबिक़, सरकार खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने में कभी पीछे नहीं रहेगी और इसमें संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. अब अगर ऐसा ही था तो फिर खिलाड़ियों को पहले 25 हज़ार रुपये देने की बात क्यों की गई? इसका जवाब भी माकन को देना चाहिए, क्योंकि 25 हज़ार और डेढ़ लाख में छह गुने का अंतर होता है. इस बदलाव से दो बातें निकल कर सामने आती हैं. पहली बात तो यह कि अगर खेल मंत्रालय के पास पहले से ही इतना पैसा था तो वह 25 हज़ार रुपये की मामूली रकम देकर शेष पैसों का क्या करना चाहता था? दूसरी बात यह कि अगर खिलाड़ियों ने पहले मिलने वाली राशि लेने से इंकार न किया होता तो क्या उनके हिस्से में डेढ़ लाख के बजाय सिर्फ़ 25 हज़ार रुपये ही आते यानी एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये हर खिलाड़ी के खाते से बचते. अब सवाल यह उठता है कि इतना सारा पैसा किसकी जेब में जाता? खेल मंत्रालय की बातों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नज़र आता है. कभी वह कहता है कि उसके पास टीम के खिलाड़ियों को देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और इसके पीछे वजह भी वह लाजवाब बताता है. उसके मुताबिक़, हॉकी क्रिकेट की तरह न तो पापुलर है और न हॉकी के मैचों के लिए बड़ी संख्या में स्पांसर मिलते हैं. अब आपको बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है. 15 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच भारतीय हॉकी महासंघ और निम्बस के संयुक्त तत्वावधान में विश्व सीरीज हॉकी खेली जाएगी. इसमें 140 भारतीयों समेत दुनिया भर के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे. इस सीरीज के प्रमोटर निम्बस स्पोर्ट्स का कहना है कि इसके पहले ही सत्र में खिलाड़ी 40 लाख रुपये से अधिक कमाई कर सकते हैं. यानिक कोलासो, जो निम्बस के मुख्य संचालन अधिकारी हैं, के मुताबिक़ हाल में मिली जीत के बाद इस सीरीज की अहमियत और बढ़ गई है. अब खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और देश में

हॉकी का स्तर मज़बूत होगा. ग़ौरतलब है कि इस सीरीज के साथ भारतीय हॉकी टीम के कप्तान राजपाल सिंह के अलावा अर्जुन हलप्पा, प्रभजोत सिंह, एड्रियन डिसूजा, भरत छेत्री, शिवेंद्र सिंह, रोशन मिंज और धनंजय महाडिक ने अनुबंध किया है. इसके अलावा दो साल का प्रतिबंध झेल रहे संदीप सिंह और सरदारा सिंह भी इससे जुड़े हैं. यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस सीरीज में ईनामी राशि साढ़े चार करोड़ रुपये है. अच्छी बात यह है कि इसमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को बराबर कमाने का मौक़ा मिलेगा. एक अच्छी बात जो स्पांसर न मिलने की बात को सिरे से नकारती है, वह यह कि हॉकी विश्वकप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की औसत टीवी रेटिंग भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट मैचों की रेटिंग के बराबर या उससे अधिक रही. अब अगर टेलीविज़न रेटिंग के स्तर पर भी हॉकी मैच इतने देखे गए तो फिर स्पांसर न मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. असल में अगर खेल मंत्रालय हॉकी की सही मार्केटिंग करे और खिलाड़ियों को उनका वाजिब मेहनताना दे तो विश्व सीरीज हॉकी भी आईपीएल की तरह मुनाफ़े वाली संस्था हो सकती है. आपको बता दें कि भारत में अगर क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा दर्शक हैं तो वे हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के हैं. किसी भी खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार ज़रूरी है. यह बात क्रिकेट पर भी पूरी तरह लागू होती है. लेकिन दु:ख से ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आता है कि हमारे देश में खिलाड़ियों को विश्व हॉकी जैसी प्रतिस्पर्धा जीतने के बाद भी उचित फीस के लिए तरसना पड़ता है. अब यह जीत का गम नहीं तो और क्या है? एक सवाल वर्षों के बाद भी जस का तस है कि इस राष्ट्रीय खेल की दुर्दशा के लिए आख़िर कौन ज़िम्मेदार है, इसके कर्ताधर्ता और सरकार या फिर कोई और?

rajeshy@chauthiduniya.com

एक था टाइगर

टाइगर के नाम से मशहूर देश के महान क्रिकेटर मंसूर अली ख़ान पटौदी का जन्म 5 जनवरी, 1941 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था. वह पटौदी रियासत के आख़िरी नवाब थे. उनके पिता इफ़्तिख़ार अली ख़ां पटौदी भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे. इसलिए यह कहना ग़लत न होगा कि क्रिकेट का शौक़ उन्हें विरासत में मिला, लेकिन 11 साल के मंसूर अली ने क्रिकेट खेलना शुरू भी नहीं किया था कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया. जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना शुरू किया तो 1961 में कार हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई. हालांकि इसके बाद भी उन्होंने पूरे जोश से क्रिकेट खेलना जारी रखा और अपने नेतृत्व कौशल का लोहा मनवाया. मंसूर अली को कप्तानी मिलने का वाक़या भी बेहद दिलचस्प है. जब मंसूर अली को कप्तानी सौंपी गई, तब टीम वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी. टीम के कप्तान नारी कांट्रेक्टर ज़ख्मी हो गए तो 21 साल के मंसूर अली को कप्तानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. तब वह सबसे कम उम्र के कप्तान थे. उनका यह रिकॉर्ड 2004 तक क़ायम रहा. साल 2004 में जिम्बाब्वे के तातैंडा तायबू ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. पटौदी ने 13 दिसंबर, 1961 को इंग्लैंड केख़िलाफ़ दिल्ली में 13 रन बनाए. 10 जनवरी, 1962 को इंग्लैंड केख़िलाफ़ टेस्ट का अपना पहला शतक लगाया. उन्होंने चेन्नई में 113 रन बनाए. 23 मार्च, 1962 को बारबडोस टेस्ट में भारत के लिए पहली बार कप्तानी की. 12–13 फ़रवरी, 1964 को करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी 203 नाबाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नई दिल्ली टेस्ट में खेली. फ़रवरी–मार्च, 1968 को ड्यूनेडिन टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार विदेश में 3–1 से सीरीज जीती. 23 जनवरी, 1975 को उन्होंने वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ करियर के अंतिम टेस्ट (मुंबई) की दोनों पारियों में 9–9 रन बनाए. ग़ौरतलब है कि वह देश के पहले ऐसे कप्तान थे, जिन्होंने विदेश में भारत को जीत दिलाई. भारत ने उनकी अगुवाई में नौ टेस्ट मैच जीते. इससे पहले भारत विदेशों में हुए 33 में से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने 1993 से 1996 तक आईसीसी मैच अंपायर की भूमिका निभाई. वह दो टेस्ट और दस वन डे मैचों में अंपायर रहे. उन्हें 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की संचालन परिषद में शामिल किया गया था, लेकिन दो साल बाद 2010 में उन्होंने यह पद छोड़ दिया. उन्होंने आनंद बाज़ार पत्रिका समूह की खेल पत्रिका स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एक दशक से भी ज़्यादा वक़्त तक संपादन किया. 2007 से बीसीसीआई के सलाहकार एवं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य पटौदी टीवी कॉमेंट्रेटर भी रहे. 2007 से इंग्लैंड–भारत के बीच पटौदी ट्रॉफी के लिए टेस्ट सीरीज खेली जाती है. पिछले दिनों आयोजित सीरीज में उनकी मौजूदगी में इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को यह ट्रॉफी दी गई थी. इंग्लैंड ने सीरीज 4–0 से जीती थी. 1968 में पटौदी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ख़िताब मिला. उन्हें 1996 में अर्जुन अवॉर्ड और पद्मश्री से नवाज़ा गया. उन्होंने फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की. उनके पुत्र सैफ़ अली ख़ान और एक बेटी सोहा अली ख़ान भी फिल्म जगत में नाम कमा रहे हैं. उन्होंने सियासत में भी क़िस्मत आज़माई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव 1971 में हरियाणा के पटौदी स्टेट से लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने 1991 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नहीं मिल पाई. तरक़्क़ी पसंद मंसूर अली ख़ान पटौदी ने 2008 में अपनी बेटी सोहा अली ख़ान को अपनी जागीर की मस्जिद, मज़ार, यतीमख़ाने और वक़्फ़ की जायदाद का नायब मुतवल्ली बनाया. उनकी रियासत में पिछली ढाई सदी से महिलाओं का ही वर्चस्व रहा है. उन्होंने भी अपनी बेटी को यह ज़िम्मेदारी सौंपकर इसे जारी रखा. बीते 22 सितंबर को उनका निधन हो गया. अगले दिन हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के गांव पटौदी में उन्हें सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया.

फ़िरदौस ख़ान
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 03 अक्टूबर–09 अक्टूबर 2011

नीलांबरी श्रीलंका की नॉर्थ- ईस्ट प्रोविंशियल काउंसिल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं तमिल नेता वरदाराजा पेरूमल की बेटी हैं.

क्या करें रणबीर

ऋषि और नीतू उसी होटल में ठहरे हुए थे, जहां रॉक स्टार की यूनिट रुकी हुई थी. निर्देशक इम्तियाज से बात करते हुए दोनों की निगाह दूर बैठी एक ख़ूबसूरत लड़की पर गई, जो किसी से बात कर रही थी. उसकी सुंदरता से दोनों प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इतनी ख़ूबसूरत लड़की को तो बॉलीवुड में होना चाहिए.

ऋषि कपूर और नीतू सिंह दिल्ली में अपने बेटे रणबीर कपूर से मिलने आए, जो फिल्म रॉक स्टार के लिए शूटिंग कर रहे थे. ऋषि और नीतू उसी होटल में ठहरे हुए थे, जहां रॉक स्टार की यूनिट रुकी हुई थी. निर्देशक इम्तियाज से बात करते हुए दोनों की निगाह दूर बैठी एक ख़ूबसूरत लड़की पर गई, जो किसी से बात कर रही थी. उसकी सुंदरता से दोनों प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इतनी ख़ूबसूरत लड़की को तो बॉलीवुड में होना चाहिए. इस पर इम्तियाज ने उस लड़की को पास बुलाकर ऋषि–नीतू से परिचय कराया और बताया कि यह नरगिस फखरी हैं, रॉक स्टार की हीरोइन. जब यह किस्सा रणबीर को बताया गया तो वह देर तक हंसते रहे. फिल्म रॉक स्टार में अपनी भूमिका के लिए अभिनेता रणबीर कपूर जी–तोड़ मेहनत कर रहे हैं. वास्तविकता का पुट देने के लिए उन्होंने गाय दुहना भी सीखा. रॉक स्टार में अपने किरदार में जान डालने के लिए रणबीर ने हाल में एक जाट परिवार के यहां दिन गुजारा. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में वह एक हरियाणवी छोरे की भूमिका में दिखेंगे, जो जाट परिवार में पलता–बढ़ता है. फिल्म में रणबीर परंपरागत जाट परिवार के सबसे छोटे बेटे जनार्दन जाखड़ की भूमिका में दिखेंगे. एक शख्स का कहना है कि इम्तियाज और रणबीर ने दिल्ली के बाहरी इलाक़े में बसे एक परिवार के साथ पूरा दिन गुजारा. इस दौरान वे परिवार के छोटे बच्चों के साथ भी घुल–मिल गए. दोनों खाट पर सोए, स्थानीय ढाबे पर खाना खाया और शाम को हुक्के का भी मज़ा लिया.

सब समझ गईं कल्कि

देव डी से बॉलीवुड में प्रवेश करने वाली कल्कि कहती हैं, मैंने इन दो सालों में एक अभिनेत्री के तौर पर काफी मेहनत की है और मुझमें बदलाव भी आ चुके हैं. देव डी के समय काफी डरी-सहमी रहने वाली कल्कि ने बताया कि अब उन्होंने फिल्मों में अपने चरित्र से जुड़ना सीख लिया है.

अपनी ही फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स को देखकर हंसती हैं कल्कि कोचलीन, जबकि उनके पति और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप उनकी हिंदी में आए सुधार को देखकर प्रभावित हैं. हालांकि कल्कि को फिल्म में अपने पति के सामने कुछ अंतरंग दृश्य देते हुए कुछ शर्म भी महसूस हुई, लेकिन अपने काम को उन्होंने प्रोफेशनल मानते हुए सभी दृश्य बेहतरीन तरीक़े से शूट किए. अच्छी बात तो यह है कि अनुराग को इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई. कल्कि कोचलिन में पहले से काफी बदलाव आ चुके हैं. अब कल्कि ने सीख लिया है कि किस तरह पात्रों को चुना जाता है. उन्होंने अनुराग के साथ पहली बार देव डी में काम किया था. देव डी से बॉलीवुड में प्रवेश करने वाली कल्कि कहती हैं, मैंने इन दो सालों में एक अभिनेत्री के तौर पर काफी मेहनत की है और मुझमें बदलाव भी आ चुके हैं. देव डी के समय काफी डरी-सहमी रहने वाली कल्कि ने बताया कि अब उन्होंने फिल्मों में अपने चरित्र से जुड़ना सीख लिया है. अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वह निर्देशक से अपनी बातें शेयर करती हैं. अगर उन्हें लगता है कि वह अपने रोल में कुछ नया भी कर सकती हैं तो इस बारे में डायरेक्टर से ही बात कर लेती हैं. कल्कि ने देव डी के बाद शैतान, दैट गर्ल इन येलो बूट्स और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं और उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया.

मिनिषा की मुश्किल

फिल्म किडनैप में जमकर अंग प्रदर्शन कर चुकीं मिनिषा लांबा ने अपनी आने वाली कॉमेडी फिल्म हम तुम शबाना में बिकनी पहनने से इंकार कर दिया है. कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले के पीछे उनके नए दोस्त मुकुल देवड़ा हैं. मुकुल और मिनिषा की दोस्ती भेजा फ्राई के समय हुई थी और मुकुल ने इसी दोस्ती की ख़ातिर हम तुम शबाना के राइट्स भी ख़रीद लिए हैं. मिनिषा बताती हैं, मुझे इस फिल्म के एक सीन के लिए बिकनी पहनने को कहा गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया. मालूम हो कि मिनिषा ने फिल्म किडनैप में बिकनी पहन कर जमकर अंग प्रदर्शन किया था, जिसके चलते वह सुर्ख़ियों में आ गई थीं. सागर बल्लरी की आने वाली फिल्म हम तुम शबाना एक रोमांटिक कॉमेडी है. इस फिल्म में दो लड़के एक ही लड़की के पीछे पड़े रहते हैं. फिल्म में मिनिषा एक ऐसी लड़की के किरदार में नज़र आएंगी, जो मॉडल बनना चाहती है, लेकिन वह मॉडल बनने के किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाती और सौंदर्य प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है.

श्रीलंका की ब्यूटी का जलवा

इन दिनों हिंदी फिल्मों में श्रीलंका छाया हुआ है. पहले तो मिस श्रीलंका रह चुकी जैकलीन फर्नांडीज ने हिंदी फिल्मों में काम किया और अब श्रीलंका की दूसरी सुंदरी हिंदी फिल्मों में छाने के लिए तैयार है और वह हैं नीलांबरी पेरूमल, जो हिंदी फ़िल्म जीत लेंगे जहां में अभिनय कर रही हैं. अशोका मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फ़िल्म के निर्माता हैं संजू सिंह और निर्देशक हैं ललित एम एस बिष्ट. नीलांबरी श्रीलंका की नॉर्थ– ईस्ट प्रोविंशियल काउंसिल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं तमिल नेता वरदाराजा पेरूमल की बेटी हैं. वरदाराजा पेरूमल को लिट्टे की धमकी मिली थी और वह सुरक्षा कारणों से बहुत दिनों तक छिपे रहे थे. नीलांबरी ने इससे पहले एक मलयालम फ़िल्म बॉम्बे मित्तई में अभिनय किया है. एलएलबी की पढ़ाई कर चुकीं नीलांबरी दिल्ली में नाटक भी करती रही हैं. वह फ़िल्म जीत लेंगे जहां में सलोनी का किरदार निभा रही हैं, जो एक फैशन डिज़ाइनर है और अजय नामक युवक से प्यार करती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

रास्कल्स

दशहरे के अवसर पर बड़ी फिल्में रिलीज होने का रिवाज बॉलीवुड में वर्षों से चला आ रहा है. इस बार भी 6 अक्टूबर को फिल्म रास्कल्स रिलीज होने जा रही है. इसका निर्देशन किया है कई सुपरहिट फिल्म देने वाले डेविड धवन ने. डेविड यदि फिल्म के निर्देशक हैं तो उसमें कॉमेडी होना तय है. इसलिए रास्कल्स में भी हास्य के ढेर सारे मसाले हैं, जो दर्शकों को गुदगुदाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. फिल्म में कई स्टार्स हैं. संजय दत्त, अजय देवगन, कंगना, अर्जुन रामपाल, चंकी पांडे और सतीश कौशिक जैसे कलाकार आकर्षण का केंद्र हैं. संजय दत्त प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और रूपाली ओम एंटरटेनमेंट ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है. डेविड धवन की फिल्म रास्कल्स का जबसे ट्रेलर रिलीज हुआ है, तबसे यह लगातार चर्चा में बना हुई है. इसके कुछ सीन आउटडोर में शूट किए गए हैं. फिल्म के क्लाइमैक्स का एक महत्वपूर्ण सीन बैंकॉक हवाई अड्डे पर शूट किया गया. इसमें संजय दत्त और अजय देवगन कॉस्ट्यूम में ही रन–वे पर बाइक दौड़ाते हैं. कुछ सीन की शूटिंग होने के बाद क्रू मेंबर्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि उन्हें अपनी शूटिंग कुछ देर के लिए रोकनी होगी, क्योंकि एक चार्टर फ्लाइट उसी समय लैंड करने वाली थी. बैंकॉक एयरपोर्ट के अधिकारियों ने फिल्म की शूटिंग में उस समय काफी सहयोग किया, जब शूटिंग के लिए अनुमति ली गई. हालांकि चार्टर फ्लाइट के कारण शूटिंग कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी. साथ ही लैंड करने वाली फ्लाइट को उस समय तक हवा में चक्कर काटना पड़ा, जब तक उसे रन–वे पर लैंड करने के लिए क्लीयरेंस नहीं मिल गया. फिल्म में कंगना रानावत मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं. संगीत मशहूर संगीतकार विशाल शेखर ने दिया है, जबकि पटकथा यूनुस सजावल ने लिखी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 03 अक्टूबर-09 अक्टूबर 2011

www.chauthiduniya.com

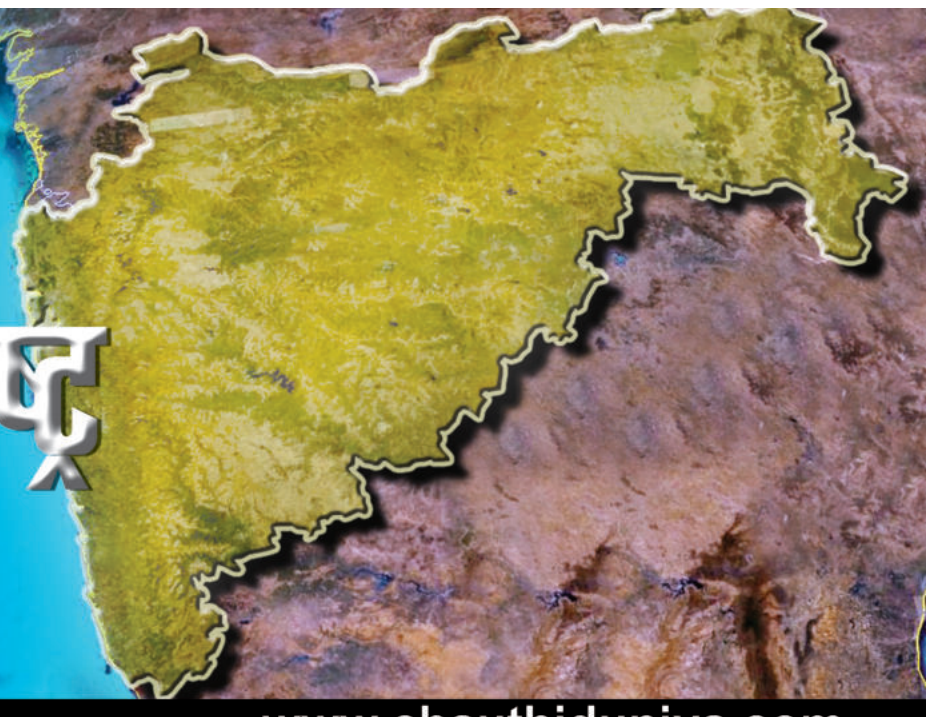

शिक्षण संस्थाओं ने अनुदान लूटा

राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने अनुदानित स्कूलों के फ़र्ज़ीवाड़े के चलते छात्र-छात्राओं के हित में बनाई गई योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान में मची लूट का ख़ुलासा किया. अकेले नादेड़ ज़िले में ही उन्होंने एक लाख 40 हज़ार फ़र्ज़ी विद्यार्थियों के होने की जानकारी दी. मुख्य सचिव गायकवाड़ ने कहा कि सितंबर माह में वह नांदेड़ गए थे. वहां उन्हें इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी मिली.

राजेश नामदेव

महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान की लूट मची है. राज्य सरकार बच्चों को शिक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के मक़सद से शिक्षण संस्थाओं को भरपूर राशि मुहैया कराती है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे संचालक उसे न केवल हज़म कर रहे हैं, बल्कि सरकार से अधिक से अधिक अनुदान कैसे प्राप्त किया जाए, इस जुगत में भी लगे रहते हैं. शिक्षा माफ़िया की वजह से राजस्व की काफ़ी क्षति हो रही है. इसके बावजूद सरकार शिक्षा माफ़िया के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. जब मामला चौराहों-चौपालों में चर्चा का विषय बनकर सार्वजनिक हो जाता है तो कुछ स्कूल संचालकों को नोटिस देकर कार्रवाई करने का दिखावा किया जाता है. समय गुज़रने के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और शिक्षा माफ़िया का कुछ नहीं बिगड़ता. क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ताधीशों का संरक्षण हासिल है. ख़ैर, इससे ज़ाहिर है कि महाराष्ट्र में शिक्षा माफ़िया की जड़ें कितनी गहरी हैं, जो करोड़ों के अनुदान हज़म करने के बाद भी क़ानून की नज़र से बचे रहते हैं. पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने अनुदानित स्कूलों के फ़र्ज़ीवाड़े के चलते छात्र-छात्राओं के हित में बनाई गई योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान में मची लूट का ख़ुलासा ख़ुद किया. अकेले नादेड़ ज़िले में ही उन्होंने एक लाख 40 हज़ार फ़र्ज़ी विद्यार्थियों के होने की जानकारी दी. मुख्य सचिव गायकवाड़ ने कहा कि सितंबर माह में वह नांदेड़ गए थे. वहां उन्हें इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी मिली. उनके मुताबिक़ फ़र्ज़ी छात्रों के नाम पर स्कूल संचालकों ने सरकारी ख़ज़ाने को 150 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. मुख्य सचिव के इस अहम ख़ुलासे के बाद सरकार की आंख खुली और मुख्यमंत्री ने तत्काल राज्य के 35 ज़िलों के सभी अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सही संख्या की जांच करने के आदेश जारी किए.

प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा सभी अनुदानित स्कूलों के छात्र-छात्राओं की गणना कराने की बात कह रहे हैं. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटिल ने भी कहा कि नांदेड़ ज़िला परिषद के स्कूलों में दो लाख विद्यार्थी, 3500 कक्षाएं और 45 शिक्षकों के फ़र्ज़ी होने की जानकारी सामने आई है. उनके मुताबिक़ इस मामले में शामिल तमाम सरकारी अधिकारियों व स्कूल संचालकों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि छात्रों की गणना के दौरान उनकी अंगुलियों पर मतदान करने के पश्चात लगने वाली स्याही का निशान लगाया जाएगा. वैसे यह मामला बेहद गंभीर और पेचीदगी से भरा है, लिहाज़ा सरकार के लिए अनुदानित स्कूलों में व्याप्त लूट को रोक पाना आसान नहीं लगता. मुख्य सचिव के ख़ुलासे के बाद सवाल उठता है कि आख़िर शासन-प्रशासन इस पूरे प्रकरण को नज़रअंदाज़ क्यों करता रहा? इसे रोकने के लिए उसने पहले ही कोई क़दम क्यों नहीं उठाया? जब यह बात मुख्य सचिव को बताई गई है तो इसका मतलब है कि नांदेड़ के शिक्षा अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को इस गोलमाल की पूरी जानकारी थी, फिर यह तथ्य नांदेड़ यात्रा के दरम्यान ही मुख्य सचिव को क्यों बताया गया? इस फ़र्ज़ीवाड़े के दोषियों व अनुदान के लुटेरे स्कूल संचालकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि पूरे प्रकरण पर ग़ौर किया जाए तो यह बात साफ़ हो जाती है कि इस फ़र्ज़ीवाड़े को संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता है. इसके अलावा सबसे बड़ा पेंच यह है कि अधिकांश अनुदानित स्कूल (फिर चाहे ज़िला परिषद हो या आश्रमशालाएं या मतिमंद बच्चों के स्कूल हों) राजनेताओं के हैं या उनके रिश्तेदारों या उनके ख़ास चहेतों के हैं. यही वह तथ्य है जो ईमानदार अधिकारियों द्वारा बेईमान स्कूल संचालकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान रोड़ा बनता है. इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, क्योंकि सत्ता मिलने पर वे अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने में पीछे नहीं रहते. ग़ौरतलब है कि आदिवासी विभाग में सचिव पद पर कार्यरत उत्तम खोब्रागड़े ने आश्रमशालाओं में मौजूद ख़ामियों को उजागर किया था. जिन आश्रमशालाओं में निर्धारित सुविधाओं का अभाव था, उन्हें नोटिस भी जारी किया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आश्रमशालाएं नेताओं व आदिवासी विभाग के अधिकारियों के लिए दुधारू गाय साबित हो रही हैं. इस सनसनीख़ेज़ ख़ुलासे के बाद तत्कालीन सरकार के सचिव उत्तम खोब्रागड़े का राजनीतिक दबाव के चलते स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन सरकारी अनुदान के लुटेरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि जब नांदेड़ ज़िले में ही 1 लाख 40 हज़ार विद्यार्थियों का नाम फ़र्ज़ी तरीक़े से दर्ज किया गया है तो राज्य के सभी 35 ज़िलों में क्या हालत होगी? बहरहाल, मुख्य सचिव के इस ख़ुलासे के बाद सरकार हरकत में आ गई है, लेकिन शासन की इस सक्रियता से शिक्षा माफ़िया के मंसूबे ध्वस्त होंगे या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है. ख़बरों के मुताबिक़ पूरे राज्य के अनुदानित स्कूलों में छात्रों की गणना और जांच होना अभी बाक़ी है. अगर इस जांच प्रकिया में पूरी तरह ईमानदारी बरती जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा माफ़िया शिकंजे में फंसेगा. वहीं इसके बरअक्स कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सत्ता गलियारे में शिक्षा माफ़िया की पहुंच होने की वजह से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला. सरकार बेशक इस मामले में फुर्ती दिखाए, लेकिन अंततः वह भी चुप बैठ जाएगी. मिसाल के तौर पर वर्धा ज़िले में कई बड़े नेताओं के शिक्षण संस्थानों में 50 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुआ, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई. अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया. इतना ही नहीं सर्वशिक्षा अभियान में भी हर साल करोड़ों रुपये की बंदरबांट होती है. ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी भनक नहीं है, लेकिन सबकुछ जानते हुए भी वह इस मामले में ख़ामोश है. मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को जो आहार परोसा जाता है, वह कितना पौष्टिक है? क्या राज्य सरकार ने इस बारे में जानने की कोशिश की है? इसके अलावा उन स्कूलों में बच्चों की ड्रेस, पुस्तक वितरण तक में गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. सभी को पता है कि केंद्र सरकार हर साल शिक्षा के मद में करोड़ों रुपये की धनराशि आवंटित करती है, लेकिन उन पैसों की इस तरह बंदरबांट शर्मनाक है. यह सवाल हर उस आम आदमी को परेशान करता है, जो यह सोचता है कि आख़िर महाराष्ट्र भ्रष्टाचार के मामले में इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? आख़िर महाराष्ट्र पूर्ण साक्षर राज्य क्यों नहीं हो सका है? यदि कोई ईमानदार अधिकारी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है. इन पस्थितियों में ईमानदार अधिकारी शिक्षा मठाधीशों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे, उससे पहले ही उसका मनोबल गिरा दिया जाता है. बहरहाल, सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का दावा चाहे जितना भी करे, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी कथनी और करनी में घोर अंतर है. वह जो करती है वह कहती नहीं और जो कहती है वह करती नहीं. प्रदेश के मुख्य सचिव ने सरकारी अनुदान से चल रहे स्कूलों में हो रही अनियमितता के बारे में सरकार को सूचित कर दिया, लेकिन सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है वह कुछ दिनों में पता चल जाएगा. इस सबके बावजूद सरकार यदि इस मामले की गंभीरतापूर्व जांच करे तो फ़र्ज़ी विद्यार्थियों और उनकी ड्रेस और किताबों पर ख़र्च होने वाले करोड़ों रुपये की लूट रोकी जा सकती है. यदि सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाए तो वह 400-500 करोड़ रुपये बचा सकती है. एक अनुमान के मुताबिक़ राज्य सरकार हर साल स्कूलों पर क़रीब 1400 करोड़ रुपये ख़र्च करती है. इसके अलावा सर्वशिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1800 करोड़ रुपये का अनुदान अलग से मिलता है, लेकिन शिक्षा माफ़िया की वजह से इन रुपयों की बंदरबांट हो रही है. यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस मामले को लेकर संजीदा हैं तो उन्हें कठोर फ़ैसले लेने पड़ेंगे. हालांकि, इस बात से सूबे के मुख्यमंत्री चव्हाण भी वाक़िफ़ हैं कि शिक्षण संस्थानों में चल रहे गोरखधंधे और अनुदान के लुटेरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में कौन लोग बाधा पैदा कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

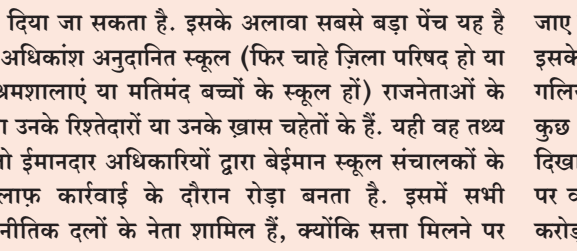

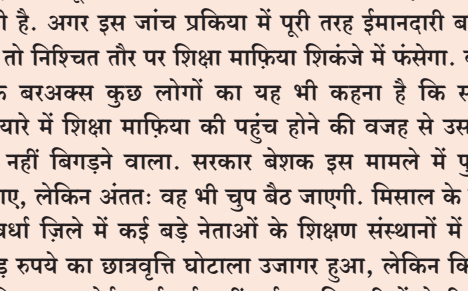

स्कूलों की संख्या और उनसे जुड़े ख़र्च

- राज्य में विद्यार्थियों की कुल संख्या- 2 करोड़ 16 लाख
- शालेय शिक्षा विभाग का वार्षिक व्यय - तक़रीबन 27,520 करोड़ रुपये
- प्राथमिक शाला- 75,466
- माध्यमिक शाला-19,767
- कनिष्ठ महाविद्यालय-7241
- स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूल- तक़रीबन 87 हज़ार
- दोपहर के भोजन पर होने वाला वार्षिक ख़र्च- लगभग 1400 करोड़ रुपये
- गणवेश संख्या- 1 करोड़ 22 लाख
- पाठ्य पुस्तकों की संख्या- 1 करोड़ 40 लाख
- पुस्तकों एवं गणवेश पर होने वाला ख़र्च- क़रीब 250 करोड़ रुपये

स्कूलों में बच्चों की ड्रेस व पुस्तक वितरण तक में गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. सभी को पता है कि केंद्र सरकार हर साल शिक्षा के मद में करोड़ों रुपये की धनराशि आवंटित करती है, लेकिन उन पैसों की इस तरह बंदरबांट शर्मनाक है. यह सवाल हर उस आम आदमी को परेशान करता है , जो यह सोचता है कि आख़िर महाराष्ट्र भ्रष्टाचार के मामले में इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? आख़िर महाराष्ट्र पूर्ण साक्षर राज्य क्यों नहीं हो सका है? यदि कोई ईमानदार अधिकारी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है.

उन्होंने बेशक कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, लेकिन हक़ीक़त यह भी है कि कांग्रेस शब्द से उनका मोह ख़त्म नहीं हुआ. उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखा.

जो ग़रीब हैं, वे इस बीमारी पर उतना ख़र्च नहीं कर पाते. आख़िर सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी क़दम क्यों नहीं उठाती?

रिपब्लिकन गवई ने कांग्रेस को चेताया

डॉ. राजेंद्र गवई

निशा वर्मा

राज्य में एक ओर स्थानीय निकाय के चुनावों की आहट आने लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से उसके सहयोगियों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है. यदि यही हाल रहा तो महानगर पालिका व ज़िला परिषद के चुनावों में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. वैसे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस लगातार अड़ंगे डाल रही है और अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ग.) ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर स्थानीय निकाय के चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है. पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस से इसलिए नाराज़ है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे उससे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं. दरअसल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राज्य नेतृत्व कांग्रेस द्वारा उसके साथ अब तक सत्ता की भागीदारी नहीं किए जाने से नाराज़ चल रहा है.

पिछले दिनों नागपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजेंद्र गवई ने कांग्रेस के रवैये के प्रति असंतोष ज़ाहिर करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस उनकी पार्टी को जल्द से जल्द राज्य सरकार में मंत्री पद देने का वादा पूरा नहीं करती है तो हम उससे अलग हो जाएंगे. उनका कहना था कि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने हमारे साथ सत्ता की भागीदारी करने का वादा किया था और इसके तहत राज्य मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी को जगह देने की बात तय हुई थी, परंतु कांग्रेस ने अब तक अपने इस वादे को नहीं निभाया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी आश्वासन दिया था कि रिपाई कार्यकर्ताओं को मंडलों-महामंडलों में शामिल किए जाने का मौक़ा दिया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किया, पर उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया. पचास फ़ीसदी मंत्रियों ने आदेश पर अमल नहीं किया. इसलिए हमारे कार्यकर्ता अब ऐसे मंत्रियों का घेराव करेंगे और आदेश पर अमल करने के लिए दबाव बनाएंगे. डॉ. गवई ने स्पष्ट किया कि नागपुर सहित राज्य की पांच महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं. यह चुनाव पार्टी अपने दम पर लड़ेगी. हमारी इच्छा है कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार का कारण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बने. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुंबई में चैत्य भूमि के लिए साढ़े पांच एकड़ ज़मीन देने का आश्वासन दिया था. उनका वह आश्वासन मात्र कोरा आश्वासन ही साबित हुआ है. उसे पूरा करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की हमारी मांग है. इसके लिए सरकार की ओर से विधानसभा में विधेयक पेश करने की पहल होनी चाहिए. मगर अब तक हमारी किसी भी मांग की ओर सरकार व कांग्रेस ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है. कांग्रेस द्वारा रिपब्लिकन पार्टी के प्रति मिल रही उपेक्षा पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए डॉ. गवई ने बताया कि सोनिया गांधी से मुलाक़ात करने और उनके आश्वासन के बाद ही कांग्रेस के साथ आने का फ़ैसला हमने किया था, लेकिन कांग्रेस से पार्टी को कुछ ख़ास नहीं मिला. रिपब्लिकन पार्टियों की स्थिति और बिखराव पर उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी जोगेंद्र कवाड़े व रामदास अठावले से किसी तरह की मदद नहीं लेगी. रही बात रिपब्लिकन एकता की तो रामदास अठावले और प्रकाश आंबेडकर कभी एक नहीं हो सकते हैं. हां, यदि दोनों जिस दिन एकजुट होते हैं और एकता को मज़बूत किया जाता है तो उसके साथ जुड़ने वाला मैं तीसरा व्यक्ति रहूंगा. फ़िलहाल रिपब्लिकन एकता के संकेत कहीं दिखाई नहीं देते हैं.

दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग हो. जो मांग राजेंद्र गवई ने की है, पार्टी के नेताओं से चर्चा कर उसे पूरा किया जाएगा. उनसे किए गए वादे 100 फ़ीसदी पूरे किए जाएंगे. हमारे बीच जो भी मतभेद या ग़लतफ़हमी है उसे शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा. जहां तक बात स्वतंत्र चुनाव लड़ने की है, यह उनका अधिकार है. उस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं. जहां तक हमारी बात है तो हम चाहते है कि गवई हमारे साथ रहे ताकि मतों के विभाजन का लाभ किसी अन्य को न मिले. अब देखना यह कि गवई की मांगें कांग्रेस कब तक पूरी करती है. कांग्रेस को सत्ता में रिपाई को भागीदारी अपने ही कोटे से देनी पड़ेगी, मगर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पार्टी के ही कई नेता कतार में हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकार के निशाने पर अन्ना

राजधानी दिल्ली में अन्ना हज़ारे अपना अनशन ख़त्म करने के बाद अपनी कर्मभूमि रालेगण सिद्धि गांव में रह रहे हैं. इसी गांव में पिछले दिनों अन्ना के सहयोगी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए यहां एकत्र हुए थे. यहां अन्ना हज़ारे ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जमकर निशाना साधा. सरकार की ओर से अन्ना को जेड श्रेणी सुरक्षा देने की पेशकश की गई थी, जिसे अन्ना ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था. हालांकि लोग क़यास लगा रहे थे कि सरकार जेड सुरक्षा के बहाने अन्ना की निगरानी करना चाहती है.

महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है. यहां विकास कार्य ठप्प पड़े हैं और राज्य में अकाल की छाया मंडरा रही है. क़र्ज़ में डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला जारी है. इसके बावजूद इसकी रोकथाम के उपायों के नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं. महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह परेशान है. इसके अलावा प्रदेश की जनता आतंकी हमलों के साए में जीने को विवश है, लेकिन सरकार इन विषयों की ओर ध्यान नहीं दे रही है. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बजाय सरकार उस शख्स की कमज़ोरियां खंगाल रही है, जिसने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने को प्रेरित किया. उस शख्स का नाम अन्ना हज़ारे है जिनकी एक आवाज़ पर लोगों ने अपने घरों से निकलकर जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग की. जनदबाव के कारण आख़िरकार केंद्र सरकार को अन्ना हज़ारे के समक्ष झुकना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार अब अन्ना के ख़िलाफ़ साज़िश करने में जुटी है. हालत यह है कि रालेगण सिद्धि जो अन्ना का पैतृक गांव है, वहां इन दिनों जासूसों का जमावड़ा हो गया है. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी टीम अन्ना को संविधान विरोधी क़रार दिया है.

ग़ौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में अन्ना हज़ारे अपना अनशन ख़त्म करने के बाद अपनी कर्मभूमि रालेगण सिद्धि गांव में रह रहे हैं. इसी गांव में पिछले दिनों अन्ना के सहयोगी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए एकत्र हुए थे. यहां अन्ना हज़ारे ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जमकर निशाना साधा. सरकार की ओर से अन्ना को जेड श्रेणी सुरक्षा देने की पेशकश की गई थी, जिसे अन्ना ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था. हालांकि लोग क़यास लगा रहे थे कि सरकार जेड सुरक्षा के बहाने अन्ना की निगरानी करना चाहती है. उनका कहना था कि जेड सुरक्षा घेरे में रहने के बाद अन्ना से मिलने वालों की लिखित इंट्री करने के बाद ही लोगों को अन्ना से मिलने की इजाज़त देने का प्रावधान है. ख़ैर, अन्ना द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी ख़ुशी है. बहरहाल, सरकार का दांव उल्टा पड़ने के बाद वह अन्ना पर निगाह रखने के लिए नए-नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही है. यही वजह है कि रालेगण सिद्धि गांव इन दिनों केंद्र और राज्य ख़ुफ़िया एजेंसियों के जासूसों का अड्डा बन गया है, जो अन्ना से जुड़ी जानकारी हासिल करने में जुटे हैं. ख़ास बात यह है कि ये जासूस साधु और चरवाहे के भेस में यहां डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इनकी गतिविधियों से गांव वाले भी वाक़िफ़ हो चुके हैं. राजधानी दिल्ली में बम धमाके हो रहे हैं, साथ ही समूचा देश दहशतगर्दों के निशाने पर है. ऐसे में रालेगण सिद्धि गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता पर नज़र रखने के लिए जासूसों की तैनाती करना सरकार के अदूरदर्शी रवैये को ज़ाहिर करता है. सवाल यह भी पैदा होता है कि आख़िर सरकार अन्ना की जासूसी क्यों करा रही है? क्या अन्ना से देश की सुरक्षा को किसी तरह का ख़तरा है? इससे साफ़ मतलब निकलता है कि सरकार ग़लत नीयत से अन्ना की जासूसी करा रही है. ऐसा लगता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ छेड़े गए आंदोलन के प्रति अपने पूर्व के रवैये से कोई सबक़ नहीं लेना चाहती. इन दिनों रालेगण सिद्धि गांव में पूरी तरह चराईबंदी लागू है. चराईबंदी का मतलब है गाय-भैंसों को खुला चराने पर रोक. स्थानीय ग्रामीण इस नए नियम का पालन कर रहे हैं, बावजूद इसके वहां एक शख्स वाटर रिचार्ज परियोजना क्षेत्र में भैंस चरा रहा था. गांव वालों की पूछताछ में उसने बताया कि वह रालेगण सिद्धि गांव का ही रहने वाला है, लेकिन जब उसके घर के बारे में पूछा गया तो वह सकपका गया. इसी तरह एक साधु से भी उसके आश्रम, गुरु और संन्यास के रीति-रिवाजों के बारे में पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सका. गांव वालों का कहना है कि बाद में किसान और संन्यासी बने उन दोनों को नज़दीक की पहाड़ी पर बातचीत करते देखा गया. लोगों को शक है कि ये लोग सरकारी जासूस हैं, जो अन्ना की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं. अन्ना हज़ारे से गांव में कौन और कब मिलने आता है इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है. अन्ना से जुड़े हर पहलुओं पर निगाह रखी जा रही है. इसके अलावा अन्ना हज़ारे के ट्रस्ट हिंद स्वराज के दानदाताओं की लिस्ट और उसके बही-खाते की जांच कराई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ़ ख़ुफ़िया विभाग स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट और भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति से संबंधित काग़ज़ातों की जांच भी कर रहा है. ख़बरों के मुताबिक़ इस काम के लिए आला अधिकारियों को भी भेजा गया है, जो अन्ना के ख़िलाफ़ सबूत खोजने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं.

दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी अन्ना के ख़िलाफ़ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने मुंबई में अन्ना के आंदोलन से पार्टी की छवि को हुए नुक़सान की भरपाई करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई. उसके बाद नागपुर में आयोजित कांग्रेस के विदर्भ स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई नेताओं ने अन्ना के आंदोलन की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक क़रार दिया. सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि मौजूदा समय में भ्रष्टाचार के ख़ात्मे की बात हो रही है. इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा. उनके मुताबिक़ जो विदेशों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल वे देश की साख को नुक़सान पहुंचा रहे हैं. ऐसे लोगों की ज़ुबान उस समय क्यों नहीं खुलती है, जब हमने गुजरात में लोकपाल गठित कर दिया है. मोहन प्रकाश की मानें तो कांग्रेस मज़बूत लोकपाल बिल संवैधानिक तरीक़े से लाना चाहती है. इस दौरान मुख्यमंत्री चव्हाण ने भी टीम अन्ना का नाम लिए बग़ैर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री चव्हाण के मुताबिक़ कुछ लोग टीवी चैनलों के ज़रिए वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है, पार्टी संविधान के मुताबिक़ ही काम करेगी. उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में देश के संविधान को बदलने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था. बहरहाल, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के रुख़ से साफ़ है कि वह टीम अन्ना के ख़िलाफ़ आने वाले समय में और सख्ती से पेश आएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

नागपुर में आयोजित कांग्रेस की एक बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पार्टी महासचिव मोहन प्रकाश व अन्य.

नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शिविर में मंचासीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, अनिल देशमुख, मनोहर नाइक व अन्य.

अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की बरसी पर मुंबई में विश्व व्यापार केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते अमेरिकी वाणिज्य दूत पीटर हास, केंद्र के अध्यक्ष कमल मोरारका, उपाध्यक्ष विजय कलंत्री, शरद उपासनी, कैप्टन सोमेश बत्रा और ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर बेकिंगहाम.

मुंबई स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री आर.आर पाटिल. उनके साथ हैं उपाध्यक्ष मदन वाफना और महासचिव दिवाकर तावड़े.

मिहान की बैठक को संबोधित करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. साथ में हैं एम.आई.डी.सी के उपाध्यक्ष एम.एस मदान.

मुंबई स्थित सिडको कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता करते सिडको अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव. साथ में हैं टी.सी बैंजामिन, वसंत राव भोईर, नामदेव भगत व अन्य गणमान्य लोग.

विभागीय लेखाधिकारी व लेखपाल संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव का स्वागत करते संगठन के उपाध्यक्ष रत्नदीप खंडारे, आर.के जाधव, बी.जी पांडे और श्रीवर्धने.

ये क्या हो रहा है...

ऐसी एकजुटता पहले क्यों नहीं?

विदर्भ का विकास हर कोई चाहता है. जन-जन की अपेक्षा सरकार से रहती है कि उनके गांव, तहसील, ज़िले का विकास हो. आवागमन के लिए सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने के लिए शुद्धजल, सिंचाई के लिए पानी, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार देने वाले कल-कारख़ाने और शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल-कॉलेज हों. हर कोई इन मूलभूत सुविधाओं को पाना चाहता है. इसके बावजूद विदर्भ के साथ अन्याय होता है और उसका बैकलाग बढ़ता जाता है. कहा जाता है कि विदर्भ के जनप्रतिनिधि पदलोलुपता व आपसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण कभी एक सुर में नहीं बोलते हैं, इसलिए यहां आने वाला हर नया प्रोजेक्ट मुंबई या पश्चिम महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया जाता है. यहां की राजनीतिक फूट का फ़ायदा पश्चिम महाराष्ट्र वाले उठाते हैं और विदर्भ और पिछड़ता जाता है. विदर्भ का पिछड़ापन दूर करने के नाम पर समितियों का खेल खेला जाता है. कभी दांडेकर समिति तो कभी इंडिकेटर कमेटी बनाकर विदर्भ के लोगों को बहला-फुसला दिया जाता है. अब केलकर समिति बनाकर भेज दी गई. आख़िर विदर्भ की जनता को बहलाने-फुसलाने का यह दौर ख़त्म होगा भी या नहीं? बहरहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार विदर्भ के जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि आ गई है. इसकी ताज़ा मिसाल है 17 सितंबर को रविभवन में आयोजित बैठक. विदर्भ विकास मंच के बैनर तले हुई इस बैठक में पार्टी लाइन से हटकर कई नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया. इन जनप्रतिनिधियों ने गंभीर होकर विदर्भ के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार आदि गंभीर मसलों पर विचार-विमर्श किया. बैठक के दौरान केलकर समिति पर भी एक दूसरे की राय सुनी गई. काफ़ी अरसे बाद विदर्भ के नेताओं में ऐसी एकजुटता देखी गई. अतीत पर निगाह डालें तो लगभग 11 वर्षों बाद स्वस्थ राजनीति का ऐसा उदाहरण देखने को मिला. सच पूछें तो विदर्भ की जनता भी चाहती है कि उनके नेताओं में यह एकजुटता क़ायम रहे, ताकि विदर्भ के साथ भेदभाव करने की हिम्मत कोई नहीं कर सके. ख़ैर, अब जब हमारे विधायकों को आपसी एकता और उसकी ताक़त का अहसास हो गया है तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विदर्भ की सूरत बदलेगी. हालांकि, यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि नागपुर में एक केंद्रीय विधि महाविद्यालय स्थापित होना था, लेकिन उसे मुंबई ले जाया गया. काश, उस समय हमारे नेताओं ने एकजुटता दिखाई होती तो यह गौरव विदर्भ को हासिल होता. इस बाबत जब अख़बारों में ख़बरें प्रकाशित हुईं तो यहां के नेताओं को होश आया कि विदर्भ के साथ अन्याय हो रहा है. उसके बाद बयानबाज़ी का दौर शुरू हो गया. बहरहाल, राजनीतिक मतभेद ठीक हैं, लेकिन विदर्भ तो आख़िर एक ही है और एक ही रहेगा. उसके हित संरक्षण की ज़िम्मेदारी आख़िरकार विदर्भवासियों के ज़िम्मे है. एकता की मिसाल क़ायम करने वाले हमारे विधायकों को अब चाहिए कि वे अपनी एकता का परिचय राज्यपाल के सामने भी प्रकट करें. उन्हें पूछना चाहिए कि महामहिम आपके राज में ये क्या हो रहा है? विदर्भ का पिछला बैकलाग ख़त्म हुआ नहीं और आपने एक और केलकर समिति बनाकर नागपुर भेज दी. समिति के अध्यक्ष को जन भावना का ज़रा भी ख़्याल नहीं है. जनता उनसे अपनी मातृभाषा मराठी और हिंदी में बोलने को कहती है, पर वह अंग्रेजी में ज्ञान बघारते हैं. भाई जिस आदमी को जनता की भाषा न आती हो, जिसे जन भावना का ख़्याल न हो, वह आख़िर जन सुनवाई कैसे कर सकता है? आख़िर समितियों के गठन का यह खेल विदर्भ के साथ कब तक खेला जाएगा?

विदर्भ विकास मंच के बैनर तले हुई इस बैठक में पार्टी लाइन से हटकर कई नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया. इन जनप्रतिनिधियों ने गंभीर होकर विदर्भ के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार आदि गंभीर मसलों पर विचार-विमर्श किया. बैठक के दौरान केलकर समिति पर भी एक दूसरे की राय सुनी गई. काफ़ी अरसे बाद विदर्भ के नेताओं में ऐसी एकजुटता देखी गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मिनी चुनाव

चव्हाण और पवार की अग्निपरीक्षा

युधिष्ठिर जोशी

गांधी-नेहरू, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और डॉ. भीमराव अंबेडकर का उठते-बैठते जय-जयकार करने वाले महाराष्ट्र के नेताओं की कथनी और करनी में घोर अंतर है. राजनीति में आने से पहले ये नेता आम आदमी और सत्ता मिलने के बाद देखते ही देखते धनकुबेरों की जमात में शामिल हो जाते हैं. राजनीति में सफलता का यह अर्थशास्त्र कांग्रेस, भाजपा और राकांपा समेत सभी पार्टियों के नेताओं पर लागू होता है. दरअसल महापुरुषों का गुणगान करने वाले इन नेताओं का असल मक़सद जनता को रिझाना होता है. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को जाणता राजा यानी (जनता का राजा) कहा जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जाणता राजा के नाम से पुकारा जाता था. अब यह संबोधन शरद पवार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. पवार प्रदेश की राजनीति में पिछले पचास साल से सक्रिय हैं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण के मानसपुत्र बनकर उन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की. चव्हाण के दिल्ली प्रस्थान करने के बाद राज्य महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एकछत्र राज्य क़ायम हो गया. शुरुआती दिनों में कांग्रेसी संस्कृति में डूबे शरद पवार ने अपनी अलग ही खिचड़ी पकाई. हालांकि बाद में उन्होंने बेशक कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, लेकिन हक़ीक़त यह भी है कि कांग्रेस शब्द से उनका मोह ख़त्म नहीं हुआ. यही वजह है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखा. देश की सियासत में शरद पवार का क़द काफ़ी ऊंचा है. दिल्ली से लेकर मुंबई के सत्ता गलियारे में पवार का अच्छा ख़ासा दख़ल है. जिस तरह उन्हें राजनीति विरासत में मिली थी, उसी तरह उन्होंने भी अपने भतीजे अजीत पवार और पुत्री सुप्रिया सुले को राजनीति की विरासत सौंपी है. हालांकि, सियासत में एक कहावत काफ़ी मशहूर है कि राजनीति में रिश्ते-नाते भी कभी-कभी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाते हैं. अजीत पवार को एक महत्वाकांक्षी सियासतदां के तौर पर जाना जा जाता है. जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद पाया उससे साफ़ ज़ाहिर है कि ऐसी जुगत कोई चतुर सुजान शख्स ही लगा सकता है. इतना ही नहीं उनके पास ऊर्जा मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय भी है. अंदरख़ाने में चल रही चर्चाओं की मानें तो राकांपा के जो मंत्री अजीत दादा की बात न मानने की हिमाक़त करते हैं, तो उन्हें कोई विशेष दंड न देकर उनके मंत्रालयों की आर्थिक मदद कम कर दी जाती है. हालांकि, छगन भुजबल ने उपमुख्यमंत्री पद अपने पास क़ायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें अंततः कामयाबी नहीं मिली. उसके बरअक्स अजीत दादा ने आगे बढ़कर पार्टी के अंदर अपने गुट को मज़बूत किया और उप मुख्यमंत्री के पद पर क़ाबिज़ हुए. गत मार्च महीने के बजट अधिवेशन में बजट पेश करते वक़्त अजीत दादा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कम राशि का आवंटन कर भुजबल को निष्क्रिय कर दिया था. इसीलिए राज्य की ख़स्ताहाल सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने का प्रश्न चर्चा में आया था. मंत्रालय की तरफ़ से कम धनराशि आवंटित होने की शिकायत भुजबल ने ख़ुद विधानसभा में की थी. शरद पवार के प्रति वफ़ादार भुजबल और आबा पाटिल को छोड़कर राकांपा के सभी मंत्री और विधायक अजीत दादा के साथ हो गए.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधीन मंत्रालयों के अधिकारिओं के चुनाव, तबादले, जो मंडल राकांपा के मंत्रियों के पास हैं, उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति अजीत दादा अपनी मनमर्ज़ी से करते हैं. इससे साफ़ ज़ाहिर है कि प्रदेश में राकांपा के सभी सूत्र अजीत दादा के हाथ में हैं. शरद पवार के तीसरे और चौथे गोलंदाज़ी की पकड़ भी ढीली पड़ गई है. अब उस पर क़ब्ज़ा अजीत दादा ने कर लिया है. इस साल के आख़िर में राज्य में नगर पालिका और अगले साल 2012 की पहली तिमाही में महानगर पालिका और सभी स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव आने वाले समय में अजीत दादा के लिए ख़ुद को आगे बढ़ाने का एक अवसर हैं. आगामी चुनावी समर जीतने के लिए अजीत दादा काफ़ी सोची-समझी रणनीति अमल में ला रहे हैं. फ़िलहाल उनके सामने दो लक्ष्य हैं- एक कांग्रेस को बदनाम करना और दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर पूर्णतः क़ब्ज़ा करना. वैसे अजीत दादा के बारे में यह कहा जाता है कि वह फ़ैसले लेने में काफ़ी माहिर हैं. वह पिछले डेढ़ दशक से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं.

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राकांपा विधायकों की संख्या कांग्रेस से अधिक हो, यही उनका अगला लक्ष्य है. तभी वह मुख्यमंत्री का पद आसानी से हासिल कर पाएंगे. कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में अगर कांग्रेस रोड़ा बनती है तो वह शिवसेना या भाजपा के साथ भी सत्ता की भागीदारी करने में कोई गुरेज़ नहीं करेंगे. पिछले दिनों यह ख़बर सुर्ख़ियों में रही कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत दादा बग़ावत करने वाले हैं. शिवसेना के ख़ेमे में पवार आएंगे यह ख़बर सुर्ख़ियों में रही थी. वैसे भी शरद पवार कौन से पाक-साफ़ हैं. एक समय पुलोद के साथ जनसंघ था ही और जनसंघ के पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय थे. केंद्र में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में शरद पवार ने आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष भी थे. आगामी स्थानीय स्वराज संस्था का चुनाव महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में मिनी चुनाव पहली बार कांग्रेस को लड़ना है. उन्हें गांव-गांव की छोटी-छोटी बारीकियां मालूम नहीं हैं और राज्य में कांग्रेस पर भी उनकी पकड़ नहीं है. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के संदर्भ में सबसे अधिक शिकायत यह है कि वह कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मिलते नहीं हैं. उनके पास अलग-अलग मंत्रालयों की कम से कम बीस हज़ार फाइलें हस्ताक्षर के लिए अटकी पड़ी हैं. इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे में भी नेतृत्व क्षमता का अभाव है और पार्टी पर उनकी पकड़ भी नहीं है. इससे यह पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस नेतृत्व राकांपा की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर है. ऐसी हालत में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए स्थानीय निकाय चुनाव किसी इम्तिहान से कम नहीं है. पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र की सत्ता संभालने से पहले केंद्र में काबीना मंत्री थे, लिहाज़ा पार्टी में स्वतंत्र रूप से उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र का मुखिया बनने के बाद कांग्रेस को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव में चव्हाण और पवार कितना कामयाब होते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

केलकर समिति

जन सुनवाई के नाम पर रस्म अदायगी

विदर्भ में अनुशेष का अध्ययन करने के मक़सद से नागपुर पहुंची केलकर समिति द्वारा 18 सितंबर को वसंत राव देशपांडे हॉल में आयोजित जन सुनवाई महज़ औपचारिकता बनकर रह गई. जन सुनवाई दोपहर दो बजे से होनी थी, लेकिन समिति के अध्यक्ष व अन्य अधिकारी अपने नियत समय से काफ़ी देर से पहुंचे. यहां जन सुनवाई के दौरान लोगों की मौजूदगी काफ़ी कम रही. स्थानीय लोगों की मानें तो इस संबंध में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी. लिहाज़ा जो भी सुनवाई हुई वह एकतरफ़ा हुई. वहां मौजूद लोगों ने जो कहा उसे समिति ने सुना. समिति के अध्यक्ष विजय केलकर और अन्य सदस्यों ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझा. वहां माहौल ऐसा था कि जन सुनवाई महज़ रस्म अदायगी ही साबित हुई. बार-बार आग्रह किए जाने के बाद भी विदर्भ के जनप्रतिधियों को सभा में आमंत्रित नहीं किया गया. हालांकि इस सभा में कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य ज़रूर मौजूद थे, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों की ऐसी उपेक्षा चर्चा का विषय बन गई. इस सभा में नागपुर का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा. हालांकि, रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल कुछ पल के लिए वहां ज़रूर आए. कलमेश्वर और कुही ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य भी अपनी बात रखने के लिए सभा में आए, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं मिला. मंच पर आसीन समिति के अध्यक्ष विजय केलकर, जिलाधिकारी सौरभ राव, प्रभारी विभागीय आयुक्त प्रवीण दराडे, डॉ. अभय बंग, डॉ. विनायक देशपांडे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. आर. पी. चहांदे, मुकुंद घारे, विजय बोराडे और डॉ. वी.एम. मायंदे जन सुनवाई के लिए बैठे थे. सभा में आए नागरिकों ने इन अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी बातें सुनाईं. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के विभागीय महा व्यवस्थापक सुधीर केदार ने कहा कि समिति को इस प्रकार सुनवाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र का विकास करते समय क्या पहले कभी जन सुनवाई करने की ज़रूरत महसूस हुई थी. नागपुर में पेट्रोल सबसे महंगा बिकता है. इसके जवाब में कई तरह के टैक्स का बहाना बनाया जाता है. क्या विदर्भ में बनने वाली बिजली मुंबई या अन्य जगह जाकर महंगी हो जाती है. सिर्फ़ विदर्भ के लोगों पर लागू होने वाला टी एंड डी लॉस पुणे के उद्योगों के बिल पर लागू किया गया तो उद्योगों को नागपुर लाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राज्य सरकार के मातहत बड़े-बड़े अधिकारी हैं, क्या उन्हें यह बताना पड़ेगा कि विकास कैसे करें? दरअसल विदर्भ को बहलाने के लिए इस तरह की समिति को यहां भेजा गया है. उन्होंने समिति को सुझाव दिया कि राज्य के मंत्रालयों से विदर्भ के सेवानिवृत्त अधिकारियों से यहां के विषय में रिपोर्ट तैयार कराई जाए तो वह ज़्यादा उपयोगी और हक़ीक़त को सामने लाने वाली होगी. वहीं इस सभा में आक्रोश संस्था के डॉ. अशोक लांजेवार ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि विदर्भ के विकास के लिए वैधानिक विकास मंडल को निधि तो दी जाती है, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल होता है या नहीं यह काफ़ी बड़ा सवाल है.

वर्धा ज़िला परिषद के सदस्य मिलिंद भेंडे ने विदर्भ में प्रलंबित प्रकल्पों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां अनेक प्रकल्प मौजूद हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण सिंचाई का अनुशेष बढ़ता जा रहा है. रामटेक से आए संजय सत्येकार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि यहां कभी समस्या का समाधान होगा. उन्होंने समिति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि समिति के सदस्यों को यहां आने-जाने का अतिरिक्त भत्ता मिलता है, जबकि हमें गाड़ी का ख़र्च अपनी जेब से भरना होता है. अभियंता नितिन रोंगे ने मानव निर्देशांक का ज़िक्र करते हुए कहा कि विदर्भ इस मामले में सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है. पुणे विभाग की एक भी तहसील इसमें शामिल नहीं है. विदर्भ के हज़ारों नौजवानों को नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना पड़ता है और बाद में वे उसी प्रदेश में बस जाते हैं. क्या इसे विदर्भ का विकास कहा जाएगा? काटोल के आए चरण सिंह ठाकुर ने सिंचाई अनुशेष का मामला उठाया. वहीं सिकलसेल निर्मूलन सोसायटी के अध्यक्ष संपत रामटेके ने सिकलसेल से सिर्फ़ पिछड़ी जाति ही नहीं, बल्कि उच्च जातियों के भी प्रभावित होने का ख़ुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ़ विदर्भ में है जिसे सरकार लगातार नज़रअंदाज़ कर रही है. जो ग़रीब हैं, वे इस बीमारी पर उतना ख़र्च नहीं कर पाते. आख़िर सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी क़दम क्यों नहीं उठाती? पृथक विदर्भ जनांदोलन समिति के महासचिव अहमद कादर ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र की समस्या का स्थायी निदान अलग विदर्भ राज्य है. उनके इस कथन का सभागृह में मौजूद सभी लोगों ने समर्थन किया.

समिति अध्यक्ष जल्दी में थे

जन सुनवाई चल रही थी. सुनवाई एकतरफ़ा हो रही थी. मंच पर वक्ता बोल रहे थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष विजय केलकर को कहीं जाने की जल्दी थी. उनका ध्यान वक्ताओं के विचारों पर नहीं था. अध्यक्ष बार-बार अपनी घड़ी में समय देख रहे थे. उनके चेहरे का भाव भी बता रहा था कि जनाब जन सुनवाई को जल्दी निपटाना चाहते हैं. उन्हें जनभावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा, क्योंकि विदर्भ के अनुशेष के संबंध में जब जन सुनवाई शुरू हुई तो समिति के अध्यक्ष विजय केलकर अंग्रेजी में बोलने लगे. उनके अंग्रेजी प्रेम पर लोगों को काफ़ी हैरत हुई. लिहाज़ा सभा में मौजूद लोगों ने उनसे मराठी में बोलने का आग्रह किया. लेकिन केलकर साहब भला किसकी सुनते. वह अपना भाषण मराठी और हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही देते रहे. बेचारे लोग जिन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, वे मन मसोस कर रह गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नागपुर महानगर पालिका चुनाव हर दल के लिए अब चुनौती बन गया है. मनपा के 136 वार्ड के लिए 72 प्रभागों की रचना होने के बाद उनके सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

गठबंधन मजबूरी बना

प्रभाग रचना से कई नेताओं का भविष्य अधर में

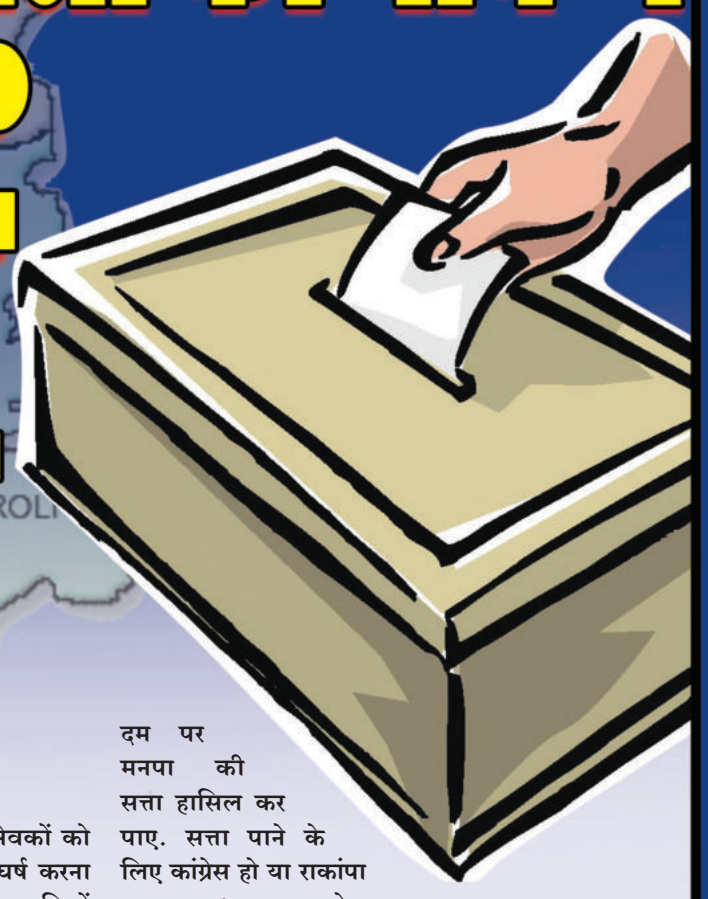

प्रवीण महाजन

महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनज़र बहुप्रतीक्षित प्रभाग रचना और आरक्षण की घोषणा होने के साथ ही सभी दलों के पार्षदों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं. प्रभाग रचना होने के साथ ही कई नगर सेवकों का भविष्य चुनाव से पहले ही डूबने लगा है. ऊपर से आरक्षण ने भी उनके प्लान को बिगाड़ दिया है. स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण घोषित किए जाने के बाद से कई मौजूदा नगर सेवक हलकान हैं. बाक़ी कसर प्रभाग रचना ने पूरी कर दी. नागपुर, अमरावती, अकोला के कई नगर सेवक अब अपना चुनावी क्षेत्र बदलने की सोच रहे हैं. इसके अलावा प्रभाग रचना ने सभी दलों के राजनीतिक समीकरणों में भी काफ़ी उलटफेर कर दी है. जो दल अपने सहयोगियों के बिना अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे थे, प्रभाग रचना के बाद अचानक उनकी बोलती बंद हो गई. उन्हें अब नए सिरे से मनपा चुनाव की रणनीति बनाने पर विचार करना पड़ रहा है. साथ ही उन्हें अब अपने सहयोगियों की ज़रूरत भी महसूस होने लगी है. मतलब साफ़ है कि सभी दल अब यह सोच रहे हैं कि अगर चुनावी नैया पार करनी है तो गठबंधन हर हाल में ज़रूरी है. कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या रिपब्लिकन पार्टी सभी के लिए चुनावी गठबंधन उनकी मजबूरी है. जिस दल ने गठबंधन नहीं किया उसकी लुटिया आगामी मनपा चुनाव में डूबना तय माना जा रहा है. नागपुर महानगर पालिका चुनाव हर दल के लिए अब चुनौती बन गया है. मनपा के 136 वार्ड के लिए 72 प्रभागों की रचना होने के बाद उनके सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं. महापौर हों या उपमहापौर या विपक्ष का नेता सभी अपने पैरों के तले की ज़मीन बचाने की जुगत लगा रहे हैं. आख़िर आगामी मनपा चुनाव में अपनी नौका कौन डुबोना चाहेगा. बहरहाल, प्रभाग रचना की घोषणा होते ही चुनावी बिसात बिछने लगी है. मगर दो वार्डों का एक प्रभाग बनने से कई वार्डों के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है. नगर सेवकों के लिए यही सबसे अधिक चिंता का विषय है. कुछ नगर सेवकों का क्षेत्र इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है. वार्ड का क्षेत्र बदलने से जिन प्रमुख लोगों को नए निर्वाचन क्षेत्र की तलाश करनी पड़ सकती है, उनमें महापौर अर्चना डेहनकर, विकास ठाकरे, शेखर सावरबांधे, अनिल सोले, संदीप जोशी, प्रकाश गजभिये, प्रफुल्ल गुडधे, वेदप्रकाश आर्य सहित सभी दलों के कई अन्य नगर सेवक शामिल हैं. महापौर अर्चना डेहनकर के वार्ड गांधीसागर प्रभाग रचना के बाद ओबीसी और सामान्य प्रवर्ग की महिला के लिए आरक्षित घोषित किया गया है. इस प्रभाग में कर्नलबाग और शनिवारी वार्ड की कई बस्तियों को शामिल किया गया है. इसी तरह विपक्षी दल कांग्रेस के नगर सेवक विकास ठाकरे का गोपालनगर वार्ड अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किए जाने से उनको अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलना ही पड़ेगा. संभावना है कि गोपालनगर वार्ड से लगकर टाकली सीम क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. ऐसी ही स्थिति स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप जोशी के वार्ड की है. प्रभाग रचना में उनके नीरी वार्ड का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है और उसका समावेश जेलवार्ड में कर दिया गया है. वहीं राकांपा नेता वेदप्रकाश आर्य का जरीपटका प्रभाग अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया है. उसके पड़ोसी प्रभागों के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने से उनके सामने जाएं तो कहां जाएं की स्थिति पैदा हो गई है. भाजपा के शहर अध्यक्ष अनिल सोले भी प्रभाग रचना की मार से नहीं बच सके हैं. उनका पुराना निर्वाचन क्षेत्र जयप्रकाश नगर वार्ड का समावेश खामला प्रभाग में कर लिया गया है. अब उनके सामने नया क्षेत्र खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. राकांपा नेता प्रकाश गजभिये का हिलटाप वार्ड दो हिस्सों में बंट गया है, जो आधा वीएनआईटी तो आधा अंबाझरी प्रभाग में गया है. इससे प्रकाश गजभिये का संकट और बढ़ गया है. उपमहापौर शेखर सावरबांधे का नंदनवन वार्ड का अस्तित्व नई प्रभाग रचना में ख़त्म हो गया है. उन्हें भी नए आशियाने की खोज करनी पड़ रही है. अमरावती मनपा में 81 वार्डों को समायोजित कर 43 प्रभागों की रचना की गई है. मात्र एक प्रभाग जवाहर गेट से तीन नगर सेवक चुने जाएंगे, जबकि सभी प्रभागों से दो का ही चुनाव किया जाएगा. अमरावती मनपा में एड. किशोर शेलके, विपक्ष के नेता संजू अग्रवाल, शिवसेना नेता दिगंबर डहाके का निर्वाचन क्षेत्र प्रभाग रचना में सुरक्षित है. कांग्रेस के नगर सेवक बबलू शेखावत, पूर्व महापौर अशोक डोंगरे, प्राध्यापक संजय शिरभाते, उपमहापौर शेख जब्बार, शिवसेना नगर सेवक प्रदीप बाजड, प्रवीण हरमकर, भाजपा के वासु देऊलकर और स्वतंत्र नगर सेवकों को सबसे ज़्यादा प्रभाग रचना का झटका लगा है. विदर्भ की सबसे छोटी महानगर पालिका अकोला है और सबसे अधिक विवादों घिरी रहती है. यहां सत्तापक्ष और अधिकारियों में कामकाज और मुद्दों को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है. अकोला मनपा के लिए 36 प्रभाग बनाए गए हैं. महापौर सुरेश पाटिल, पूर्व महापौर मदन भरगरड़, राकांपा के उपमहापौर हाजी अज़ीज़ अहमद, शिवा मोहोड़, कांग्रेस की पुष्पा गुलवाड़े, सुनील मेश्राम, विजय अग्रवाल, पप्पू शर्मा, सुमन गावंडे के निर्वाचन क्षेत्रों पर प्रभाग रचना का कोई असर नहीं पड़ा है जिससे इन सभी ने राहत की सांस ली है. लेकिन प्रभाग रचना से जिनके क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, उनमें राकांपा के पूर्व उपमहापौर निखिलेश दिवेकर, शिवसेना के राजेश मिश्रा, राजू गाड़े, मुस्लिम लीग के इक़बाल सिद्दीक़ी शामिल हैं. प्रभाग रचना एक तरह से हर दल के लिए अब सरदर्द साबित हो रहा है. प्रभाग प्रणाली लागू होने और महिलाओं के लिए पचास फ़ीसदी आरक्षण लागू होने से जहां कई नगर सेवकों को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वहीं हर दल को प्रभाग के अनुसार प्रत्याशियों की तलाश करनी पड़ रही है. इसके अलावा नए क्षेत्र को लेकर कई नगर सेवक आशंकित हैं, क्योंकि जहां उन्होंने काम किया वह प्रभाग रचना में दूसरी ओर चला गया है और जहां से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है, उस क्षेत्र में उनकी कोई पकड़ नहीं है. योग्य महिला प्रत्याशियों की तलाश में राजनीतिक दलों को ख़ासी मेहनत करनी पड़ रही है. इस सबके बीच जो नई बात यह उभरकर सामने आई है कि जिस क्षेत्र में पिछले चुनाव में राकांपा या शिवसेना की पकड़ अच्छी वह अब कांग्रेस या भाजपा के प्रभावी नगर सेवक के प्रभाग में समावेश कर दिया गया है. इसी तरह जहां कांग्रेस या भाजपा का नगर सेवक था, वह एरिया अब राकांपा या शिवसेना के प्रभाव वाले प्रभाग में शामिल कर लिया गया है. मतलब साफ़ है कि अब यदि राकांपा अपनी सहयोगी कांग्रेस को या भाजपा अपने परंपरागत साथी शिवसेना का साथ छोड़ने का विचार करती है तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा. नई प्रभाग रचना के बाद किसी दल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने दम पर मनपा की सत्ता हासिल कर पाए. सत्ता पाने के लिए कांग्रेस हो या राकांपा अथवा भाजपा हो या शिवसेना, अपने सहयोगी को अपने साथ लेकर चलना होगा. जिसने एकला चलो का रास्ता अपनाया वह कहीं का नहीं रहेगा. इसके अलावा यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्वतंत्र प्रत्याशियों की राह भी आसान नहीं रहेगी. उनके लिए अपना एरिया छोड़कर अन्य क्षेत्र से समर्थन पाना आसान नहीं होगा. दलबदल बढ़ने की आशंका मनपा चुनाव में प्रभाग रचना के बाद अब दलबदल की घटनाएं बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई. इसका कारण यह बताया जा रहा है कि कई नगर सेवक अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाकर अपनी पार्टी को बाय–बाय, टाटा कर अन्य दल का दामन पकड़ सकते हैं. चूंकि मनपा चुनाव के हाई प्रोफाइल होने के साथ ही इसमें पैसे का पानी की तरह बहना निश्चित है. इसलिए बड़े पैमाने पर दलबदल होने की आशंका है. यह भी कहा जा रहा है कि दलों में तोड़फोड़ करने में राकांपा सबसे आगे रहने वाली है. इसके लिए उसने पिछले दिनों नागपुर में संपन्न कार्यकर्ता शिविर में अपने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर रणनीति भी बनाई है. यह भी कहा जा रहा है कि राकांपा के निशाने पर सभी दल हैं. बहरहाल, चुनाव के समय दलबदल होना आज की राजनीति में एक आम बात है. इसका उपयोग हर दल दूसरे दल को कमज़ोर करने के लिए करता है. जिसे दूसरे दल में बेहतर अवसर मिलने की संभावना नज़र आती है, वह वहां छलांग लगाने में ज़रा भी देर नहीं करता है. हां, प्रभाग रचना से पैदा हुई स्थिति के चलते इस बार अधिक दलबदल होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

विलास मुत्तेमवार

गडकरी और मुत्तेमवार के बीच मुक़ाबला

नितिन गडकरी

चूंकि इस बार के चुनाव हाई प्रोफाइल होने की अभी से चर्चा है. इसकी वजह यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का नागपुर गृह नगर है और वर्तमान में मनपा पर उनकी पार्टी का राज है. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विलास मुत्तेमवार का घर भी नागपुर ही है यानी लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के बीच होगी और इस लड़ाई को राकांपा तिकोना बनाने की तैयारी कर चुकी है. उसके वर्तमान के 8 नगर सेवकों की संख्या आगामी मनपा चुनाव में 20 करने का लक्ष्य तय किया है और उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है. अन्य छोटे दल व स्वतंत्र प्रत्याशी इस चुनाव को बहुरंगी बनाएंगे, लेकिन आगामी मनपा चुनाव भाजपा नेता गडकरी और कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेमवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. इसलिए दोनों ओर से कमर कस ली गई है और इस चुनावी जंग को जीतने के लिए साम-दाम-दंड-भेद की हर चाल अभी से चली जा रही है. यदि मनपा चुनाव में मनपा से भाजपा की सत्ता जाती है तो गडकरी के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे. इससे पार्टी में उनकी साख पर आंच आने की आशंका ज़ाहिर की जा रही है. कुछ ऐसी ही बात मुत्तेमवार के विषय में कही जा रही है. राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा शुरू हो गई है कि मनपा चुनाव में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने 45 करोड़ रुपये और भाजपा ने 30 करोड़ रुपये और राकांपा ने 20 करोड़ ख़र्च करने का बजट हो सकता है यानी आने वाले चुनाव में पैसा पानी की तरह बहेगा.

संदीप जोशी

अर्चना डेहनकर

प्रकाश गजभिए

शेखर सावरबांधे

एड. किशोर शेलके

दिगंबर दहाके

संजू अग्रवाल

हाजी अज़ीज अहमद

शिवा मोहोड

सुमनताई गावंडे

सुरेश पाटिल

वेदप्रकाश आर्य

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

कार्यालय स्थानांतरित

साप्ताहिक चौथी दुनिया के कार्यालय का स्थानांतरण 28 सितंबर को सीताबर्डी स्थित मुरलीधर काम्प्लेक्स में हो रहा है. अतः चौथी दुनिया के सभी पाठकों, एजेन्टों व हॉकरो से अनुरोध है कि वे कार्यालयीन कार्य के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क करें–

साप्ताहिक चौथी दुनिया
आशीर्वाद पब्लिकेशन
मुरलीधर काम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, सीताबर्डी, नागपुर
E-mail : chauthiduniya @gmail.com

सुनहरा अवसर
चौथी दुनिया

पत्रकारिता में रूचि रखने वालों के लिए
'साप्ताहिक चौथी दुनिया' से जुड़ने का सुनहरा अवसर

1– वार्ड प्रतिनिधि : नागपुर के सभी वार्डों के लिए
2– कॉलेज प्रतिनिधि : नागपुर के सभी कॉलेज के लिए

वार्ड व कॉलेज प्रतिनिधि बनने के उम्मीदवार अपने बायोडाटा व दो पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं.

संपर्क साप्ताहिक चौथी दुनिया
आशीर्वाद पब्लिकेशन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में सीताबर्डी नागपुर
E-mail : chauthiduniya@gmail.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 03 अक्टूबर–09 अक्टूबर 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

9661337777 / 9472722024

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9472727767 / 9162779209

मोदी पर महाभारत

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

जब कोई किसी को जीने की दुआ दे और साथ ही मरने की दवा भी दे दे, तो वाक़ई एक उलझने वाली स्थिति पैदा हो जाती है. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिनों के हाई वोल्टेज शो ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को बुरी तरह उलझाकर रख दिया है.

उलझन ऐसी कि अब जदयू व भाजपा में महाभारत के आसार बन गए हैं. मंत्रियों व पार्टी पदाधिकारियों के बयानों से इसकी बानगी दिखने लगी है. विपक्ष को इस प्रकरण से बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है. दरअसल, बिहार के कई मंत्री, नेता व प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को उपवास मंच पर गले लगाकर जदयू–भाजपा गठबंधन की कई गांठों को कमज़ोर कर दिया. अब विपक्ष, गुजरात गए मंत्रियों की बर्ख़ास्तगी की मांग पर अड़ गया है. विपक्ष का कहना है कि अगर नीतीश कुमार को मोदी से परहेज़ है तो उनके मंत्री नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगा रहे हैं? सीपी ठाकुर व रामेश्वर चौरसिया गए, ठीक है, पर नीतीश कुमार के मंत्री वहां क्या कर रहे थे? कुछ मंत्री तो उपवास पर बैठे और किसी ने हवन किया, यह क्या है? नीतीश कुमार अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उन्हें इस पर सफ़ाई देनी चाहिए और इन मंत्रियों को तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए. राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि यह नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र है. अगर उनमें ज़रा भी नैतिकता बची है तो उन्हें नरेंद्र मोदी को गले लगाने वाले मंत्रियों को कैबिनेट से तुरंत बाहर कर देना चाहिए. दूसरी तरफ़ बिहार भाजपा कह रही है कि यह सद्भावना उपवास था और इसमें शामिल होने में क्या बुराई है. सीपी ठाकुर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का फ़ैसला तो संघ करेगा. नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की और इसका स्वागत होना चाहिए. बिहार में हम जदयू के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और यह रिश्ता जारी रहेगा. हर पार्टी अपना काम करती है, इसमें हर्ज क्या है. लेकिन शिवानंद तिवारी इन बातों से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया. राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब भी गुजरात की जनता में डर और असुरक्षा की भावना है. उपवास के दौरान अपने संबोधन में मोदी की जो भाव–भंगिमा थी, वह अहंकारपूर्ण थी. मोदी, जो आमतौर पर गुजरात की जनता को गुजराती भाषा में संबोधित करते हैं, पहली बार हिंदी में भाषण दे रहे थे. इसके ज़रिए वह यह ज़ाहिर करना चाहते थे कि वह अपने बदले व्यक्तित्व में राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. अपने भाषण में मोदी ने वर्ष 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ, उसके लिए पछतावे की कोई बात नहीं की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर भाजपा कुछ नहीं कहती वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. वैसे प्रधानमंत्री बनने के न तो मैं योग्य हूं और न ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है. बिहार की सेवा मेरा धर्म है और पूरी ईमानदारी से इसे कर रहा हूं. उपवास भाजपा का अंदरूनी मामला है.

जदयू के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी मानते हैं कि भारत में किसी को भी संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहने का अधिकार है. जबकि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है. मोदी ने गुजरात के साथ–साथ पूरे देश में शांति के लिए तीन दिन का उपवास किया, उनमें अच्छे नेतृत्वकर्ता के तमाम गुण मौजूद हैं. यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जदयू व भाजपा के नेताओं के बीच यह बयानबाज़ी तेज़ होगी. नीतीश कुमार हर हाल में नरेंद्र मोदी से दूरी चाहते हैं, पर राष्ट्रीय राजनीति में उभर रही परिस्थितियां उन्हें अब परेशान करने लगी हैं. इसलिए जदयू के नेता अपना गला साफ़ कर रहे हैं और इससे तेज़ आवाज़ में भाजपा के नेता जवाब दे रहे हैं. इस बीच भाजपा अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि प्रधानमंत्री का फ़ैसला संघ करेगा. ठाकुर के इस बयान पर जदयू सांसद अली अनवर ने गहरी नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि गठबंधन व सरकार तो समन्वय से ही चलेगी. किसी को एकतरफ़ा बात नहीं करनी चाहिए. अनवर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रकरण भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है. मेरी राय में आख़िरकार प्रधानमंत्री का फ़ैसला तो जनता करती है. जनता जिसे चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा. लेकिन जहां तक एनडीए की बात है तो इसके सभी घटक दल आपसी राय से ही किसी फ़ैसले पर पहुंचेंगे. अकेले किसी के कुछ तय कर देने से कुछ नहीं होगा. नेताओं के तेवर तल्ख़ होते जा रहे हैं. देखना है इन तेवरों से नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार के अपने–अपने मिशन को कितना फ़ायदा मिलता है.

feedback@chauthiduniya.com

नेताजी कहिन

यह नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र है. अगर उनमें ज़रा भी नैतिकता बची है तो उन्हें नरेंद्र मोदी को गले लगाने वाले मंत्रियों को कैबिनेट से तुरंत बाहर कर देना चाहिए.
– रामकृपाल यादव

नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया. अब भी गुजरात की जनता में डर और असुरक्षा की भावना है. उपवास के दौरान अपने संबोधन में मोदी की जो भाव–भंगिमा थी, वह अहंकारपूर्ण थी. ***– शिवानंद तिवारी***

वैसे प्रधानमंत्री बनने के न तो मैं योग्य हूं और न ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है. बिहार की सेवा मेरा धर्म है और पूरी ईमानदारी से इसे कर रहा हूं. उपवास भाजपा का अंदरूनी मामला है.
–नीतीश कुमार

नरेंद्र मोदी प्रकरण भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है. मेरी राय में आख़िरकार प्रधानमंत्री का फ़ैसला तो जनता करती है. जनता जिसे चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा.
– अली अनवर

प्रधानमंत्री का फ़ैसला संघ करेगा.
–सीपी ठाकुर

नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है. मोदी ने गुजरात के साथ–साथ पूरे देश में शांति के लिए तीन दिन का उपवास किया, उनमें अच्छे नेतृत्वकर्ता के तमाम गुण मौजूद हैं.
–गिरिराज सिंह

फोटो– *संजय कुमार*

फेसबुक पर भी सरकार का पहरा

लिखने–पढ़ने की आज़ादी पर भी अब बिहार सरकार कड़ा पहरा लगा रही है. बीते 16 सितंबर को बिहार विधान परिषद ने अपने दो कर्मचारियों को फेसबुक पर प्रतिकूल लिखने के कारण निलंबित कर दिया. ये कर्मचारी हैं कवि मुसाफ़िर बैठा और युवा आलोचक अरुण नारायण. मुसाफ़िर बैठा को दिए निलंबन पत्र में कहा गया है कि मुसाफ़िर बैठा ने परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया और दीपक तले अंधेरा जैसी टिप्पणी की. उन्होंने लिखा कि बिहार विधान परिषद, जिसकी मैं नौकरी करता हूं वहां विधानों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं. इस तरह की टिप्पणी करने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाता है. अरुण नारायण को दिए गए निलंबन पत्र के पहले पैराग्राफ में उनके द्वारा कथित रूप से परिषद के पूर्व सभापति अरुण कुमार के नाम आए चेक की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है, जबकि इसी पत्र के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया कि परिषद में सहायक पद पर कार्यरत अरुण कुमार (अरुण नारायण) को प्रेम कुमार मणि की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में सरकार एवं सभापति के विरुद्ध असंवैधानिक टिप्पणी देने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. इन दोनों पत्रों को बिहार विधान परिषद के सभापति व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ताराकांत झा के आदेश से जारी किया गया है. फेसबुक की दुनिया में कवि मुसाफ़िर बैठा अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. अरुण नारायण ने अभी लगभग एक महीने पहले ही फेसबुक पर अकाउंट बनाया था. उपरोक्त जिन टिप्पणियों का ज़िक्र इन दोनों को निलंबित करते हुए किया गया है, वे फेसबुक पर ही की गई थीं. बड़ी पूंजी के सहारे चलने वाले अख़बारों और चैनलों पर लगाम लगाना तो सरकार के लिए बहुत मश्किल नहीं था, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मालिक बिंदास लेखकों पर नकेल कसना संभव नहीं हो रहा था. वह भी तब, जब मुसाफ़िर और अरुण जैसे लेखक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अपने योगदान के प्रति प्रतिबद्ध हों. इस बारे में प्रेम कुमार मणि आरोप लगाते हैं कि यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है. उनके इशारे पर ही मंत्री विजेंद्र यादव पूरे दिन इन कर्मचारियों के निलबंन की चिट्ठी निकलवाने के लिए परिषद में जमे रहे. मणि मानते हैं कि यह तानाशाही रवैया है. क्या सरकार यह चाहती है कि लोग अब लिखना–पढ़ना भी छोड़ दें.

अरुण नारायण

मुसाफ़िर बैठा

पुलिस की इस हैवानियत से दर्जनों ग्रामीण घायल हुए. पुलिस की मार से घायल दर्जनों महिलाओं को बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

भारत मधुमेह की राजधानी बन रहा है : श्रीवास्तव

भारत सन 2020 तक विश्व के मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है. यह बीमारी संक्रमित तो नहीं है, लेकिन इसकी गतिशीलता भी कम नहीं है. इस बीमारी से देश के युवा, वृद्धजन ही नहीं, अपितु किशोर भी ग्रसित होते जा रहे हैं, आख़िर क्यों? इस बीमारी के मुख्य कारकों और निदान पहलुओं पर सीवान के जाने माने चिकित्सक आर. पी. श्रीवास्तव से बातीचत हुई. प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:

आर पी श्रीवास्तव

● आख़िर यह बीमारी देश में तेज़ी से क्यों बढ़ रही है?

दरअसल, इस बीमारी के तीव्रगति से बढ़ने का मुख्य कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक खान-पान व रहन-सहन. सबसे अहम बात यह है कि लोग अपना वज़न नहीं बढ़ने दें. वज़न बढ़ने से भी परेशानी बढ़ती है. तैलीय खाना व जंक फूड से परहेज़ करें. कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहना ही बेहतर है. इससे बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वे प्राचीन और पुरातन जीवन शैली व खान-पान को सहज रूप से अपनाएं. अगर लोग शारीरिक श्रम व व्यायाम नहीं करेंगे और रिच डायट लेंगे तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है.

● किशोर इस बीमारी से क्यों ग्रसित हो रहे हैं?

आख़िर किशोरों और बच्चों को भी तो शारीरिक श्रम की ज़रूरत है, जिससे वे स्वस्थ्य रहें. लेकिन जब परिवार के खान-पान, रहन-सहन और जीवन शैली आधुनिक रूप में बदली है तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है. बच्चों के लिए खेलना-कूदना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए शहर ही नहीं, बल्कि गांवों में आज खेल के मैदान न के बराबर हैं. दूसरा यह कि वे विद्यालय से जब घर लौटते हैं तो भोजन के बाद स्कूल के होम टास्क के लिए बैठ जाते हैं और फिर समय मिला तो टेलीविज़न में घंटों बिताते हैं...

● इस रोग से बचाव कैसे करें?

● क्या अत्यधिक मीठा खाने से यह बीमारी होती है?

● भारत में इस बीमारी के निदान के लिए अभी कारगर दवाइयां कौन-कौन सी हैं?

धनंजय मिश्र

सैप जवानों की रेलवे में नौकरी

सुनील सौरभ

पुलवरिया व जमुआ घाट पर पुल बनेगा

वंशी चाचा की शहादत रंग लाई

कुणाल

एक नज़र

हिंदी बोलने और लिखने पर गर्व करें : डॉ. अनिल सुलभ

जिस बात पर शर्म आनी चाहिए उस पर लोग गौरव की अनुभूति करें, इसे दूर्भाग्यपूर्ण न कहें तो क्या कहें, जिस भाषा से दासता की करूण दास्तान याद आती है आज देश में वही महत्पूर्ण हो जाए और देश की राष्ट्रभाषा और लोक-भाषाएं शर्म का कारण लगें तो मैं समझाता हूं कि हमें डूब मरना चाहिए. हम विदेश की भाषा अंग्रेजी सीखने, बोलने और लिखने में गर्व करें और हमें हिंदी बोलना, लिखना और समझना नहीं आए और यदि आए भी तो हम इसमें बात करने की जगह अंग्रेजी बोलकर अपनी विद्धता प्रकट करने का यत्न करें तो इससे शर्मनाक और चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती. उपरोक्त बातें यहां राज्य पोषित उच्च विद्यालय में वैशाली ज़िला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वधान में आयोजित हिंदी पखवारा के अंतर्गत चलाए जा रहे हिंदी चेतना उन्नयन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपना व्याख्यान दे हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. सुलभ ने कहीं. इस अवसर पर पत्रकार मदन मोहन ठाकुर अधिवक्ता दिवाकर भारतीय, कवि विजय विनीत ज़िला हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री और पत्रकार शांति भूषण सिंह समेत कई विद्धानों और शिक्षकों ने अपने विचार व्यकत किए. सभा की अध्यक्षता सम्मेलन के ज़िला अध्यक्ष प्रो. श्याम नारायण चौधरी ने की. मंच का संचालन अशोक कुमार सिंह ने किया तथा धन्यवाद-ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य चंद्र भूषण कुमार ने पढ़ा.

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

अन्ना हज़ारे की मुहिम से जुड़ने और इसे आगे बढ़ाने के मद्देनज़र भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की पुस्तकों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिवम क्लासेज शिवाजी नगर कुर्जी, दीघा, पटना के सौजन्य से पालिपुत्रा पुराना थाना के निकट राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महंत हनुमान शरण कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बिमल नारायण आर्य ने किया. प्राचार्य डॉ. आर्य ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एवं शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष सदैव जारी रहना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब...

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 10.50 करोड़ रुपये का चेक सौंपा

पदयात्रा बक्सर से शुरू होगी

– चौथी दुनिया ब्यूरो

सम्राट ने पुल की सौग़ात दी

– गीता कुमार यादव

पुतला दहन असंवैधानिक : देवेंद्र मिश्र

– सुनील सौरभ

श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन दर्शन

सांसारिक जीवन को भागवत जीवन में रूपांतरित करना ही आध्यात्म है

बिहार में शुभागमन

प्रमोद कुमार सिंह

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
नामांकन सूचना 2011

Prog./Course	Session	Prospectus	Eligibility
1) बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) (अवधि : 2 वर्ष)	2011-13	Rs. 800/- Rs. 500/-(SC/ST)	[illegible]
2) M.A. in Education (अवधि : 2 वर्ष)	2011-13	Rs. 500/- Rs. 250/-(SC/ST)	[illegible]
3.) M.LIS (अवधि : 1 वर्ष)	2011-12		[illegible]

डॉ. मो. इसराईल ख़ाँ
निदेशक

पुलिस ने फिर हैवानियत दिखाई

कुमार प्रशांत